एशियाई राजनीति में संतुलन साधने की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा केवल दो देशों की यात्रा भर नहीं है, बल्कि एशिया तथा वैश्विक राजनीति की दिशा और संतुलन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव वॉशिंगटन तक भी पहुँचेंगे। सबसे पहले, 29-30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान जाएंगे, जहाँ वह प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। यह मोदी का जापान का आठवां दौरा और इशिबा के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। हम आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, जिसमें रक्षा-सुरक्षा, व्यापार, तकनीकी सहयोग और जन-से-जन संपर्क प्रमुख आधार हैं। इस यात्रा के माध्यम से मोदी यह संदेश देंगे कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक, पारदर्शी और नियम-आधारित व्यवस्था का प्रबल समर्थक है। जापान के लिए यह संकेत भी स्पष्ट होगा कि भारत उसके साथ गहरी साझेदारी चाहता है और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच वह अकेला नहीं है। इसके बाद, 31 अगस्त- 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। एससीओ भारत की एशिया नीति का अहम हिस्सा है, जहाँ सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होता है। इस मंच पर मोदी की मौजूदगी चीन के लिए यह संदेश है कि भारत टकराव नहीं बल्कि संवाद और बहुपक्षीय सहयोग का पक्षधर है। साथ ही यह भी स्पष्ट संकेत है कि भारत जापान जैसे देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाकर बीजिंग पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाए रखने की क्षमता रखता है।कूटनीति में यात्रा का क्रम भी संदेश देता है। मोदी ने पहले जापान और फिर चीन का दौरा तय कर यह जताया है कि भारत एशिया में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चलता है। बीजिंग को संकेत दिया गया है कि भारत उसकी शर्तों पर नहीं झुकेगा और जापान को आश्वस्त किया गया है कि चीन के साथ संवाद उसकी कीमत पर नहीं होगा। इसके अलावा, जापान के साथ रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का संतुलन साधने में मदद कर सकता है, वहीं जापान निवेश और तकनीकी सहयोग का भी बड़ा स्रोत है। दूसरी ओर, चीन के साथ सीधे संवाद बनाए रखने से भारत को सीमा विवाद और एससीओ जैसे मंचों पर अपनी स्थिति मजबूती से रखने का अवसर मिलता है। इस क्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का हालिया बयान उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि परिस्थितियाँ मांगने पर चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर लगी पाबंदियों की समीक्षा की जा सकती है। यह संकेत ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में तनाव देखा जा रहा है और चीन के साथ तालमेल की संभावनाएँ खुल रही हैं। अमेरिकी दृष्टि से यह यात्रा बेहद अहम है। वॉशिंगटन इसे गहराई से देखेगा, क्योंकि यह उसकी इंडो-पैसिफिक रणनीति, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और जापान की भूमिका- तीनों से जुड़ी है। भारत यहाँ अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। जापान में जाकर भारत अपने स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्प को मजबूत करता है, जो अमेरिका की इंडो-पैसिफिक दृष्टि से मेल खाता है। वहीं चीन जाकर मोदी यह दिखाएंगे कि भारत अपने पड़ोस और बहुपक्षीय मंचों की अनदेखी नहीं करेगा। बहरहाल, मोदी की जापान और चीन यात्रा अमेरिका को यह याद दिलाती है कि भारत उसका नेचुरल पार्टनर तो है, लेकिन जूनियर पार्टनर नहीं। भारत सहयोग का पक्षधर है, पर अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करता। यह दौरा साफ तौर पर दिखाता है कि भारत किसी एक ध्रुव का हिस्सा बनने के बजाय संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देता है।

अब भाजपा का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल

अशोक भाटिया

लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार हैं

दिल्ली चुनाव में मिली जीत ने भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। दिल्ली में करीब 28 साल बाद भाजपा की सरकार बनी इस जीत के बाद भाजपा बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में लग गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के मुताबिक बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार, लोकलुभावन योजनाओं, दान वितरण और व्यक्तिवाद के आरोप ही वे तीन मुख्य तत्व हैं जो दिल्ली की तरह बंगाल की राजनीति में समान हैं।

बंगाल में अपनी जीत को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हालिया तीन बार चक्कर लगा चुके है व करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का ऐलान कर चुके है . ताजा दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार को दोबारा निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा है टीएमसी ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। पीएम ने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल में चीख-पुकार मची है, लोग कह रहे हैं कि अब नहीं चाहिए टीएमसी की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की तुलना निर्मम सरकार से की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ।वो यहां की टीएमसी सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आयुष्मान योजना से लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी की सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बंगाल में बंद रहे टी-गार्डन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार को आदिवासियों से कोई लगाव नहीं है। टीएमसी आदिवासी समाज को वंचित रखना चाहती है। पार्टी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति का विरोध किया। जनमन योजना भी लागू नहीं होने दी जा रही है।टीएमसी के नेताओं ने पाप किया है। बंगाल में कोर्ट को बार-बार दखल देना पड़ता है। बंगाल की जनता को टीएमसी पर नहीं, कोर्ट पर भरोसा है। सत्ताधारी दल के नेता ही लोगों के घरों को जलाते हैं।

इधर अमित शाह भी बंगाल का किला फतह करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे है . उनकी पहचान जपा के 'चाणक्य' के रूप में होती है। पार्टी के इस कुशल रणनीतिकार ने अपने लिए पश्चिम बंगाल को बड़े लक्ष्य के रूप में तय किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शाह ने यह लक्ष्य क्यों रखा है। जानते हैं इसके बारे में।अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव और आरजी कर की घटना के बाद शाह हाल ही में पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। शाह ने वहां पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरूआत की। इसके साथ ही शाह ने घोषणा की कि भाजपा का 'अगला बड़ा लक्ष्य' 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सरकार बनाना है।

गौरतलब है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बंगाल से 30 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसे 2019 की तुलना में छह कम यानी 12 सीट पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट हैं। राज्य में संदेशखाली का मुद्दा काफी गरम रहा था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने का पुरजोर प्रयास किया था। पार्टी ने संदेशखाली पीड़ित में से एक रेखा पात्रा बशीरहाट लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर एक संदेश देने की कोशिश भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा तक कहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल जाककर संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिले थे। हालांकि,भाजपा महिला सुरक्षा जैसे मजबूत मुद्दे को भुनाने में असफल रही थी। इससे पार्टी को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में शाह में संदेशखाली मुद्दे को पार्टी की तरफ से नहीं भुना पाने की टीस तो जरूर रही होगी। ऐसे में शाह नहीं चाहते हैं कि वह अगली बार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से पिछड़ें।

अमित शाह ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में दो तिहाई बहुमत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शाह ने पार्टी सदस्यों से राज्य में अपने प्रभाव को कम नहीं आंकने का आग्रह किया है। शाह एक कुशल रणनीतिकार की तरफ से कार्यकताओं का मनोबल बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।भाजपा ने राज्य में सदस्यता अभियान के दौरान पिछली बार 88 लाख से अधिक सदस्य बनाए थे। मौजूदा समय में पार्टी में अधिक सांसद और विधायक हैं। ऐसे में पार्टी का लक्ष्य एक करोड़ सदस्यों को पार करना है। पार्टी कार्यकताओं को यह विश्वास दिला रही है कि वे चुनौती को स्वीकार करते हुए पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं।

इस समय मजबूत संगठन, नए चेहरों को लाना भी एक चुनौती है क्योंकि भाजपा का राज्य में प्रदर्शन टुकड़ो-टुकड़ों में रहता है। पार्टी एक साथ पूरे राज्य में मजबूत नजर नहीं आती है। नार्थ परगना, साउथ परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली में पार्टी का संगठन तुलनात्मक रूप से कमजोर है। इस क्षेत्र में 16 लोकसभा सीटों आती हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 16 में से महज 3 सीटें ही जीती थी। इस बार यह प्रदर्शन और भी कमजोर रहा। राज्य में दिलीप घोष, सुवेंदु अधिकारी, तापस रॉय जैसे गिने-चुने ही चेहरे नजर आते हैं। ऐसे में शाह की नजर राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत चेहरों को सामने करने की होगी। इस तरह शाह के लिए पश्चिम बंगाल में अगले दो साल रणनीतिक रूप से काफी अहम है। शाह के सामने ममता के मजबूत किले को ध्वस्त करने की चुनौती है।

इस बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में आवास योजना के तहत एक लाख 20 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इस पैसे से घर नहीं खरीदा जा सकता। भाजपा सत्ता में आई तो आवास योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, जिन लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें सीधे तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो हम महिलाओं को मौजूदा सरकार की लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत मिलने वाली राशि से अधिक देंगे।

इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत फरवरी में 10 दिनों के लिए बंगाल दौरे पर थे। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान भागवत ने भाजपा की जीत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। भागवत के बंगाल से जाने के बाद संघ ने 1 और 2 मार्च को हावड़ा में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की थी। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा 2026 विधानसभा चुनाव था। बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा एक करोड़ सदस्यों को जोड़ने के अपने लक्ष्य में कहां तक पहुंची है और अपना आधार मजबूत कैसे कर सकती है, इसकी रणनीतियों पर चर्चा की गई। संघ ने भाजपा को बंगाल में हिंदू एजेंडा फैलाने का भी निर्देश दिया।बंगाल में हिंदुओं को अपनी विनाशशील से जोड़ने की संघ की कवायद नई नहीं है। वह बंगाल में लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो साल में संघ ने बंगाल में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। 2023 में बंगाल में संघ की कुल 3,560 शाखाएं थीं, जो 2025 में 4,540 हो गई हैं।एक्सपर्ट कहते हैं कि भाजपा ने अगर टी एम सी के वोट बैंक में 4% की सेंध लगा दी, तो यह 2026 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

निचले स्तर पर राजनीतिक व्यवहार, राहुल गांधी के झूठे दावे बेनकाब

अवधेश कुमार

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगा रही है। वे उसके अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और निचले व्यवहार पर उतरकर उनके परिवार तक को निशाना बना रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शर्मनाक है।

राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चोर कहते हुए निशाना बना रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें... एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में हमारी सरकार होगी। फिर हम आप तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं के सोशल मीडिया हैंडल देख आप सन्न रह जाएंगे। राजनीति इतने नीचे स्तर पर गिर जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी की राजनीति देश में डरावने दृश्य प्रस्तुत कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यह व्यवहार पहली बार नहीं है। पिछले लगभग सात वर्षों से राहुल गांधी की राजनीति का एक स्थापित पैटर्न बन गया है।

राहुल गांधी पहले भी कई संस्थाओं को धमकी दे चुके हैं। वे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसा कह चुके हैं कि मोदी अब सड़कों पर निकलेगा तो लोग डंडों से पीटेंगे? उनके नेतृत्व में अब कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें मयार्दा, पद की गरिमा, भाषा की शालीनता, व्यवहार का संतुलन तथा सच और झूठ के भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी किसी को निशाना बनाते हैं, उनकी पूरी पार्टी उस व्यक्ति, अधिकारी या उनके खानदान को ढूंढ़ कर चरित्र हनन और बदनाम करने का अभियान चलने लगती है। डिजिटल मीडिया कई बार बहुत विषाक्त हो जाता है। इसकी अनदेखी न की जाए कि आपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिसरी को डिजिटल मीडिया पर किस तरह निशाना बनाया गया।

निम्न राजनीति पहले सामने वाले के विरुद्ध संदेह पैदा करने के लिए कथित तथ्य गढ़ती है, फिर नारे एवं मुहावरे बनाती है। अब वह संस्थाओं को भी निशाना बना रही है। इन दिनों संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग इस राजनीति के निशाने पर है। आज पूरे देश के सामने प्रश्न है कि इस तरह के राजनीतिक व्यवहार का प्रतिकार कैसे हो?

राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त सहित पूरे चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के पक्ष में कोई ठोस तथ्य नहीं दे रहे हैं। अब तो वे सार्वजनिक रूप से गलत साबित हो रहे हैं। गत दिनों बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा के दौरान रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के एक गांव की रंजू देवी उनके सामने यह कहती देखी गईं कि उनका और परिवार के सभी छह लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। राहुल ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बना दिया। बाद में उन्हीं रंजू देवी ने कहा कि मतदाता सूची में उनके परिवार के सभी लोगों के नाम हैं। उनके अनुसार वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल आ रहे हैं, उनके सामने बता देना कि हमारा नाम मतदाता सूची से कट गया है। उन्होंने माना कि वार्ड सचिव ने जैसा कहा, वैसा राहुल के सामने बोल दिया।

यह एक प्रसंग राहुल और वोट चोरी के आरोप लगाने वालों के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। राहुल के महाराष्ट्र चुनाव संबंधी आरोप भी गलत साबित हो चुके हैं। बंबई उच्च न्यायालय संबंधित याचिका खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के रामटेक और देवली विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा में क्रमशः 38.45 प्रतिशत तथा 36.82 प्रतिशत मतदाताओं की कमी का आंकड़ा भी गलत साबित हो गया। इसे ह्रासामनेह्न लाने वाले सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक ने न केवल संबंधित पोस्ट को हटाया, बल्कि गलत उत्तर देने के लिए माफी भी मांगी। इसके बावजूद वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के तेवर और भाषा देखकर लगता है कि उनका मुद्दा चुनाव आयोग या सत्ता प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि कुछ और है।

लगता है वे सब कुछ पहले से निर्धारित किसी योजना के अनुसार कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि किसी संवैधानिक संस्था पर नेताओं द्वारा राजनीतिक आरोप लगाने के पीछे निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे कि संस्थानों पर दबाव बढ़ाना, उन्हें कानूनी मामले में फंसाना, ताकि लोगों का मुख्य काम से ध्यान हटे। देश में संस्थाओं के प्रति घोर अविश्वास और विरोध का वातावरण बनाने और उसके खिलाफ आक्रामक तरीके से शोर मचाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या राहुल और उनके सहयोगी देश में उथल-पुथल और अशांति की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लक्ष्य साधना चाहते हैं?

आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं, इसे जनता खुद समझे। शायद वह समझ भी रही है। इसकी आशंका है कि अपने किसी खतरनाक उद्देश्य के लिए राहुल के नेतृत्व में आगे भी देश की अन्य संस्थाओं की प्रतिष्ठा समाप्त करने के लिए ऐसे ही निम्नतम स्तर के अभियान चलें, ताकि सामने वाला विवश होकर या आवेश में कार्रवाई करे और देश का वातावरण बिगड़े। देश की शांति, स्थिरता, समृद्धि और विश्व स्तर पर उसकी साख की चिंता करने वाले हर व्यक्ति को ऐसी राजनीति से चिंतित होना चाहिए।

राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त सहित पूरे चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के पक्ष में कोई ठोस तथ्य नहीं दे रहे हैं। अब तो वे सार्वजनिक रूप से गलत साबित हो रहे हैं। गत दिनों बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा के दौरान रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के एक गांव की रंजू देवी उनके सामने यह कहती देखी गईं कि उनका और परिवार के सभी छह लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। राहुल ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बना दिया। बाद में उन्हीं रंजू देवी ने कहा कि मतदाता सूची में उनके परिवार के सभी लोगों के नाम हैं। उनके अनुसार वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल आ रहे हैं, उनके सामने बता देना कि हमारा नाम मतदाता सूची से कट गया है। उन्होंने माना कि वार्ड सचिव ने जैसा कहा, वैसा राहुल के सामने बोल दिया। यह एक प्रसंग राहुल और वोट चोरी के आरोप लगाने वालों के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। राहुल के महाराष्ट्र चुनाव संबंधी आरोप भी गलत साबित हो चुके हैं। बंबई उच्च न्यायालय संबंधित याचिका खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के रामटेक और देवली विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा में क्रमशः 38.45 प्रतिशत तथा 36.82 प्रतिशत मतदाताओं की कमी का आंकड़ा भी गलत साबित हो गया। इसे ह्रासामनेह्न लाने वाले सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक ने न केवल संबंधित पोस्ट को हटाया, बल्कि गलत उत्तर देने के लिए माफी भी मांगी।

बहस

चीन का कहना है कि ताइवान को लेकर विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण से उसे हैरत है, और यह 'तथ्यों से परे है। जिससे यह दावा गहरा जाता है, जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा करार दिया गया था। इसका विदेश मंत्रालय ने प्रतिवाद भी किया था। विदेश मंत्रालय/सरकार से ताजा बयान पर प्रतिक्रिया का इंतजार है।

सुहासिनी हैदर, पत्रकार@suhasinih

विचार

जीएम फसल और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित

भारत डोगरा

चावल की जीन एडिटिड फसलों के संदर्भ में इस समय भारत में तीखी बहस हो रही है। विश्व स्तर पर चल रहे अधिक व्यापक विमर्श के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने बताया है कि जीन एडिटिड फसलों से भी काफी हद तक वही क्षति होती है, जो जीएम फसलों या जेनेटिकली मोडीफाइड (जीएम) फसलों या जीन संवर्धित फसलों से होती है। जीन एडिटिड फसलों के विरोध में विश्व स्तर पर बताया गया है कि चूंकि जीएम फसलों के विरुद्ध आंदोलन जोर पकड़ते जा रहे थे और इनकी क्षतियां अधिक सामने आ रही थीं, अतः गुपचुप जीन एडिटिड तकनीक का प्रसार किया गया।

आज भारत में भी यही प्रवृत्ति देखी जा रही है कि जिन्होंने जीएम फसलों का विरोध किया वे लगभग उन्हीं कारणों से जीन एडिटिड फसलों का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पेटेंट आधारित मोटे मुनाफे की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सोच यहां भी पीछे से प्रयासरत है, जबकि बाहरी तौर पर चाहे किसी अन्य को सामने कर दिया जाए। चावल के मामले में तो यह और भी खतरनाक है, क्योंकि यह हमारा प्रमुख खाद्य है और इसके लिए जैव-विविधता यानी तरह-तरह की किस्मों का खेत में बने रहना बहुत जरूरी है जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी किस्म को ही दूर-दूर तक फैलाती हैं। इस स्थिति में नये सिरे से जीएम फसलों की हानियों को रेखांकित करना जरूरी है। जीएम फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों और पौधों में फैल सकता है। इस विचार को इंडिपेंडेंट साइंस पैनल (स्वतंत्र विज्ञान मंच) ने बहुत सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया है।

इस पैनल में एकत्र हुए अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जीएम फसलों पर महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है-जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं और ये फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रही हैं। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अतः जीएम फसलों और गैर-जीएम फसलों का सह-अस्तित्व नहीं हो सकता। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जीएम फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे इन फसलों की सेफ्टी

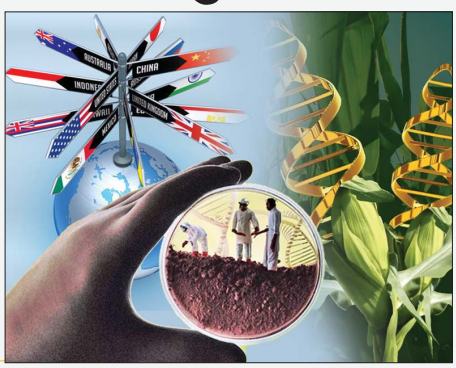

या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसे फिर ठीक नहीं किया जा सकता। जीएम फसलों को अब दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए।

2009-10 में भारत में बीटी बैंगन के संदर्भ में जीएम के विवाद ने जोर पकड़ा तो विश्व के 17 विख्यात वैज्ञानिकों ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर इस बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई। पत्र में कहा गया कि जीएम प्रक्रिया से गुजरने वाले पौधे का जैव-रसायन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है, जिससे उसमें नये विषैले या एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों का प्रवेश हो सकता है, और उसके पोषण गुण कम हो सकते हैं या बदल सकते हैं। जीव-जंतुओं को जीएम खाद्य खिलाने पर आधारित अनेक अध्ययनों से जीएम खाद्य के गुर्दे (किडनी), यकृत (लिवर), पेट और निकट के अंगों (गट), रक्त कोशिका, रक्त जैव रसायन और प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी सिस्टम) पर नकारात्मक स्वास्थ्य असर सामने आ चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अधिकांश महत्त्वपूर्ण उत्पादों के पेटेंट बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास हैं और वे अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इस तकनीक का जैसा उपयोग करती हैं, उससे इस तकनीक के खतरे और बढ़ जाते हैं। कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टैक्नोलजी मात्र लगभग छह-सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (और उनकी सहयोगी या उप-कंपनियों) के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में है। इनका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विश्व कृषि एवं खाद्य व्यवस्था पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करना है जैसा विश्व इतिहास में आज तक संभव नहीं हुआ है।

हमारे देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रो. पुष्प भार्गव, वे सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलीक्युलर बॉयलाजी, हैदराबाद के संस्थापक निदेशक रहे और नेशनल नॉलेज कमीशन के उपाध्यक्ष रहे, उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुचर्चित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया था, ने जीएम फसलों का स्पष्ट और तथ्य आधारित विरोध किया था, और वह भी बहुत प्रखरता से।

बिजनेसलाइन (नवम्बर 5, 2015) में 'द केस फॉर बैनिंग जीएम क्रॉप्स' या 'जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाना क्यों जरूरी है' शीर्षक से उन्होंने महत्त्वपूर्ण लेख लिखा। इसमें लिखा, 'आज बहुत से और संदेह से परे प्रमाण हैं कि जीएम फसलें मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण और जैव-विविधता के लिए हानिकारक हैं। (इनमें) प्रायः प्रयोग होने वाला बीटी जीन कपास या बैंगन के पौधों में प्रवेश कर उनकी संवृद्धि और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जीएम खाद्यों के बारे में यह भी सिद्ध हुआ है कि इनसे चूहों में कैंसर होता है।' एक अन्य लेख (हिंदुस्तान टाइम्स, 7 अगस्त, 2014) में प्रो. भार्गव ने लिखा, 'लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों ने जीएम फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव-जंतुओं और पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है, और ये सभी प्रकाशन ऐसे वैज्ञानिकों के हैं जिनकी ईमानदारी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा है। दूसरी ओर जीएम फसलों का समर्थन करने वाले लगभग सभी पेपर या प्रकाशन उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने कान्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्वीकार किया है, या जिनकी विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठ सकते हैं।'

प्रायः जीएम फसलों के समर्थक कहते हैं कि वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन जीएम फसलों को मिला है पर प्रो. भार्गव ने इस विषय पर समस्त अनुसंधान का आकलन कर स्पष्ट बता दिया कि अधिकतम निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों का विरोध ही किया है। यह भी बताया कि जिन वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है, उनमें से अनेक किसी न किसी स्तर पर जीएम बीज बेचने वाली कंपनियों या इस तरह के निहित स्वार्थों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, या प्रभावित रहे हैं।

आज भारत में भी यही प्रवृत्ति देखी जा रही है कि जिन्होंने जीएम फसलों का विरोध किया वे लगभग उन्हीं कारणों से जीन एडिटिड फसलों का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पेटेंट आधारित मोटे मुनाफे की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सोच यहां भी पीछे से प्रयासरत है, जबकि बाहरी तौर पर चाहे किसी अन्य को सामने कर दिया जाए। चावल के मामले में तो यह और भी खतरनाक है, क्योंकि यह हमारा प्रमुख खाद्य है और इसके लिए जैव-विविधता यानी तरह-तरह की किस्मों का खेत में बने रहना बहुत जरूरी है जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी किस्म को ही दूर-दूर तक फैलाती हैं। इस स्थिति में नये सिरे से जीएम फसलों की हानियों को रेखांकित करना जरूरी है। जीएम फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं

'जेन जी' के शौक और मीडिया

मीडिया

सुधीश पचौरी

यह 'जेन जी' का युवक है जिसका चित्त 'अस्थिर' है, हमेशा 'अधीर' रहता है, 'आत्मविश्वास रहित' है, इसलिए हमेशा डरा रहता है, इसलिए 'डराता' रहता है, और जरा सी बात पर 'हिंसा' पर उतर आता है। इसी 'जेन जी' का 'शौक' है 'ऑनलाइन 'गेमिंग', जिसमें कभी जीतता है, कभी हारता है और अधिकाधिक जीतने की हवस में कभी-कभी...

भरी सड़क पर दो युवतियां पहले बहस करती दिखती हैं, फिर गुत्थम-गुत्था हो जाती हैं। तमाशबीन वीडियो बनाने लगते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिसे खबर चैनल दिखाने लगते हैं। इसे देखते ही हमारी 'नैतिकता' फैसले देने लगती है कि कैसे दिन हैं कि लड़कियां तक सरेआम लड़ती हैं। इससे भी अधिक खूंखार खबर गुजरात के एक स्कूल से आती है, जहां के बीस-पच्चीस लड़कों का 'व्हाट्सएप ग्रुप' सक्रिय है। एक दिन 'ग्रुप' का लड़का दूसरे की चाकू मार कर हत्या कर देता है। फिर 'चैट' में कहता है 'कर दिया...'। पुलिस गिरफ्तारियां करती है। एक चैनल बहस कराता है, जिसमें उसकी राजनीतिक परतें खोली जाने लगती हैं...।

हमारे जैसों की 'नैतिकता' फिर कुलबुलाती है। हम फिर रोते हैं कि युवकों में हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है कि जरा सी बात पर दूसरे की जान ले बैठते हैं...अब जेल में सड़ते रहो बेटे...रोते रहें माता-पिता...और हिंसा की आड़ में नेता सेंकते रहें अपनी राजनीतिक रोटियां...रोज बढ़ती ऐसी हिंसक घटनाएं विचलित करती हैं, लेकिन इनका 'उपचार' कोई नहीं सोचता। ऐसी हर खबर हमारे 'अवचेतन' में जगह बनाते हुए हमें भी 'हिंसा' का आदी बनाती रहती है, और हम मन ही मन मीडिया के दिए उस मुहावरे को दुहराने लगते हैं, जो कहता है कि 'यही है न्यू नॉर्मल', 'जेनरेशन जी', 'जेड पीढ़ी' का 'नया नॉर्मल' यानी 'नया आदर्श' जहां सिर्फ 'विवाद' हैं, लेकिन 'संवाद' नहीं है। उन्हें अपने अपने एक 'अनार्जित अहंकार' में और तज्जनित 'बेहद उत्तेजित क्षण' में जीना है, माता-पिता को रोते-बिलखते, मुकदमा लड़ते, 'बर्बाद' होते छोड़ जाना है।

यह 'जेन जी' का युवक है जिसका चित्त 'अस्थिर' है, हमेशा 'अधीर' रहता है, 'आत्मविश्वास रहित' है, इसलिए हमेशा डरा रहता है, इसलिए 'डराता' रहता है, और जरा सी बात पर 'हिंसा' पर उतर आता है। इसी 'जेन जी' का एक 'शौक' है ऑनलाइन 'गेमिंग', जिसमें कभी जीतता है, कभी हारता है और अधिकाधिक जीतने की हवस में कभी-कभी सब कुछ हार जाता है, फिर निराशा में डूब कर 'आत्महत्या' तक कर लेता है...'ऑनलाइन गेमिंग' के विज्ञापन ललचाते रहते हैं कि तू 'ऑनलाइन' 'गेम' खेल, उसके लिए ये-ये 'गेमिंग ऐप' उपयोग में ला और 'करोड़पति' बन जा, कुछ पैसे से दांव लगा...वह कभी जीतता है, कभी हारता है। यह 'हार-जीत' उसे ललचाती रहती है। वह खेलता रहता है, और एक दिन जब करोड़पति बनने के आसपास होता है तो अचानक सब कुछ हार जाता है, और घोर 'अवसाद' में डूब जाता है जिसका अंत अक्सर उसकी 'आत्महत्या' में होता है...।

ऐसे 'गेमिंग ऐपों' को बड़े 'सेलीब्रिटीज', बड़े 'खिलाड़ी' विज्ञापित करते रहते हैं। वे ऐसे 'गेम' खेलते दिखते हैं और चंचलमना 'जेन जी' को ललचाते रहते हैं कि ऑनलाइन 'गेम' खेलो, दांव लगाओ और पल में अमीर बन जाओ। 'गेमिंग ऐप' भारत में शुरू से ही 'पॉपुलर' रहे हैं। एक बड़ी युवा आबादी ऑनलाइन 'गेम' खेलती रहती है और कुछ बड़ी 'ऑनलाइन' गेमिंग कंपनियां मालामाल होती रहती हैं। यहां जीतता कोई-कोई है, लेकिन हारते ज्यादा हैं, और बहुत सा पैसा इन कंपनियों के खजाने में जाता रहता है।

'गेमिंग' ऑनलाइन कराने वाली कई कंपनियां ग्लोबल हैं तो कई देशज। गेमिंग बाजार पर इन्हीं का नियंत्रण है। पिछले दिनों, जैसे ही सरकार ने 'गेमिंग' के 'जोखिम' देखते हुए ऑनलाइन 'गेमिंग' पर अंकुश लगाने वाला कानून बनाया वैसे ही गेमिंग कंपनियों के अधिकारी 'टोल बना कर' शिकायत करते दिखे कि सरकार हमारे पेट पर क्यों लात मार रही है? हम जबर्दस्ती 'गेम' नहीं खिलाते। लोग खुद खेलते हैं...यहीं आकर 'गेमिंग' शब्द का मतलब खुलता है: 'गेमिंग' कहने से प्रकटतः तो ऐसा लगता है कि जैसे 'गेमिंग' सिर्फ 'ऑनलाइन खेल' है जिसमें 'बौद्धिक क्षमता' और 'कुशलता' की 'परीक्षा' होती है लेकिन ऐसा है नहीं। यहां 'गेमिंग' का मतलब है 'पैसे का जुआ' जिसे 'गेमिंग' का नाम देकर 'खेलकूद' की तरह मीडिया में 'विज्ञापित' किया जाता है जबकि है यह शुद्ध 'जुआ'! हम-आप रोज बहुत से विज्ञापन चैनलों में देखते हैं जो कहते हैं कि ये ऐप लो, ये 'गेम' खेलो और 'अमीर' हो जाओ फिर 'सुपरफास्ट स्पीड' में बोला जाता है कि इसमें जोखिम हो सकता है ध्यान से खेलें...'गेमिंग' के विज्ञापन, अधिकांश 'जेन जी' को 'ललाच' की 'कैद' में बंद किए रहते हैं। लोग बर्बाद होते रहते हैं। मीडिया विज्ञापन देकर अपनी कमाई करते रहते हैं, और 'गेमिंग कंपनियां' अकूत मुनाफे कमाती रहती हैं। कोई मरे या जिए, किसी को क्या?

क्या गुल खिलाएगा संवाद

भारत-चीन

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

भारत-चीन के बीच सीमा विवाद 3,488 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा है। कई दौर की वार्ताओं और सैन्य समझौतों के बावजूद समाधान संभव नहीं हो पाया है। हाल में हुई वार्ताओं में सहमति बनी है कि सीमा विवाद को अलग रखते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह 'टू-ट्रैक मूवमेंट' (दोहरी रणनीति) है

भारत और चीन, एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां, न केवल भौगोलिक रूप से एक-दूसरे की पड़ोसी हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इतिहास गवाह है कि इन दोनों देशों के रिश्ते समय-समय पर उतार-चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। कभी रिश्ते मित्रता और सहयोग के स्वरूप में दिखे तो कभी सीमा विवाद और तनाव ने इन्हें गहरी खाई में धकेल दिया। हाल के वर्षों में जहां लद्दाख में झड़पों और सीमा पर तनाव ने दोनों के संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया था, वहीं अब पुनः संवाद और सहयोग की संभावनाएं उभरती दिखाई दे रही हैं।

वांग यी की भारत यात्रा, उच्चस्तरीय वार्ताओं की पुनः शुरुआत और कूटनीतिक प्रयासों के कारण प्रतीत हो रहा है कि रिश्तों में नई गरमाहट लौट रही है। परंतु इस गरमाहट के साथ-साथ सतर्कता और विवेक भी उतना ही आवश्यक है। भारत-चीन संबंधों की नींव 1950 के दशक में 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे के साथ रखी गई थी। परंतु 1962 का युद्ध दोनों देशों के रिश्तों में निर्णायक मोड़ लेकर आया। सीमा विवाद, विशेषकर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर असहमति, आज भी दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद का कारण है। उसके बाद से समय-समय पर रिश्तों में उतार-चढ़ाव आते रहे। 2017 का डोकलाम संकट और 2020 का गलवान संघर्ष इस अविश्वास की पराकाष्ठा थे। दोनों घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा विवाद अब भी संबंधों का सबसे बड़ा अवरोधक है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 3,488 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा है। कई दौर की वार्ताओं और सैन्य समझौतों के बावजूद समाधान अब तक संभव नहीं हो पाया है। हाल ही में हुई वार्ताओं में सहमति बनी है कि सीमा विवाद को अलग रखते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह 'टू-ट्रैक मूवमेंट' (दोहरी रणनीति) है, जिसमें सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंध समानांतर रूप से चलेंगे। भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध बेहद जटिल हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। लेकिन इसमें असंतुलन स्पष्ट है। भारत जहां चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, रसायन और दवाओं का कच्चा माल आयात करता है, वहीं उसका निर्यात अपेक्षाकृत बहुत कम है। इस कारण व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि चीन का प्रभुत्व व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भारत के बाजार पर हावी होकर आत्मनिर्भरता और 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं को चुनौती देता है। हालांकि, भारतीय आईटी, फार्मा और कृषि क्षेत्र में चीन की बढ़ती मांग भारत के लिए अवसर भी प्रस्तुत करती है। सवाल है कि भारत इस असंतुलन को कैसे कम करेगा और आर्थिक संबंधों को संतुलित एवं परस्पर लाभकारी कैसे बनाएगा।

भारत-चीन संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू सुरक्षा और सामरिक हितों से जुड़ा हुआ है। चीन पाकिस्तान के साथ मिल कर 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के तहत हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की घेराबंदी कर रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौती है क्योंकि इसका मार्ग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन की नौसैनिक गतिविधियां भी हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा करती हैं। यही कारण है कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल कर क्वाड समूह को मजबूत कर रहा है। भारत-चीन संबंध द्विपक्षीय दायरे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन में भी गहराई से जुड़े हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई मुलाकातें, चाहे 2019 का महाबलीपुरम शिखर सम्मेलन हो या हाल में वांग यी की यात्रा, दर्शाती हैं कि संवाद ही आगे का रास्ता है।

दोनों देशों ने तय किया है कि सीमा प्रबंधन के तंत्र को मजबूत किया जाए और सैनिक तनाव को कम करने के लिए नियमित वार्ता और हॉटलाइन का इस्तेमाल किया जाए। पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाए। 'पीपुल-टू-पीपुल कॉन्टैक्ट' दोनों के बीच विश्वास बहाली का प्रभावी साधन हो सकता है।

शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार

ऑनलाइन गेमिंग

अली खान

केंद्रीय सरकार युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से बाहर निकालने और उन्हें सही दिशा दिखाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 लेकर आई है। इस बिल के विधिवत कानून बनने के बाद पैसों से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग एप्लिकेशन पर सख्त रोक लगा दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य को बचाने और समाज में फैल रही बुराइयों पर नियंत्रण लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह कदम जितना सराहनीय है, उतना ही सार्थक भी है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का बड़ा हिस्सा मोबाइल गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गिरफ्त में फंसता जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, इस बिल में साफ प्रावधान किए गए हैं कि ऑनलाइन गेम खेलने वाले सामान्य खिलाड़ियों को कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो इस तरह के एप संचालित करते हैं। ऐसे संचालकों को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की कैद भुगतनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, जो बड़े सितारे और सेलिब्रिटी इन गेमिंग एप्स का विज्ञापन करके युवाओं को बरगलाते हैं, उन पर भी दो साल तक की कैद और पचास लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार, सरकार ने महज संचालकों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रचार-प्रसार करने वालों पर भी शिकंजा कसने का साफ संदेश दिया है। नये बिल के तहत यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सट्टेबाजी और दांव लगाने से जुड़े किसी भी प्रकार के गेम का कारोबार अब मंजूर नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे ऐसे सभी प्लेटफॉर्म, जो वास्तविक पैसे के लालच में बच्चों और युवाओं को आकर्षित करते हैं, अब पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।

एक अनुमान के मुताबिक, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2016 में लगभग 54.30 करोड़ डॉलर का था लेकिन महज छह वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2022 तक यह बढ़ कर लगभग 2.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी रफ्तार से विस्तार होता रहा तो 2027 तक यह आंकड़ा 8.6 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। यह बढ़ोतरी महज आर्थिक पहलू नहीं दिखाती, बल्कि इस बात की भी पुष्टि करती है कि भारत में लोग किस तेजी से इस लत का शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल गेम खेलने वाला देश बन चुका है। वर्ष 2021 में जहां तकरीबन 45 करोड़ भारतीय ऑनलाइन गेमर्स थे, वहीं महज एक साल के भीतर यह संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई। और तो और, एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के अंत तक यह गिनती 70 करोड़ के करीब पहुंच सकती है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा वे खिलाड़ी हैं, जो वास्तविक पैसे लगा कर गेम खेलते है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान ही भारत में लगभग 12 करोड़ मोबाइल यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के लिए वास्तविक धन का भुगतान किया। यह रकम गैंबलिंग और बेटिंग के अलावा गेम कॉइन्स, यूसी, गेम स्किन, गेम रैंक तथा अन्य वर्चुअल सामान खरीदने में खर्च की गई थी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि देश में जुआ और सट्टेबाजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न केवल युवाओं बल्कि नाबालिग बच्चों तक को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जो इनकी बर्बादी का मुख्य कारण बन रहा है।

https://t.me/RajPaperPaid1

दागी जेल से नहीं चला पाएंगे सरकार

मुद्दा

प्रमोद भार्गव

अरसे से चुनाव सुधार के लिए ऐसी विसंगतियां दूर करने की मांग उठती रही है, जिनके चलते दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों के आरोपियों को चुनाव लड़ने के अधिकार के साथ, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से सरकार चलाने का अधिकार भी मिला हुआ है, किंतु अब केंद्र सरकार तीन संविधान संशोधन विधेयक लाकर उन विरोधाभासी कानूनों को बदलने की तैयारी में है, जो दागियों को जेल में रहते हुए सरकार चलाने की सुविधा देते हैं।

कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोक सभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक समेत तीन विधेयक पेश किए गए। इनमें गंभीर आपराधिक आरोप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लगातार 30 दिनों तक जेल में बंद रहने की स्थिति में स्वयमेव पद से हटाने का प्रावधान शामिल है। दरअसल, दागियों को चुनाव लड़ने से तब तक बाधित नहीं किया जा सकता है, तब तक वर्तमान विरोधाभासी कानूनों में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता। इस मकसद पूर्ति के लिए सरकार तीन विधेयक पारित कराने की इच्छुक है।

पहला, संविधान में 130वां संशोधन विधेयक-2025 है, जिसके तहत 30 दिन तक जेल में रह कर पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। पारित होने के बाद यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा विधेयक केंद्रशासित प्रदेशों के लिए इन्हीं प्रावधानों के साथ लागू होगा। तीसरा विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतएव धारा-54 में संशोधन करके आपराधिक मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को 30 दिन में हटाने का प्रावधान किया जाएगा।

हालांकि इन सभी विधेयकों में जमानत की सुविधा दी गई है। यदि 30 दिन में जमानत नहीं मिलती है तो ये स्वयं अयोग्यता के दायरे में आ जाएंगे। सरकार को संसद के दोनों सदनों से संशोधन विधेयक पारित कराने होंगे। वर्तमान में दलों के बीच जबरदस्त असहमति है, अतएव ऐसा संभव होना कठिन है। तत्काल टकराव को टालने के नजरिए से गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को समीक्षा हेतु भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे लोक सभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। चूंकि ये विधेयक विधायिका को अपराधमुक्त बनाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, इस कारण संयुक्त संसदीय समिति भी इन विधेयकों को समर्थन में दिखाई देगी?

संविधान के अनुच्छेद 173 और 326 में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा दोषी-करार दिए लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते। प्रश्न खड़ा होता है कि जब संविधान के अनुसार कोई अपराधी मतदाता भी नहीं बन सकता तो जनप्रतिनिधि बनने के नजरिए से निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी कैसे कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत यह दोहरा मापदंड समानता के अधिकार का उल्लंघन है। एक याचिका में दर्ज इस विसंगति को शीर्ष न्यायालय ने अपने अभिलेख में प्रश्नांकित करते हुए तब की मनमोहन सिंह सरकार से जवाब तलब भी किया था। तब सरकार ने शपथ-पत्र देकर तर्क गढ़ा था, 'कई बार सरकार बनाने या गिराने में चंद वोट ही बेहद महत्त्वपूर्ण होते हैं, लिहाजा सजा मिलने पर किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर दी जाती है तो सरकार की स्थिरता ही खतरे में पड़ सकती है।' यह भी तर्क दिया था 'यह उन मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा जिन्होंने उन्हें चुना है।' जाहिर है कि सरकार राजनीति में शुचिता लाने के बरक्स अपराध बहाली को तरजीह दे रही थी। अन्यथा सरकार क्या नहीं जानती कि जो प्रतिनिधि जेल में कैद है, वह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? क्या सरकार इस संवैधानिक व्यवस्था से अनभिज्ञ है कि किसी प्रतिनिधि की मृत्यु होने, इस्तीफा देने अथवा सदस्यता खत्म होने पर छह माह के भीतर नया जनप्रतिनिधि चुनने की संवैधानिक अनिवार्यता है? इस स्थिति में न तो कोई निर्वाचन क्षेत्र नेतृत्वविहीन रह जाता है और न ही सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ती है।

दागियों के बचाव में राजनेता और कथित बुद्धिजीवी सहजता से कह देते हैं कि दागी, धनी और बाहुबलियों को दल उम्मीदवार बनाते हैं, तो किसे जिताना है, यह तय स्थानीय मतदाता को करना होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर मजबूत विकल्प का अभाव होता है। अतएव मतदाता के समक्ष दो प्रमुख दलों के बीच से ही उम्मीदवार चयन की मजबूरी पेश आती है। लोक पर राजनेता की मंशा असर डालती है। मतदाता से राजनीतिक सुधार की उम्मीद करना बेमानी है क्योंकि राजनीति और उसके पूर्वाग्रह पहले से ही मतदाताओं को धर्म-जाति के आधार पर बांट चुके होते हैं। कई पार्टियां का तो बुनियादी आधार ही जाति है। वैसे भी देश में इतनी अज्ञानता, अशिक्षा, असमानता और गरीबी है कि लोग बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर मतदान करने लगे हैं। ऐसे में राजनीति में शुचिता-नैतिकता के कानूनी मानदंड स्थापित करने के प्रयास में सर्वसम्मति की जरूरत है।

दागियों के बचाव में राजनेता और कथित बुद्धिजीवी सहजता से कह देते हैं कि दागी-धनी-बाहुबलियों को दल उम्मीदवार बनाते हैं, तो किसे जिताना है, यह तय स्थानीय मतदाता को करना होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर मजबूत विकल्प का अभाव होता है। मतदाता के समक्ष दो प्रमुख दलों के बीच से ही उम्मीदवार चयन की मजबूरी पेश आती है।

लोक पर राजनेता की मंशा असर डालती है। मतदाता से राजनीतिक सुधार की उम्मीद करना बेमानी है क्योंकि राजनीति और उसके पूर्वाग्रह पहले से ही मतदाताओं को धर्म-जाति के आधार पर बांट चुके होते हैं। कई पार्टियां का तो बुनियादी आधार ही जाति है। अज्ञानता, अशिक्षा, असमानता, गरीबी के बीच मुफ्त की रेवड़ियां भी खेल करती हैं

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.

मीमांसा

क्या आप एक शेर की भांति काम करना चाहते हैं। शेर पूरा दिन काम नहीं करता। आराम करता है, सतर्क रहता है, और पूरी शक्ति से लक्षित प्रहार करता है। रचनात्मक कार्य मनोयोग से टुकड़े-टुकड़े में किया जाता है, जल्दबाजी में नहीं। जब मन प्रेरित हो तो बढ़िए। जब जरूरत हो तो आराम करिए। यही राजा का तरीका है।

हर्ष गोयनका, उद्योगपति@hvgoenka

संजीव ठाकुर

पाश्चात्य दर्शन बनाम सनातनी संस्कृति

भारतीय संस्कृति हमें अपने भारतीय होने का अहसास कराती है। हमें अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं, जो सामाजिक जीवन को अधिक सभ्य एवं अच्छा इंसान बनाए रखने में योगदान देती हैं, जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है, जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है, जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकता है। वहीं, पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती हैं, जिससे हम अपना जीवन तार्किक तथा बौद्धिक बना सकते हैं, जिन्हें हम जीवन में क्रियान्वित कर मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं।

निस्संदेह हम रूढ़िवादी या पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रख कर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपना कर जीवन सरल, सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं परंतु वर्तमान में हमने पश्चिम दर्शन से खोखला आधुनिकवाद ओढ़ लिया है, न अत्यंत आधुनिक ही हो सके हैं, और न ही सही-सही संस्कारित परंपरावा के वाहक ही बन पाए हैं। हम पाश्चात्य दर्शन और भारतीय संस्कार-परंपरा के बीच त्रिशंकु बन कर झूल रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वीणा के तार को इतना भी न कसो कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला छोड़ो कि वह बज भी न पाए। मूलतः हमें दोनों संस्कृतियों की समग्र अच्छाइयों को आत्मसात कर उनकी बुराइयों को त्यागना होगा तब ही जीवन सफल हो सकेगा। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता लिए होती है, और उसमें भौतिकता की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति से तात्पर्य भौतिकतावादी दृष्टिकोण से दूर रह कर भौतिकतावादी होने का ही है। प्राचीन काल से ही भारत देश में 'अतिथि देवो भव' और 'वसुधैव कुटुंबकम' वाली संस्कृति रही है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, विश्वास, भावना, आस्था, धर्म, रीति-रिवाज जैसे तथ्यों से भरी पड़ी है। धर्म प्रधान संस्कृति होने के कारण ही इसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला देश माना गया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में यदि कहें तो ईश्वरत्व और सदाचार पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियां हैं।

परंपरागत दृष्टिकोण से हम अपने धार्मिक तथा अध्यात्मिक दर्शन को लेकर बहुत हद तक अपने आप को एवं देश को महिमामंडित करने में लगे रहते हैं, किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर इस तथ्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि 21वीं सदी में पांचवी एवं छठवीं सदी की मान्यताएं तथा परंपराएं जारी रख उन्हें अपना सकते हैं क्या?, आज जब दुनिया वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया विज्ञान की प्रगति से चांद तो क्या सूर्य को भी खंगालने का प्रयास कर रही है। मानव का क्लोन बना कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है।

ऐसे में धार्मिक संस्कृति तथा आध्यात्मिकता को आवश्यकता से अधिक महत्त्व एवं परंपरा में लाना प्रासंगिक एवं तार्किक होगा। निस्संदेह नहीं। पाश्चात्य दर्शन भौतिकता प्रधान एवं वैज्ञानिक संस्कृति है। भौतिकता प्रधान युग से तात्पर्य ऐसी परंपरा जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्त्व देती है। वैसे ही भौतिकता का सामान्य मतलब इंद्रिय बोध से साक्षात

संबंध रखने वाली वस्तु से है अर्थात जो वास्तविकता है एवं यथार्थ है वही पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य संस्कृति को इसलिए भी वैज्ञानिक एवं वस्तुपरख माना जाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जांच-पड़ताल कर वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन अपना कर एक सामान्य सिद्धांत एवं नियम बनाया जाता है जिससे भविष्य की बातों को जान कर जीवन को और अच्छा तथा बेहतर बनाने में मदद मिल सके। वैसे पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सी अहितकर बातें भी हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कमतर होते जा रही है। संयुक्त परिवार की प्रणाली का विघटन होते जा रहा है। पारिवारिक वातावरण संघर्ष तथा तनावपूर्ण होते जा रहा है।

पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर लोग परिवार से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करना पसंद करते हैं। उनमें विवाहविच्छेद और अन्य विसंगतियां जन्म लेने लगी हैं। धर्म तथा आध्यात्मिक के प्रति आमजन की सूची धीरे-धीरे कम होते जा रही है। ऐसो आराम के सामान खरीदने के कारण लोगों के खर्चे अनाप-शनाप बढ़ चुके हैं। बुजुर्गों की इज्जत तवज्जो होना कम हो गई है।

दादा और नाती के संबंधों में अब वह गर्माहट शेष नहीं रह गई है, जैसी की एक सांस्कृतिक तथा नैतिक परिवार जनों में हुआ करती थी। धीरे-धीरे परिवार के सदस्य अलग होकर अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति भूलती जा रही है। प्रेम विवाह तथा अंतरजाति विवाह पाश्चात्य सभ्यता के कारण बहुत बढ़ गए हैं जिससे वैवाहिक संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं पर दूसरी तरफ पाश्चात्य सोच के कारण स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है। महिलाएं जहां पहले अपने घरों में कैद थीं, अब उन्मुक्त होकर शिक्षित होकर समाज में सफल होकर पुरुषों से कंधे से कंधा मिला कर व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना कर बड़े-बड़े पदों में कार्य कर रही हैं। समाज में खुलापन भी आ गया है।

विकास रोजगार एवं मानवीय सोच में भी काफी विस्तार आया है, जो विश्व की सभ्यताओं में आज मौजूद है, जो भारत के विकास में सहायक भी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें आध्यात्मिक भारतीय परंपरा संस्कृति तथा पाश्चात्य दर्शन तथा पाश्चात्य संस्कृति की सकारात्मक बातें आत्मसात कर विकास की एक नई राह खोजनी होगी एवं सदैव अच्छी बातों के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा और पाश्चात्य संस्कृति की विसंगतियों को दूर रख भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ■

पाश्चात्य संस्कृति को इसलिए भी वैज्ञानिक एवं वस्तुपरख माना जाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जांच-पड़ताल कर वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन अपना कर एक सामान्य सिद्धांत एवं नियम वनाया जाता है जिससे भविष्य की वातों को जान कर जीवन को और अच्छा तथा वेहतर वनाने में मदद मिल सके। वैसे पाश्चात्य संस्कृति में वहुत सी अहितकर वातें भी हैं, जैसे वसुधैव कुटुंवकम की भावना कमतर होते जा रही है। संयुक्त परिवार की प्रणाली का विघटन होते जा रहा है। पारिवारिक वातावरण संघर्ष तथा तनावपूर्ण होते जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर लोग परिवार से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करना पसंद करते हैं

हास्य-व्यंग्य | सुरेश सौरभ

थप्पड़-थप्पड़ का खेला

बात पुरानी है-तब अपने विद्यार्थी जीवन का अल्हड़पन और लड़कपन था। पड़ोस में कुछ लड़के रहते थे-वे कहीं गांव से, शहर में आकर पढ़ाई करने आए थे। कमरा किराये से लेकर बड़ी मौज में रहते थे। अक्सर आधी-आधी रात तक वह खूब हंसते, कभी रोते, कभी चिल्लाते। मैंने एक रोज उनसे पूछा-भाई क्या मामला है-तुम लोगों का, आधी-आधी रात तक हंसने-गाने-रोने का कौन सा सीरियल चलता है। तुम लोगों की क्या नाटकबाजी है ये सब।

वे हंसते हुए बोले-जब पढ़ने का मन नहीं होता, मन बहुत ऊबने लगता है, तब हम लोग चुटकुलेबाजी शुरू करते हैं-धुआंधार हास्य-व्यंग्य के लतीफे शुरू करते हैं, और तब हंसगुल्लों की बौछार शुरू होती है, और फिर जब हम हंसगुल्लों से हंसते-हंसते लोटपोट ,बेहाल हो जाते हैं-

पेट पर तमाम बल पड़ने लगता है-तब हम एक-दूसरे को थप्पड़ मारते हैं-तब हमारी हंसी-ठहाकों का प्रवाहमान सैलाब थमता है। मेरा पूरा सिर नाच गया। मैंने कहा-वाह क्या सीन है। हंसी के मैच में थप्पड़ की फिक्सिंग। जिओ और जीने दो के महान समीकरण पर क्या खूब मनोरंजन का खेला रचाया है, भाई तुम लोगों ने। वाह! क्या गजब का टाइमपास, टॉप क्लास का मनोरंजन है। शगल है। बरसों बीते गए, हंसगुल्ले वाले उन लड़कों को, अब मैं नेता के वेश में टीवी, मोबाइल पर रोज देखता हूं। विद्यार्थी जीवन से शुरू हुआ उनका, थप्पड़-थप्पड़ में हंसी-ठहाकों और रोने, गाने का खेला, अब कहीं स्याहीफेंक, कहीं जूताफेंक, कहीं कालिख पोत आदि इत्यादि तक की बड़ी पटकथा तक पहुच चुका है। ■

जीवन में ऊंचाई मायने रखती है : राजगुरु

जयंती पर विशेष

कल्पना करें उस पल को, जब एक युवा, जिसकी उम्र मुश्किल से इक्कीस-बाइंस वर्ष होगी, आंखों में आजादी का सपना लिए, चेहरे पर न डरने वाली हंसी और दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट जुनून लिए, फांसी के तख्ते की ओर इस तरह बढ़ता हो, मानो कोई उत्सव मनाने जा रहा हो। यह महज काल्पनिक चित्र नहीं, बल्कि शिवराम हरि राजगुरु की अमर गाथा है, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अनूठे हास्य से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई चमक दी। राजगुरु का जीवन सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, बल्कि ऐसी ज्योति है, जो हमें आत्मबल, बौद्धिक गहराई और निर्भीकता का सबक देती है।

शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त, 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा (अब राजगुरु नगर) में मध्यमवर्गीय मराठा परिवार में हुआ। बचपन साधारण रहा पर सोच असाधारण थी। कम उम्र में बनारस जाकर उन्होंने संस्कृत और तर्कशास्त्र का गहन अध्ययन किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में पूछताछ के दौरान संस्कृत में जवाब देकर अंग्रेजों को चकित कर दिया जो उनकी विद्वता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक था। राजगुरु का व्यक्तित्व विद्वता तक सीमित नहीं था; उनकी शारीरिक शक्ति और अनुशासन भी अद्भुत थे। बनारस में 'हनुमान प्रसारक मंडल' से जुड़कर उन्होंने कुश्ती, व्यायाम और आत्मरक्षा में निपुणता हासिल की। क्रांतिकारी आंदोलन के चरम पर उन्होंने अपने शरीर को लोहे-सा दृढ़ बनाया, जो किसी भी यातना को झेल सके।

एक बार चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस की यातनाओं का जिक्र किया। जवाब में राजगुरु ने चुपके से अंगीठी से जलती लोहे की छड़ उठाई और उसे अपने शरीर पर सात बार रखा बिना दर्द की शिकन के। आजाद के चिंतित पूछने पर उन्होंने हंसते हुए कहा, 'यातना शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं।' यह उनकी अटूट सहन शक्ति और आत्मबल का प्रेरक उदाहरण है, जो इतिहास में कम ही उजागर हुआ। राजगुरु की निशानेबाजी की कला अद्वितीय थी, जिसने उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नायाब सिपाही बनाया। 17 दिसम्बर, 1928 को लाहौर में जॉन सांडर्स की हत्या की योजना में उनकी भूमिका उनकी अचूक निशानेबाजी के कारण थी। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने उनकी सटीकता पर अटूट भरोसा जताते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। भले ही गोली स्कॉट के बजाय सांडर्स को लगी, इस कार्रवाई ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। कार्रवाई के बाद राजगुरु की निर्भीक सहजता देखते बनती थी। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, निशाना सिर पर था, गोली सीने में लगी। यह हास्यबोध उनकी निर्भीकता का प्रतीक था। मृत्यु की छाया में भी उनकी हंसी अडिग रही। राजगुरु का हास्यबोध उनकी सबसे अनोखी विशेषता थी। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी दोस्ती केवल क्रांति की साझेदारी नहीं थी, बल्कि ऐसा रिश्ता था जो हंसी और आत्मीयता से भरा था। जेल में भी वे अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए मजाक करते। एक बार भूख हड़ताल के दौरान जब साथियों ने उनसे पूछा, 'अगर तुम पहले मर गए तो?' तो राजगुरु ने ठहाका लगाते हुए कहा, 'तो मैं वहां तुम्हारे लिए एक कमरा बुक कर दूंगा।' यह हल्का-फुल्का जवाब उस युवक की मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है, जो मृत्यु को भी खेल की तरह लेता था।

उनकी सहजता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब सांडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह और राजगुरु को भागना पड़ा। भगत सिंह और उनकी पत्नी दुर्गावती (जो साथ थीं) ने अंग्रेज साहब और मैम का वेश बनाया जबकि राजगुरु ने नौकर की भूमिका निभाई। ट्रेन में उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि अंग्रेज अधिकारी भी धोखा खा गए। लाहौर सेंट्रल जेल में राजगुरु का अटल आत्मबल कभी नहीं डिगा। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी बातचीत गंभीरता और हास्य का अनूठा संगम थी, जो जेल की दीवारों को उनके ठहाकों से गूंजने देती थी। फांसी से कुछ घंटे पहले उन्होंने साथियों से कहा, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी ऊंचाई में है। यह वाक्य उनके जीवन का सार है। महज 22 वर्ष की उम्र में राजगुरु ने ऐसी ऊंचाई छुई, जो आज भी हर दिल को प्रेरित करती है, साहस और बलिदान की अमर गाथा बनकर।

राजगुरु को प्रायः भगत सिंह और सुखदेव की छाया में देखा जाता है, किंतु यह एक भ्रांति है। वे उस त्रयी का अपरिहार्य अंग थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा गति प्रदान की। कम लोग जानते हैं कि जेल में राजगुरु ने संस्कृत में एक डायरी लिखी, जिसमें उनके गहन विचार झलकते थे। अफसोस, वह डायरी आज लुप्त है, पर यह उनके बौद्धिक सामर्थ्य का प्रतीक है। उनकी जयंती पर हमें स्मरण करना होगा कि राजगुरु क्रांतिकारी नहीं, बल्कि जीवंत प्रेरणा भी थे। उन्होंने सिखाया कि क्रांति केवल बारूद और बंदूकों का शोर नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्मबल और हृदय की निर्मलता का संगम है। 23 मार्च 1931 को, जब राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव फांसी के तख्ते पर चढ़े, उन्होंने न केवल अपनी जान कुर्बान की, बल्कि ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो आज भी धधक रही है। राजगुरु की निर्भीक मुस्कान, गहन विद्वता और प्रचंड ज्वाला हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता महज शब्द नहीं, बल्कि पवित्र जिम्मेदारी है। उनकी गाथा कोई धूमिल इतिहास नहीं, बल्कि जीवंत प्रेरणा है, जो साहस, हास्य और ज्ञान के संगम से असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। उनकी अमरता मृत्यु में नहीं, बल्कि उस अखंड ऊर्जा में बसती है, जो आज भी हमारे हृदय में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्जवलित रखती है।

प्रस्तुति -प्रो. आर.के. जैन ■

कविता | अनुष्का नरेन्द्र देवपुरिया

लड़का होना भी आसान...

लड़कों का जीवन जीना भी इक दुश्वारी होती है।
सपनों से ज्यादा कंधों पर जिम्मेदारी होती है।।

दुनिया भर का दर्द समेटे रहते अपनी मुट्ठी में,
घर में सबको खुश रखते खुद तपते रहते भट्ठी में,
जब बात सुकूं की आती है तब उसका नाम नहीं होता,
पर बात अगर तानों की हो बिन उसके काम नहीं होता,
कभी साथ जो न देती वो रिश्तेदारी होती है।
सपनों से ज्यादा कंधों पर जिम्मेदारी होती है।।

मां की दवा बहन की शादी के ख़र्चे में सपने रह जाते,
प्यार मोहब्बत के चक्कर में गिरते खुद ही संभल जाते,
पत्नी की फरमाइश पूरी करने को क्या क्या करते,
बच्चों की खुशियों के खातिर वो दिन रात पिसा करते,
उनके सपनों में तो लगी एक चिंगारी होती है।
सपनों से ज्यादा कंधों पर जिम्मेदारी होती है।।

घर में जब लड़के रहते तो कहते कि वो मर्द नहीं,
घर से बाहर जब निकलें कहते अपनों का दर्द नहीं,
अपनी उम्मीदों पर आखिर कब तक उन्हें चलाओगे,
आंसू पर भी रोक लगा कर कब तक उन्हें रुलाओगे,
लड़कों की भी सब खुशियों में हिस्सेदारी होती है।
सपनों से ज्यादा कंधों पर जिम्मेदारी होती है।।

लड़कों का जीवन जीना भी इक दुश्वारी होती है।
सपनों से ज्यादा कंधों पर जिम्मेदारी होती है

■

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राग रंग | आलोक पराड़कर

विरासत की बड़ी चुनौती

बहुत सारे लोगों के बनारस जाने का एक कारण दिग्गज संगीतकारों से भेंट-मुलाकातें भी रहा है। बनारस की तंग गलियों में कभी कोठों से सारंगी और तबले की सवारी करती टीपें गूंजा करतीं। उसकी दो-चार गलियों में रहने वाले पद्म अलंकरणों से सम्मानित दिग्गज संगीतकारों की संख्या कई-कई शहरों पर भारी पड़ती रही है। अगर किसी समय बनारस में शास्त्रार्थ विद्वता का प्रमाण समझा जाता था तो संगीत समारोहों की दर्शक दीर्घा में दिग्गज कलाकारों की उपस्थिति बाहर से आने वाले कलाकारों को सतर्क और सावधान रखती थी। वह उन्हें अपना श्रेष्ठ प्रस्तुत करने को प्रेरित भी करती थी।

बनारस ने शास्त्रीय-उपशास्त्रीय संगीत को जिस प्रकार संरक्षित-प्रोत्साहित किया वह दुर्लभ है लेकिन पिछले दिनों बनारस के कलाकारों को बकायदा पत्रकार वार्ता कर कहना पड़ा कि बनारस के बारे में यह दुष्प्रचार ठीक नहीं है कि यहां अब कलाकार नहीं हैं। उस वार्ता में यह भी कहा गया कि बनारस में आज भी लगभग डेढ़-दो सौ कलाकार हैं, और स्थानीय कलाकारों का कोई संगीत समारोह अगर यहां कभी आयोजित हो तो तो वह इस संख्या के कारण कई-कई दिनों तक चल सकता है। जो शहर संगीत का गढ़ रहा है, जिस नगर के नाम पर संगीत की विभिन्न विधाओं में घराने चलते हैं, जिसके साथ कई विख्यात कलाकारों का नाम जुड़ा है, उसके बारे में अब ऐसी बातों का होना ही चिंताजनक है लेकिन यह भी सच है कि किसी समय बनारस में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों का एक दुर्लभ प्रवास था। कल्पना करके जरा देखिए, हड़हा सराय में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रह रहे हैं, नाटी इमली में विदुषी गिरिजा देवी हैं, कबीरचौरा में पं. गुदई महाराज और पं. किशन महाराज अपने भरे-पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, रामापुरा में पं. महादेव प्रसाद मिश्र हैं, और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन.राजम। ये कुछ चर्चित नाम हैं, नगर में प्रवास करने वाले प्रसिद्ध कलाकारों में कई और भी थे।

यह वह समय था जब नगर में हो रहे समारोहों में अगर ये कलाकार अपनी संगीत प्रस्तुतियां नहीं कर रहे होते तो दर्शक दीर्घा में उपस्थित रहते। अच्छी तरह याद है कि एक बार ऐसे ही घाट की सीढ़ियों पर उपस्थित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सितार वादन कर रहे उस्ताद विलायत खान से खड़े होकर फरमाइश कर दी थी और चौखंभा की गलियों में गेंठे जी के फाटक के पास एक छोटी-सी धर्मशाला में सामने इस शहनाई सम्राट को देखकर पं. जसराज भावविभोर हो उठे थे। विदुषी गिरिजा देवी और पं. किशन महाराज तो कितने ही संगीत समारोहों में कलाकारों के चयन को लेकर भी मार्गदर्शन करते थे। महाराज तो प्रायः हर प्रमुख समारोह में रहते ही थे। यह भी सच है कि कथक क्वीन सितारा देवी और उनकी बहनें पहले ही मुंबई जा चुकी थीं तथा पं. राजन मिश्र और पं. साजन मिश्र ने भी दिल्ली का रुख कर लिया था लेकिन इन कलाकारों का भावनात्मक जुड़ाव अपने गृह नगर से हमेशा बना रहा। सारंगी वादक पिता पं. हनुमान प्रसाद मिश्र कबीरचौरा के अपने घर में ही रहे तो मिश्र बंधु का आना-जाना लगातार होता रहा। पं. रविशंकर देश-दुनिया में घूमते रहे, ठहर कर अपने जन्म स्थान में नहीं रह सके लेकिन उनके रिपा के आयोजनों को संगीत प्रेमियों ने लंबे समय तक याद रखा।

विदुषी गिरिजा देवी भी जब कोलकाता रहने लगीं तो बनारस आने का अवसर ढूंढती रहतीं। लेकिन याद रखा जाना चाहिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तबले के दो धुरंधर-पं. गुदई महाराज और पं. किशन महाराज और फिर पं. छन्नूलाल मिश्र जैसे कलाकार तमाम प्रलोभनों और आमंत्रणों को ठुकराते हुए असुविधाओं के बावजूद बनारस में ही रहे, यह कहते हुए 'जन्नत भी भरे पानी मेरी काशी के सामने'। इससे बनारस का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध बना रहा लेकिन फिर वह समय भी आया जब बिस्मिल्लाह खान, गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, राजन मिश्र जैसे कलाकारों के निधन से अचानक इस परिदृश्य में खालीपन आ गया। एन. राजम सेवानिवृत्ति के बाद मुंबई चलीं गईं और कोरोना में पारिवारिक सदस्यों को खोने के बाद स्वास्थ्य कारणों से छन्नूलाल मिश्र बेटी के पास मिर्जापुर में रहने लगे।

यूं देखें तो, बनारस का संकट समूचे हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संकट भी है, जहां दिग्गज कलाकारों के निधन के बाद एक खालीपन दिखने लगता है लेकिन बनारस में यह खालीपन अब अधिक नजर आने लगा है। हालांकि बनारस ऐसा नगर है जहां संगीत समारोहों की आज भी खूब धूम होती है, और दिग्गज कलाकारों का आना-जाना बराबर बना रहता है। दिवंगत पं. किशन महाराज ने ऐसे ही सवाल पर बातचीत में मुझसे कहा था, 'जब कमरे में अधिक रोशनी वाला बल्ब जल रहा होता है तो कम रोशनी के बल्ब का जलना नहीं दिखता है'। आज जब बनारस में बड़े बल्ब अब नहीं हैं, छोटे बल्बों को अपनी रोशनी बढ़ाने की चुनौती है। यह अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखने और उसे आगे बढ़ाने का समय है। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

आधुनिक शिल्प के प्रणेता रामकिंकर

देश के अग्रणी मूर्तिकारों में एक रामकिंकर बैज आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूत के माने जाते हैं। लगभग 120 वर्ष पूर्व को जन्मा यह मूर्धन्य कलाकार अभिव्यक्ति और जुड़ाव के नवीनतम रूपों की खोज करता रहा। नये आकारों को खोजती उनकी यह दृष्टि कला और पारंपरिक धारणाओं को चुनौती भी देती रही। वह नवीन रूपों में रचनात्मकता को विस्तार देते एवं वर्जनाओं को तोड़ते वैचारिक रूप से सामाजिक मूल्यांकन को भी परिभाषित करते रहे। आधुनिकतावादी शैली और पारंपरिक भारतीय विषयों को समकालीन तकनीकों के साथ मिश्रित करते शिल्प, चित्र एवं रेखांकन के माध्यम से रचनात्मक आकार देती उनकी कला में अपने अंतर्निहित ज्ञान और धारणाओं का प्रयोगात्मक दृष्टिकोण उनका श्रेष्ठ अभिव्यक्तिपूर्ण कला कौशल है, जो उनकी 'संथाल परिवार' और 'मिल कॉल' जैसी कृतियों में भी दिखता है।

पद्म भूषण से सम्मानित बंगाल के बांकुड़ा जिले में गरीब नाई परिवार में जन्मे रामकिंकर के रचनात्मक स्वरूप से जब हम पिछली सदी के भारतीय कला में विकास को देखते हैं, तो पता चलता है कि आधुनिक कलाकारों में विस्तृत रूप से परिवर्तन हुए हैं। इसी क्रम में परिवर्तन की दृष्टि से जब बैज की कलाकृतियों को गौर से देखते हैं, तो गढ़े शिल्पों में कलाकार की व्यापक दृष्टि दिखती है, जहां कलाकृति की विषयवस्तु, शैली, तकनीक और संदर्भ के संबंध में यह कलाकार अत्यधिक चिंतनशील दिखता है।

नंदलाल बोस ने उनकी इस प्रतिभा को आरंभ में ही पहचाना। "लैंपस्टैंड" जैसी अपनी मूर्तियों में अमूर्तता के विशिष्ट प्रयोग के साथ आधुनिकता को नई दिशा दी। यह कलाकार अपने कामों को मौलिक रूप में अभिव्यक्त करता है। लाल मिट्टी से रेखाचित्र और मूर्तियां रचने की उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर पत्रकार रामानंद चट्टोपाध्याय ने बैज को शांति निकेतन के कला भवन में प्रवेश कराया, जहां प्रवास के दौरान संथाल, प्रकृति और आमजन का चित्रण किया। दर्शक जब उनके इन चित्रांकन को देखते हैं, तो उनकी कला में अजीब बेचैनी सी दिखती है, जो सामाजिक-राजनीतिक विमर्श की गहराई से निहित है। संवेदनशील विषय को कलाकार ने बेहद मार्मिकता से रचा है। वे जितना संवेदनशील हैं, उतना ही अपनी कला में दक्ष हैं। यह दक्षता उनकी स्मृति के विषयों को इतना सशक्त बनाती है कि वह अपने अनुभवों और इरादों के दृष्टिकोणों से आकारों को विस्तृत रूप देते हैं। नई दिल्ली में आरबीआई भवन के मुख्यद्वार में खड़ी यक्ष-यक्षी के शिल्प यही आभास कराते हैं।

19वीं सदी में समकालीन कला के प्रवर्भाव में 20वीं सदी के मूर्तिकारों के लिए उनके भविष्य हेतु चुनौती भरी लकीर खींच कर अनेक प्रयोग किए। इसी वैचारिकी के साथ बैज के शिल्पों की सतहें बताती है कि रचने की प्रक्रिया में कलाकार की दृष्टि आकारों को कितना विश्लेषित कर सकती है। कला के माध्यम से विचारधाराओं, धार्मिकता, अंधविश्वास और सामाजिकता जैसे विभिन्न कारकों को संदर्भित करते हैं। उनके बोल्ड आकारों में प्रदर्शित काम आम जन की मानवीय स्थिति पर चिंतन करने को मजबूर करते हैं। आग्रह करते हैं कि जीवन में मूल्यवान आदर्श अपनाएं।

रामकिंकर वह समकालीन कलाकार हैं, जो संदर्भों को कुछ इस तरह से अपनी कला के माध्यम से जड़ते हैं कि हमें पीछे से आगे की ओर ले चलते हैं। वह कहते भी थे कि इस दुनिया के बगीचे में दिन के उजाले में मैं अपनी आंखों से जो देखता हूं, उसे अपनी पेंटिंग में चित्रित करता हूं, इसके अंधेरे में मैं जो छूता और महसूस करता हूं, उसे अपनी मूर्तिकला में ढालता हूं। अपनी पेंटिंग, मूर्तियों आदि के माध्यम से कलाकार प्रतिरोध की उन परतों को भी गढ़ते रहे जो परत दर परत विक्षोभ और विरोध का प्रदर्शन करती हैं। उनकी शिल्पाकृतियों पर दृष्टि जाती है तो विस्मृत भाव से भान होता है कि ये आम कलाकृतियां नहीं हैं, जो अपने पूर्ण अर्थ को संप्रेषित करती हैं। 2 अगस्त, 1980 देह त्यागने वाले रामकिंकर बैज द्वारा सीमेंट माध्यम में गढ़ा गया अपने गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का शिल्प उनके सुजाता, हार्वेस्टर आदि जैसे कई प्रसिद्ध शिल्पों में एक है। ■

मानवीय भावना को तकनीक पर प्रबलता हासिल करनी होगी।
-अल्बर्ट आइंस्टीन

कल्पना कीजिए कि किसी व्यस्त चौराहे पर एकाएक कई कारें खड़ी हो जाएं, जिन्हें अपनी जगह से इंच भर भी हिला पाना मुमकिन न हो। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआई6 के पूर्व प्रमुख रिचर्ड डिअरलव ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ से नाराज चीन एक ही झटके में तकरीबन 400 इलेक्ट्रिक कारों का कनेक्शन काटकर लंदन के ट्रैफिक को घुटनों पर ला सकता है।

चीन, इलेक्ट्रिक कारें और स्पाइवेयर

चीन द्वारा प्रौद्योगिकी का शस्त्रीकरण एक कंपकंपा देने वाला यथार्थ बन चुका है। इस खतरे की गंभीरता का पता ब्रिटेन को तब लगा, जब 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकारी गाड़ी में चीनी ट्रैकिंग डिवाइस पाई गई।

रवींद्र दुबे
वरिष्ठ पत्रकार

दइटैलियन जॉब फिल्म की वजह से ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। इस क्लासिक फिल्म में माइकल केन द्वारा अभिनीत चार्ली क्रोकर के नेतृत्व में लंदनवासियों का एक गिरोह तुरीन की ट्रैफिक लाइटों को नाकाम कर चुराए हुए सोने से लदे एक ट्रक का अपहरण कर लेता है। ट्रैफिक लाइटों के साथ छेड़छाड़ एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की जाती है, जिसकी भूमिका बेनी हिल ने निभाई है। वह एक सेंट्रल कंप्यूटर को हैक कर पूरे शहर में ट्रैफिक जाम करवा देता है और क्रोकर का गिरोह सोने से लदे ट्रक को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। यह फिल्म 1969 में बनी थी, लेकिन इसकी कथावस्तु का यह पहलू पहले से कई गुना ज्यादा गूंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यातायात व्यवस्था का तकनीकी पक्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी कि खुद गाड़ियां, जो कि आजकल पहिये लगे कंप्यूटरों में तब्दील हो चुकी हैं।

सेंसरों और कैमरों से उफनती हुई वायरलेस कनेक्शन द्वारा अपने निर्माताओं के नेटवर्कों से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक कारें दुनिया की महाशक्तियों द्वारा प्रभुत्व की खातिर विश्वव्यापी युद्ध में नवीनतम मोहरा बन चुकी हैं। चूंकि, ब्रिटेन के कार बाजार में चीन का हिस्सा दस प्रतिशत से अधिक है-और आने वाले वर्षों में और भी बढ़ने वाला है, ब्रिटेन के लिए एक गंभीर समस्या साबित होगा। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के कारण बीजिंग के अमेरिकी बाजार से बाहर होने की आशंकाएं मंडरा रही हैं।

ब्रिटेन की बाहरी खुफिया एजेंसी एमआई6 के पूर्व प्रमुख रिचर्ड डिअरलव ने चेतावनी दी है कि चीन एक ही झटके में तकरीबन 400 इलेक्ट्रिक कारों का कनेक्शन काटकर लंदन के ट्रैफिक को घुटनों पर ला सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यस्त चौराहे पर एकाएक कई कारें खड़ी हो जाएं, जिन्हें अपनी जगह से इंच भर भी हिला पाना मुमकिन न हो? उनका मानना है कि यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक आशंका है।

चूंकि, ये गाड़ियां इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आसानी से दूर बैठे ही निष्क्रिय किया जा सकता है। इस अवधारणा को यूक्रेन में विस्तार से दर्शाया जा चुका है। रूसी सेनाओं ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर आधुनिक वाहन चुरा लिए। इन वाहनों की डीलरशिप जॉन डीयर के पास थी। रूसियों ने इन्हें जहाजों में लादकर 700 मील दूर चेचन्या भेजा, लेकिन वे उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि जॉन डीयर ने उन वाहनों को ट्रैक कर उन्हें दूर से ही बंद कर दिया।

दुनिया के ज्यादातर लोग मोबाइल फोन में स्पाइवेयर को लेकर चिंतित हैं, तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां इस बात से परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) पूरी तरह विशालकाय स्पाइवेयर हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ईवी को निष्क्रिय कर बंद कर दिए जाने पर ब्रिटेन के शहरों में एक इटैलियन जॉब का खतरा पैदा हो सकता है।

ईवी तोड़फोड़, निगरानी, जासूसी, यहां तक कि लक्षित हत्याओं के लिए पूर्ण हथियार है। साइबर सुरक्षा सम्मेलनों में प्रदर्शन किए जाते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक कारों का नियंत्रण हाथों में लिया जा सकता है। चीनी हैकरों के एक समूह ने तो इस बात पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की है कि उन्होंने किस तरह से एक टेस्ला कार के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को तोड़कर उसे लेन में यू-टर्न करवा दिया। दूसरे गुट ने बताया कि किस तरह से किसी कार की डिक्की, विंडस्क्रीन के वाइपर और यहां तक कि ब्रेक भी दूर से ही सक्रिय या निष्क्रिय किए जा सकते हैं। ईवी की बैटरी की 50 फीसदी वैश्विक आपूर्ति का नियंत्रण सीएटीएल और बीवायडी नामक, दोनों चीनी कंपनियों के हाथ में है। इनकी नजरें ईवी उद्योगों के वर्चस्व पर केंद्रित हैं, जिनमें चार्जिंग नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण व्यवस्थाएं शामिल हैं। दोनों कंपनियों की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से निकटता है और ये सरकार से प्राप्त सब्सिडी से लाभान्वित भी हुई हैं। इससे सुरक्षा खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बिजली के भंडारण और चार्जिंग नेटवर्कों को देश की इलेक्ट्रिकल ग्रिड से जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

इसके अलावा, कई ऐसे चीनी कानून हैं, जो सभी कंपनियों को, चाहे वे पूरी तरह सरकारी हों या निजी, राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्रित करने हेतु सहयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। ये कंपनियां किसी भी सूरत में सरकार को मना नहीं कर सकतीं। हालांकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि चीनी कार कंपनियां ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकतीं, क्योंकि इससे उनके धंधे पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप यह बात मान लेते हैं, तो आप बहुत मासूम हैं! चीन द्वारा प्रौद्योगिकी का शस्त्रीकरण एक कंपकंपा देने वाला यथार्थ बन चुका है। इस खतरे की गंभीरता का पता ब्रिटेन को तब लगा, जब 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकारी गाड़ी में चीनी ट्रैकिंग डिवाइस पाई गई। वह चीन से आयातित एक पुर्जे में छिपी हुई थी, जिसे निर्माता कंपनी ने फिट किया था। प्रधानमंत्री की कार चीन में तो नहीं ही बनी थी!

हाल ही में ब्रितानी प्रतिरक्षा अनुबंधों पर काम कर रही फर्मों ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने मोबाइल फोनों को चीन द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक कारों से कनेक्ट न करें। उन्हें भय है कि संवेदनशील डाटा बीजिंग न चला जाए। दरअसल, हर प्रतिरक्षा आपूर्तिकर्ता चीन निर्मित कारों की तकनीक के प्रति आशंकित है। ये कारें न सिर्फ आपकी यात्राएं डाउनलोड कर सकती हैं, बल्कि मैसेज, वॉइसमेल व मोबाइल के संवेदनशील दस्तावेज भी निकाल सकती हैं। बताते हैं कि बीएई सिस्टम्स, रोल्स रॉयस, रेथियॉन, लॉकहीड मार्टिन और थेल्स जैसी बड़ी-बड़ी डिफेंस फर्में भी इनमें शामिल हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ईवी के संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों और प्रशिक्षण कैंपों में घुसने पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। सैन्य प्रमुखों का जोर तो इस बात पर भी है कि न सिर्फ चीनी ईवी, बल्कि चीनी पुर्जों वाली कारें भी संवेदनशील भवनों से दो मील की दूरी पर खड़ी की जाएं।

अमेरिका और यूरोपीय संघ में ये वाहन कड़ी निगरानी में तो हैं ही, इन्होंने आयात पर काफी लेवी लगा दी है। नतीजतन चीन अब नए बाजार खोज रहा है, जहां वह इन कारों के पहाड़ को खपा सके। उसकी नजर भारत पर भी है, क्योंकि भारत भी आयातित कारों का अच्छा-खासा बाजार है। और चीनी इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होती हैं, क्योंकि चीन उनके निर्माण के लिए काफी सब्सिडी देता है तथा जबर्दस्त और जरूरत से ज्यादा उत्पादन को भी प्रोत्साहित करता है। फिलहाल चीन कुछ भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ईवी के बाजार में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। चीनी कंपनियां बीवायडी और लीपमोटर भारतीय बाजार में घुसने की तैयारी कर रही हैं।

आखिरकार भारत भी इन कारों के निर्माण में लिथियम आयन बैटरियों पर निर्भर है, जिनका एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। अस्तु, हालात चाहे जो हों, लेकिन क्या हमें ब्रिटेन की चिंताओं से सबक सीखने की जरूरत है या नहीं? वैसे ही पिछले कुछ वर्षों में चीन भारत को लेकर काफी विवादों में घिरा रहा है। चाहे वह डोकलाम मुद्दा रहा हो या फिर अरुणाचल और सिक्किम को लेकर उसके दावे हों।

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

पांच अप्सराओं ने तपस्वी की साधना में विघ्न डाला। इससे क्रोधित होकर उन्होंने अप्सराओं को सौ वर्षों तक ग्राह बनने का शाप दे दिया। क्षमा-याचना करने पर तपस्वी ने बताया कि अब तुम्हें कोई श्रेष्ठ पुरुष ही मुक्ति दिलाएंगे।

ग्राह बनीं अप्सराओं को कैसे मिली मुक्ति

पूर्वकाल की बात है, अर्जुन बारह वर्षों की तीर्थयात्रा पर निकले थे। वह मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पांच तीर्थों में स्नान करने का निश्चय किया। ये तीर्थ बहुत पवित्र माने जाते थे, परंतु उनमें रहने वाले ग्राहों के भय से तपस्वियों ने इन्हें छोड़ दिया था और वे लोग दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। पहला तीर्थ कुमारेश था, जो मुनियों को प्रिय था। दूसरा स्तंभेश था, जो सौभद्र मुनि को प्रिय था। तीसरा वर्करेश्वर तीर्थ था, जो इंद्र-पत्नी शची को प्रिय था। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ राजा करंधम को तथा पांचवां सिद्धेश तीर्थ महर्षि भारद्वाज को प्रिय था। अर्जुन ने इन पांचों तीर्थों का दर्शन किया और नारद आदि मुनियों से पूछा कि इतने सुंदर तीर्थों को मुनियों ने क्यों छोड़ दिया। तब तपस्वियों ने अर्जुन को बताया कि इन तीर्थों में पांच ग्राह रहते हैं, जो तपस्वियों को जल में खींचकर ले जाते हैं। इसी कारण इन तीर्थों का त्याग कर दिया गया है।

धूप आने दो

तपस्वियों ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह उन तीर्थों में स्नान करने न जाएं, क्योंकि ग्राहों ने कई राजाओं और मुनियों को मार डाला था। मुनियों ने अर्जुन को समझाते हुए यह भी कहा कि बारह वर्षों में उन्होंने अनेक तीर्थों में स्नान किया ही होगा, फिर इन पांच स्थानों तीर्थों में स्नान करने पाप लगेगा? इस पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि धर्माचरण के लिए यदि जीवन भी चला जाए, तो कोई हानि नहीं। जो व्यक्ति अपना जीवन, धन, पुत्र, स्त्री व धर्म के लिए अर्पित कर देता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है।

https://t.me/prasadi2aid1

● अर्जुन ने तपस्वियों को प्रणाम किया और सौभद्र मुनि के प्रिय स्तंभेश तीर्थ में स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने जैसे ही जल में प्रवेश किया, एक ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया।

महाबाहु अर्जुन ने बलपूर्वक ग्राह को खींचकर जल से बाहर निकाल लिया। जल से बाहर आते ही वह ग्राह, एक सुंदर स्त्री में बदल गया। उस स्त्री का रूप अत्यंत दिव्य था और उसने सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे। अर्जुन ने स्त्री से उसके विषय में पूछा और उसके ग्राह रूप के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की।

स्त्री ने बताया कि वह अप्सरा वर्चा है, जो अपनी चार सखियों के साथ एक वन में पहुंची, जहां एक ब्राह्मण अकेले बैठे तपस्या कर रहे थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वर्चा और उसकी सखियों ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए नृत्य और गायन किया। इससे ब्राह्मण का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर उन पांचों अप्सराओं को सौ वर्षों तक ग्राह बनने का शाप दे दिया। दुखी होकर अप्सराएं ब्राह्मण की शरण में गईं और क्षमा मांगने लगीं। तब ब्राह्मण ने कहा कि शाप तो भोगना होगा, किंतु एक दिन कोई श्रेष्ठ पुरुष उन्हें जल से बाहर निकालेगा और शाप से मुक्ति दिलाएगा। अप्सराओं को नारद ने बताया कि अर्जुन ही उन्हें मुक्त करेंगे। इसलिए वे समुद्र तट के उन तीर्थों में निवास करने लगीं। वर्चा ने अर्जुन से कहा कि अब आप हमें मुक्ति दें।

इसके बाद अर्जुन ने शेष चार तीर्थों में भी स्नान करके ग्राह रूपी सभी अप्सराओं को जल से बाहर खींचकर उनका उद्धार किया। सभी अप्सराओं ने अर्जुन को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से लौट गईं। ब्राह्मण ने अप्सराओं को उपदेश दिया था कि भगवान ब्रह्मा ने स्त्री और पुरुष के संयोग की व्यवस्था सृष्टि के विस्तार के लिए की है। जो लोग धर्म के विरुद्ध इसे अपवित्र करते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। गार्हस्थ्य धर्म शास्त्रसम्मत हो, तो पुण्य देता है, अन्यथा पाप का कारण बनता है। ब्राह्मण ने अप्सराओं से यह भी कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और जो अपने मन, वाणी और इंद्रियों को वश में रखे, वही सच्चा तपस्वी है। जो स्त्री और संतान के मोह में पड़कर पाप करता है, वह नरक में जाता है। अप्सराओं को मुक्त करके अर्जुन ने मुनियों की आज्ञा का पालन किया और पुनः तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। इस प्रकार अर्जुन ने अपने साहस और धर्मनिष्ठा से अप्सराओं को ग्राह के शाप से मुक्ति दिलाई और धर्म की रक्षा की।

आप सभी को खुश नहीं रख सकते

अलोभः परमं वित्तम्
अहिंसा परमं तपः।
अमाया परमा विद्या
निरवद्या मनीषिणाम्॥

लोभ का अभाव ही सबसे बड़ा धन है, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना ही परम तप है और कपट-रहित सरलता ही विद्या का सर्वोत्तम रूप है। ऐसे गुणसंपन्न मनीषियों की विद्या सदा निर्दोष और प्रशंसनीय मानी जाती है। -आचार्य क्षेमेन्द्र विरचित दर्पदलन (3.152)

प्रस्तुति : शास्त्री कोसलेंद्रदास

लोगों को जरूरत से ज्यादा खुश करने की आदत कभी-कभी असुरक्षा के जाल में फंसा सकती है। मनोचिकित्सक मेग जोसेफसन कहती हैं कि मुसीबत में होने की कष्टदायक भावना आम बात है, और इसे दूर रखने के लिए कुछ लोग जो रणनीति अपनाते हैं, उसका नाम है-चापलूसी। जब हम खतरे का आभास करते हैं, तो हमारा तंत्रिका तंत्र तीन तरह से प्रतिक्रिया करता है-लड़ना, भागना या ठहर जाना। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चापलूसी करना तनाव की चौथी प्रतिक्रिया है।

जान्सी डन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

अपनी असुरक्षा के चलते लोगों की चापलूसी करना यदि आपकी आदत बन गई है, तो यह समझ लें कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते।

मनोवैज्ञानिक पीट वॉकर बताते हैं कि चापलूसी लोगों को खुश करने का चरम रूप है। मैंने जोसेफसन से तीन मुख्य बातें समझाने को कहा, जो लोगों को चापलूसी करने से रोकने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा, यह मत मानिए कि कोई नाराज है। इसके लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं: क्या मैं जो कहानी खुद को सुना रही हूं, वह पूरी तरह सच है? क्या इस व्यक्ति का व्यवहार असामान्य है या बस उसके संवाद करने का तरीका ही ऐसा है।

ऐसा नहीं है कि लोग आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। लेकिन रुककर खुद को याद दिलाना मददगार होता है कि आपका बेचैन मन अतीत में आपसे झूठ बोल चुका है। जोसेफसन कहती हैं कि जो लोग आदतन चापलूसी करते हैं, उनके लिए सीमाएं तय करना और 'न' कहना थोड़ा डराने वाला हो सकता है। इसलिए कम जोखिम वाली परिस्थितियों से शुरुआत करें। ध्यान दें कि आप कब लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जो आपके हृदय से नहीं निकल रही हैं।

अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह आपसे नाराज नहीं है, तो उसकी बात मान लीजिए। जोसेफसन कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर आपके सामने अपनी बात नहीं रखता, तो आपको उसे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदार और स्पष्ट संवाद किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यह मतभेद को मिटा देता है। अगर आप कोई योजना रद्द कर रहे हैं, तो कोई बहाना बनाने के बजाय ईमानदार रहें, ताकि सामने वाला नाराज न हो। यह तरीका थोड़े समय के लिए भले ही असुविधाजनक लगे, लेकिन हमारी बहुत ऊर्जा बचाता है और उन रिश्तों को मजबूत बनाता है, जिनकी हम सचमुच कद्र करते हैं। जोसेफसन कहती हैं कि हर किसी को खुश करना आपके वश में नहीं है। आपके वश में यह है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान कैसे लगाते हैं।

©The New York Times 2025

अध्ययन कक्ष

यू हैव ए न्यू मेमोरी

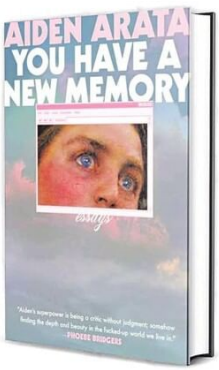

लेखिका : ऐडन अराता

प्रकाशक : ग्रांड सेंट्रल पब्लिकेशन
मूल्य : 2,530 रुपये (हार्डकवर)

सोशल मीडिया के शोर में कहीं खुद को न खो दें

इंटरनेट के अच्छे और बुरे अनुभवों के दौर में पिछले ही महीने प्रकाशित ऐडन अराता की पहली और बेस्टसेलर किताब कहती है कि मोबाइल और इंटरनेट कोई बुराई नहीं हैं, यह मनुष्य ही है, जो इसे अच्छा या बुरा बना देता है।

अपनी पहली और बेस्टसेलर किताब *यू हैव ए न्यू मेमोरी* में लेखिका ऐडन अराता ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के बीच के उस धुंधले हिस्से को उजागर करती हैं, जहां हमारी असली और आभासी (वर्चुअल) जिंदगी आपस में टकराती है। यह दरअसल, निबंधों की एक रोचक श्रृंखला और विज्ञान-सम्मत किताब है, जो कम उम्र से ही मोबाइल और सोशल मीडिया संस्कृति में उलझे रहने के दुष्परिणामों की पड़ताल करती है।

चूंकि, अराता खुद कैलिफोर्निया के एक समृद्ध परिवार से आती हैं, जहां उन्हें बचपन से कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया का साथ मिला, तो उन्होंने अपने इन्हीं अनुभवों के जरिये अपनी पीढ़ी की भावनाओं को पकड़ने की कोशिश की है। किताब में वर्तमान का एक तीखा विश्लेषण और भविष्य का एक दूरदर्शी आकलन किया गया है। उन्होंने डिजिटल दुनिया में यादों, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत बदलावों के गहरे पहलुओं को बेहद रोचक व सहज भाषा में इस किताब में प्रस्तुत किया है। उनके लिखे शब्द इतने तीव्र और जीवंत हैं कि वे पाठकों को कभी हंसाएंगे, तो कभी उनके रोंगटे खड़े कर देंगे और उनकी तनहा महसूस करने की भावना को कम करेंगे। यह किताब याददाश्त की अद्भुत दुनिया में ले जाकर यह समझ प्रदान करती है कि हम जो रील्स देखते हैं, वे किस तरह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं तथा किस प्रकार हम नई यादों के साथ अपने जीवन को पुनः संजो सकते हैं। अराता ने डिजिटल दुनिया की अपनी जटिल यादों को इतनी सहजता से स्पष्ट किया है कि सामान्य पाठक भी इसे आसानी से समझ सकता है। *यू हैव ए न्यू मेमोरी* पुस्तक खुद में बदलाव लाने की एक कड़ी है, जो यह सिखाती है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के युग में भी अपने दिमाग और यादों की शक्ति को समझकर हम अपने जीवन को किस तरह से नया आकार दे सकते हैं। इस किताब को वे लोग जरूर पढ़ें, जो सोशल मीडिया के शोर में खुद को खोया हुआ पाते हैं। किताब का हर निबंध आपको वास्तविक और आभासी दुनिया के बारे में कुछ नया सिखाएगा और दिल को छू जाएगा। ऐडन अराता की इस कृति को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा, मानो आप अपने सबसे समझदार दोस्त के साथ देर रात तक जाग रहे हों। उन्होंने किताब के जरिये यह साबित करने की कोशिश की है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली हथियार है और यदि उसे सही दिशा मिले, तो वह अपनी मनोवैज्ञानिक जंजीरों से मुक्त होकर नई खुशियों और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर आप ऑनलाइन रहने का अनुभव लेते हुए बड़े हुए हैं और पुराने इंटरनेट को याद करते हैं और उसे फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। लेखिका अपनी कुछ शरारतों के बारे में भी बताती हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने प्रयासों में ईमानदार हैं और यही चीज किताब को पठनीय बनाती है।

अभियान

किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यही है कि जो जरूरी है, उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें।
- स्वामी विवेकानंद, आध्यात्मिक गुरु

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

इक जरा-सी बारिश क्या आई,
सड़कें सब सरकारी हो गईं...

वो टूटी छतरी आज भी कोने में पड़ी है
जब भी नजर पड़ती है, भीग जाता हूं...

व्यापार के लिए सूरत पहुंचा 'हेक्टर'

ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज 'हेक्टर' आज के ही दिन सूरत के तट पर पहुंचा था। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। उस समय कोई नहीं जानता था कि व्यापार के लिए आई यह कंपनी करीब 200 सालों तक भारत पर राज करेगी।

16वीं शताब्दी में अंग्रेजों का व्यापारिक साम्राज्य केवल यूरोप तक ही सीमित था। उन्हें एक बड़े बाजार की जरूरत थी। भारत में व्यापार करने के लिए सन 1600 में शाही परिवार के संरक्षण में एक कंपनी बनाई गई। 24 अगस्त, 1608 को कंपनी का पहला जहाज सूरत के तट पर पहुंचा। इस जहाज के कैप्टन का नाम था हॉकिंस।

सूरत में पहले से ही पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। ऐसे में हॉकिंस के लिए वहां व्यापार की अनुमति प्राप्त करना आसान नहीं था। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो ने भारत के तत्कालीन शासक जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाकर धीरे-धीरे कंपनी ने शासन-प्रशासन में भी अपना दखल बढ़ाना शुरू कर दिया और एक व्यापारिक कंपनी से अलग प्रशासनिक कंपनी भी बन गई।

■ रश्मि सिन्हा, गाजियाबाद

झरोखा
24 अगस्त

सुर और साज के साथ संगीत के दो दीवाने

1969 में बनी फिल्म 'किस्मत' के गाने 'आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलें' की धुन संगीतकार ओ.पी. नैयर ने बनाई थी, जिसे आवाज दी थी गायिका आशा भोसले ने।

■ प्रीति दास, जम्मू

छायानट

ऐश्वर्या की एक फिल्म जो रिलीज नहीं हो पाई

ऐश्वर्या राय बच्चन लंबे समय से फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह फैन्स से हमेशा जुड़ी रहती हैं। कुछ दिनों पहले उनकी एक फिल्म का पुराना वीडियो अचानक से वायरल हुआ। यह वीडियो 1997 में शूट की गई उनकी फिल्म 'राधेश्याम सीताराम' का था। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ सुनील शेट्टी थे। दिलचस्प बात है कि यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। वीडियो में ऐश्वर्या ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने पर्पल कलर का लहंगा पहना है। वीडियो में ऐश्वर्या डांस के स्टेप्स सीख रही हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राय और सुनील शेट्टी लीड रोल में थे। वहीं, परेश रावल भी इस फिल्म में लीड रोल में थे। हालांकि यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई और इसको बंद करना पड़ा। हालांकि इसके बाद ऐश्वर्या ने कई हिट फिल्में कीं, जिनमें 'गुरु', 'हम दिल दे चुके सनम', 'जोश', 'देवदास', 'मोहब्बतें' और 'रोबोट' आदि शामिल हैं।

■ प्रियल राज, दिल्ली

ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से युवाओं को बचाने के लिए संसद में 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग' बिल पास हुआ है। अब ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगेगी और 'गेमिंग एप' डाउनलोड नहीं हो सकेंगे। इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग पर कानून का स्वागत

पैसे बनाने के झांसे से बचें

चिट्ठी 1

क्रिकेट से जुड़े ऑनलाइन गेम्स काफी लोकप्रिय हैं। इसके जरिए आज सट्टा एवं जुआ भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस तरह के गेम से खेलने वाले का न केवल नुकसान है, बल्कि उसे मानसिक टेंशन भी काफी रहती है। केंद्र सरकार ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए इस मानसून सत्र में संसद से एक विधेयक 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल' को पास कराया है। अब शीघ्र ही इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद बिल के कानून बनने पर पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग सकेगा। कानून बनने के बाद लोग गूगल प्ले स्टोर से ऐसे 'गेमिंग एप' डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर यह कानून दोनों सदनों से पास हो जाता है तो लोगों को इससे काफी फायदा होगा। इस प्रकार के गेमिंग एप को संचालित करने वालों के लिए एक करोड़ तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गेम में ट्रांजेक्शन सुविधा देने वालों को भी एक करोड़ के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद होगी। ऑनलाइन गेमिंग एप का विज्ञापन करने वाले स्टार एवं लोकप्रिय खिलाड़ियों के लिए भी दो साल की सजा एवं पचास लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। भारत सरकार का कहना है कि वह इस ऑनलाइन गेम के बदले में बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन देगी। सरकार का उद्देश्य समाज को बर्बादी से बचाना एवं लगातार हो रही आत्महत्याओं को भी रोकना है। इस तरह के ऑनलाइन गेम्स ड्रग्स की तरह हैं। एक बार लत लग जाने के बाद पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इस पर प्रतिबंध लगने के बाद देश की युवा पीढ़ी को शॉर्टकट से पैसे कमाने से मुक्ति मिल जाएगी।

■ मनमोहन राजावत 'राज', राजापुर

विरोध के बजाय विपक्ष का सहयोग जरूरी

चिट्ठी 2

कुछ राजनीतिक चरित्र भारतीय लोकतंत्र में मनमानी व्यवस्था के पक्षधर हैं, व्यवस्था में सुधार के कम। यदि ऐसा न होता तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए सभी राजनीतिक दल विशुद्ध ईमानदारी से देश को समृद्ध देखना चाहते तथा चुनाव व्यवस्था सुधारने के प्रति गंभीर प्रयास करते। मतदाता सूचियों में सुधार का विरोध करने के बजाय सतर्कता से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में सहयोग करते, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका ही न रहती।

सच तो यह है कि तथ्यों के विपरीत बयानबाजी करके कुछ लोगों का कार्य ही चुनाव सुधारों में व्यवधान डालना रह गया है। ऐसे लोग आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज करके उनको भ्रमित कर झूठ-फरेब की राजनीति करने पर आमादा हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद के आधार पर चुनावों में मानसिक संकीर्णता का परिचय देने वाले तत्व यदि चुनाव मैदान में धार्मिक गठबंधन का खेल खेलेंगे, तब उन्हें राष्ट्रवाद भला कैसे रास आएगा? ऐसे में और भी आवश्यक हो गया है कि देश की सांविधानिक संस्थाएं, बुद्धिजीवी और निरपेक्ष जनमानस मिलकर एक होकर, एक चुनाव और हर चुनाव में पुनर्रीक्षित मतदाता सूची के लिए गंभीर चिंतन करें, ताकि स्वार्थों की राजनीति करने वाले तत्वों के विघटनकारी मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके।

■ डॉ. सुधाकर आशावादी, मेरठ

'सुप्रीम' आदेश के बाद बदलाव की उम्मीद

चिट्ठी 3

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों को सड़कों से हटाने का फैसला सराहनीय है। पशु जन्म नियंत्रण नियम पर सभी राज्य सरकारों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने से होने वाली परेशानी और रेबीज से होने वाली मौतों पर चिंता जताई थी। कितनी हैरानी और चकित करने वाली बात है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को देश के आवारा कुत्तों की समस्या पर भी आदेश देना पड़ा। इसके बाद अनेक इलाकों से अवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम ले जाया गया।

पशु प्रेमियों ने इसे बेजुबान जानवरों पर अत्याचार बताते हुए विरोध किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज के टीकाकरण और नसबंदी के बाद कुत्तों को उन्हीं इलाकों में छोड़ने के आदेश दिए हैं, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। साथ ही यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना न दिया जाए। हालांकि आवारा कुत्तों से आमजन को होने वाली परेशानी पर राज्य सरकारों को चिंता नहीं, बल्कि चिंतन करना चाहिए।

मीडिया भी इस समस्या के लिए गंभीरता दिखाता है और इसे मुद्दा बनाकर सरकार और प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे गंभीरता नहीं दिखाते। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति में कितना बदलाव आता है।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

बरेली से सीमा गुप्ता, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी, लखीमपुर खीरी से सुरेश सौरभ, मेरठ से डॉ. वरेन्द्र टोंक, फिरोजाबाद से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मोहाली से अभिलाषा गुप्ता, सूरत से कांतिलाल मंडोत, उज्जैन से हेमा हरि उपाध्याय, देवास से हरिप्रसाद चौरसिया, इंदौर से अमृतलाल मारू 'रवि', रायपुर से संजीव ठाकुर।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

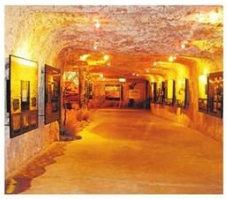

भीषण गर्मी में भी सर्दी का अहसास

ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा शहर है, जहां बने भूमिगत घर भीषण गर्मी में भी ठंडक का अहसास कराते हैं।

कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक अनोखा शहर है, जो अपनी भूमिगत बस्तियों और ओपल खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे दुनिया की 'ओपल राजधानी' कहा जाता है, क्योंकि विश्व के 70 प्रतिशत से अधिक ओपल यहीं से निकाले जाते हैं।

यह शहर 1915 में तब चर्चित हुआ, जब यहां पहली बार ओपल की खोज हुई। धीरे-धीरे लोग यहां बसने लगे। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यंत गरम और शुष्क है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। इस कठोर मौसम से बचने के लिए यहां के लोगों ने जमीन के नीचे घर, चर्च, होटल और यहां तक कि दुकानें भी बनाईं। इन भूमिगत घरों को 'डगआउट्स' कहा जाता है। यह ठंडी और आरामदायक जगह है, जहां लोग आसानी से रह सकते हैं।

ये घर पूरी तरह से फर्निश्ड होते हैं और इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद होती हैं। यही वजह है कि कूबर पेडी का वास्तुशिल्प दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह शहर रोमांचक अनुभव देता है। यहां आने वाले पर्यटक ओपल की खदानें देखने, भूमिगत संग्रहालयों और चर्चों का दौरा करने तथा अद्वितीय रेगिस्तानी परिदृश्य का आनंद लेने आते हैं।

कूबर पेडी का 'लूनर लैंडस्केप' यानी चंद्रमा जैसा परिदृश्य इतना मशहूर है कि कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहां की गई है, जैसे कि 'मैड मैक्स', 'क्रोकोडाइल डंडी' और 'प्रिंसेस बेवोन ऑफ द डेजर्ट'। संक्षेप में कहा जाए तो कूबर पेडी अपनी 'ओपल खदानों', 'भूमिगत जीवनशैली' और 'विशिष्ट रेगिस्तानी दृश्यों' के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह शहर कठिन हालात में भी मानव की जीने की इच्छा और अनुकूलन क्षमता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है।

■ प्रणय वर्मा, कुल्लू

https://t.me/AllNewsUpdate1

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 'सुपर बॉस' भारत

राजनीतिक प्रभाव के मामले में हम कई देशों से बहुत पीछे हो सकते हैं, आर्थिक ताकत के मामले में भी हमारी वर्तमान रैंकिंग कम हो सकती है, लेकिन जब बात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की होती है तो हम न केवल 'विश्व-गुरु' हैं, बल्कि 'सुपर बॉस' भी हैं।

जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो भाजपा और आरएसएस ने देश को 'विश्व-गुरु' बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा का जोर-शोर से प्रचार किया। गुजरते वक्त के साथ उनकी यह महत्वाकांक्षा पीछे छूटती जा रही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारी नाकामियां चाहे जो भी हों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के क्षेत्र में भारत अब सबसे शक्तिशाली 'खिलाड़ी' है। यह अलग बात है कि इससे क्रिकेट का कितना भला हुआ है?

मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 'प्रशासकों की समिति' के एक सदस्य के रूप में कुछ महीने बिताए थे। इस समिति का उद्देश्य भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गतिविधियों में अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाना था, लेकिन यह इसमें असफल रहा। मैंने देखा कि बीसीसीआई के अधिकारी दूसरे सभी क्रिकेट बोर्डों को अपने अधीन करना चाहते हैं। एक इतिहासकार होने के नाते यह बात मुझे चिंतित करती थी, क्योंकि मैं जानता था कि अतीत में गोरे देशों का साम्राज्यवादी अहंकार शायद ही कभी खेल के हित में काम आया हो। जैसा कि मैंने अपनी 2022 की पुस्तक 'द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट' में लिखा है- "मैंने बीसीसीआई में अपने सहयोगियों से कहा कि अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई आधिपत्य ने अक्सर दुनिया भर में क्रिकेट के बड़े हितों के खिलाफ काम किया है। मैंने तर्क दिया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैसा नहीं बनना चाहिए, जैसा अमेरिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए है, खुद नियम बनाना और जब चीजें उनके अनुसार न हो तो अंतरराष्ट्रीय संधियों की अवहेलना करना।"

ये चेतावनियां मुझे रॉड लायल की नई किताब 'द क्लब : एंपायर, पावर एंड द गवर्नेंस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट' पढ़ते हुए याद आ गईं। किताब की शुरुआत इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की कहानी से होती है, जिसकी स्थापना 1909 में शाही खनन के दिग्गज अबे बेली के दिमाग की उपज थी। अपने शुरुआती कुछ दशकों में आईसीसी पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे श्वेत प्रभुत्व वाले देशों का दबदबा था। इन देशों में खासकर इंग्लैंड यह तय करता था कि अंतरराष्ट्रीय खेल कैसे खेला जाएगा? नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी? दौरे और सीरीज कैसे तय किए जाएंगे। कानून और नियम कैसे बनाए जाएंगे? भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसे क्रिकेट खेलने वाले देशों के साथ उपेक्षा और यहां तक कि अवमानना का व्यवहार किया जाता था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यह एक साम्राज्यवादी और यहां तक कि नस्लवादी खेल व्यवस्था थी। 1946 तक आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व एक अंग्रेज करता था।

1950 और उसके बाद जब ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र बने तो उनके क्रिकेट प्रशासकों ने आईसीसी को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की। रॉड लायल बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान अक्सर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए मिलकर काम करते थे। 1965

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

में, आईसीसी में 'आई' शब्द 'इंपीरियल' से बदलकर 'इंटरनेशनल' हो गया और 1989 में 'कॉन्फ्रेंस' शब्द की जगह 'काउंसिल' शब्द ने ले ली। 2005 में आईसीसी का मुख्यालय लंदन से दुबई स्थानांतरित हो गया, जिससे संगठन उपमहाद्वीप में अपने नए शक्ति-आधार के और करीब आ गया।

अपनी किताब के आखिरी हिस्से में लायल लिखते हैं कि हाल के दशकों में भारत विश्व क्रिकेट के संचालन पर कैसे हावी हुआ? उनके विवरण में कुछ खामियां हैं, जैसे कि 1983 विश्व कप जीत के महत्व को नजरअंदाज करना और बिना किसी प्रमाण के 2011 विश्व कप फाइनल के बारे में 'फिक्स' होने का संदेह जताना।

इसके बाद भी बीसीसीआई की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के प्रति लायल का दृष्टिकोण निष्पक्ष है। वह लिखते हैं कि पूर्व बीसीसीआई और आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर शायद अकेले ऐसे शीर्ष प्रशासक थे, जिन्होंने बीसीसीआई के संकीर्ण हितों से आगे सोचने की हिम्मत दिखाई।

दिसंबर 2024 में भारतीय गृह मंत्री के बेटे आईसीसी के अध्यक्ष बने। जय शाह की पदोन्नति के बारे में लायल लिखते हैं- "एक समय में एमसीसी को विदेशी डेस्क माना जाता था, लेकिन आईसीसी अब एक अतिराष्ट्रवादी भारतीय राजनीतिक दल और उसकी कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षाओं का साधन बनता जा रहा है। यह विश्व क्रिकेट के 'टॉवर ऑफ साइलेंस' पर गिद्धों के मंडराने जैसा है। यहां 'राष्ट्रवादी' की जगह 'अंधराष्ट्रवादी' शब्द का इस्तेमाल अधिक सटीक है।"

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टोनी ग्रेग ने 2012 में ही चेतावनी दी थी कि बीसीसीआई के एमसीसी जैसा बनने का खतरा है। उन्होंने क्रिकेट की प्रमुख समस्याएं- जुआ, खराब प्रशासन और शक्ति का असमान वितरण जैसी बातें कही थीं और बताया था कि यदि भारत क्रिकेट की भावना को अपनाए और उसका पालन करे तो अधिकतर समस्याएं हल हो सकती हैं।

हालांकि यह उम्मीद गलत साबित हुई। बीसीसीआई ने आईसीसी पर कब्जा जमाने के लिए अपने वित्तीय प्रभाव का इस्तेमाल किया। आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन की स्थिति को देखते हुए लायल का निष्कर्ष है- "भारत का प्रभुत्व इस कारण है कि उपमहाद्वीप में क्रिकेट के प्रति अपार रुचि है। अतीत में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और उनके सहयोगियों का वर्चस्व अत्यंत शर्मनाक था। लेकिन यह तथ्य भारतीय पूंजीवाद की क्रूरता, कुछ राष्ट्रवादी राजनेताओं और कुलीन वर्गों द्वारा क्रिकेट को बंधक बनाए रखने को उचित नहीं ठहरा सकता।"

विडंबना यह है कि बीसीसीआई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्रशासकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि इससे दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट प्रशासक भी अलग-थलग पड़ गए हैं।

पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंत में जारी किया गया वीडियो, जिसमें जय शाह को विजेता दक्षिण अफ्रीकी टीम की तुलना में क्रिकेट से अधिक महत्वपूर्ण दिखाया गया था, यह प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। 1909 में अपनी स्थापना के बाद से ही आईसीसी षड्यंत्रों और अक्षमता का अड्डा रहा है। अब इसमें भ्रष्टाचार और द्वेष भी जुड़ गया है। अंग्रेजों के दौर में भी इसने क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत कुछ नहीं किया और भारतीय नियंत्रण में भी इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट की अच्छी सेवा की है या नहीं। सभी को मालूम है कि टेस्ट क्रिकेट खेल का सर्वोच्च रूप है, लेकिन तीनों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत जीत नहीं पाया है। पहले न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तीसरी बार तो भारत फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया। जहां तक वैश्विक क्रिकेट प्रशासन की बात है तो भारत पिछली शताब्दी में कई अलग-अलग चरणों से गुजरा है- पहले अंग्रेजों के वर्चस्व के प्रति सम्मान, फिर नेतृत्व की चाह और अंततः एक दबंग आधिपत्य।

राजनीतिक प्रभाव के मामले में हम अमेरिका, चीन और रूस से बहुत पीछे हो सकते हैं। आर्थिक ताकत के मामले में हमारी वर्तमान रैंकिंग 137वीं है। लेकिन जब बात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की होती है तो हम न केवल 'विश्व-गुरु' हैं, बल्कि 'सुपर बॉस' भी हैं।

मजबूत रिश्ते के आधार में शर्त नहीं होती

यह सच है कि अकेले जिंदगी नहीं कट सकती। जब लोग एक-दूसरे के करीब रहते हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है, पर कभी-कभी ये मतभेद बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं। ऐसे में रिश्तों को बचाने के लिए झगड़े सुलझाना बेहद जरूरी हो जाता है। मनमुटाव के बाद रिश्ते को संभालने का तरीका ही उसकी उम्र तय करता है। हमें पत्थरों से सीखना चाहिए- कठोर होते हुए भी उनके बीच की रिक्तता में दूब उग आती है। फिर क्यों दो मनुष्यों के विचारों की रिक्तता अलगाव की दीवार बन जाए? अक्सर स्नेह का एक छोटा-सा कार्य ही झगड़े को शांत कर सकता है। साथी का हाथ थामना या दिल से कहना कि "मुझे इस झगड़े से ज्यादा तुम्हारे करीब रहना पसंद है" काफी होता है।

डॉ. निर्मल जैन

खुला आकाश

रिश्तों को शर्तों पर नहीं जीया जा सकता। फर्क नहीं पड़ता पहल कौन करता है, जरूरी है साथ निभाना। छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। दोषारोपण के बजाय सौहार्द्रपूर्ण संवाद से झगड़े सुलझते हैं।

रिश्तों में हमेशा कोई एक सही नहीं होता। अक्सर दोनों की बातें सही होती हैं, बस समझने की जरूरत होती है। समझौते और बीच का रास्ता निकालने से रिश्ते में मिठास बनी रहती है। ध्यान रहे कि विवाद सुलझाते समय ऐसी बातें न कहें, जो भावनाओं को आहत करें। साथ ही सामने वाले की राय का सम्मान करना भी जरूरी है। एक अच्छा श्रोता बनकर शब्दों के साथ भावनाओं को भी समझें। झगड़े अक्सर इसलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हम सुनने से ज्यादा अपनी बात मनवाने पर जोर देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनें, समझें और फिर अपने विचार साझा करें। इससे सामने वाले को महत्व मिलने का अहसास होगा और विवाद जल्दी सुलझेगा।

गलत-फहमियों को दूर करने के लिए उनकी बातों को भी सुनें और अपनी बातों को भी उनके सामने रखें। स्वयं की गलती को स्वीकारें और माफी मांगें। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इससे रिश्ता और मजबूत होता है। माफी मांगने से सामने वाले को भी लगता है कि आप अपने रिश्ते को महत्व देते हैं। उनके दिल में आपके जो विचार हैं, वे प्यार में बदल जाएंगे। रिश्तों को शर्तों पर नहीं जीया जा सकता। फर्क नहीं पड़ता पहल कौन करता है, जरूरी है साथ निभाना। छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें और कई बार चीजों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। दोषारोपण के बजाय सौहार्द्रपूर्ण संवाद से झगड़े सुलझते हैं। अपनी गलती मानकर माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत करने का संकेत है। विवाद के तुरंत बाद समाधान ढूंढना जरूरी नहीं, क्योंकि उस वक्त भावनाएं उफान पर होती हैं। कुछ समय बाद शांत मन से लिया गया निर्णय ज्यादा तर्कसंगत होता है। मतभेद की जड़ को समझें और अपनों के लिए समय निकालें। यही मजबूत रिश्तों का असली आधार है।

वादाखिलाफी

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

जम्मू-कश्मीर में सितंबर, 2024 में चुनाव हुए, लेकिन आज तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है। यह निस्संदेह केंद्र सरकार की ओर से वादाखिलाफी है। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में टालमटोल के लिए भाजपा और राजग सरकार जिम्मेदार हैं। राजग में शामिल अन्य दल भी दोषी हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में सहभागी हैं।

यह व्यापक धारणा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 'निरस्त' करने के सरकार के कदम को सही ठहराया था। सरकार ने दावा किया कि 'निरस्तीकरण' को न्यायालय ने वैध ठहराया और कुछ विद्वानों ने इस दावे को सही मान लिया। यह गलत है, जैसा कि मैंने अपने एक आलेख (*'अंधेरगर्दी के भविष्य की ओर', जनसत्ता, 17 दिसंबर, 2023)* में बताया था। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'निरस्तीकरण' के मुद्दे पर इसके विपरीत निर्णय दिया था।

निरस्तीकरण अवैध, लेकिन...

सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को तीन कदम उठाए:

– संविधान के व्याख्या खंड (अनुच्छेद 367) में खंड (4) जोड़ने के लिए अनुच्छेद 370(1) का उपयोग किया;

– विस्तारित व्याख्या खंड का उपयोग कर अनुच्छेद 370(3) के उपबंधों को 'संशोधित' करने का दावा किया;

– 'संशोधित' अनुच्छेद 370(3) और उसके उपबंधों का उपयोग करके अनुच्छेद 370 को ही 'निरस्त' कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों कदमों को अस्वीकार्य और असंवैधानिक माना।

फिर भी, शीर्ष अदालत ने तर्क दिया कि *संविधान के सभी प्रावधानों को* जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए अनुच्छेद 370(1) के तहत शक्ति का प्रयोग वैध था और इसका अनुच्छेद 370 को 'निरस्त' करने के ***समान ही प्रभाव था।***

कानूनी स्थिति पर स्पष्टता : अनुच्छेद 370 को तथाकथित रूप से निरस्त करने का काम बहुत ही चतुराई से आधी-अधूरी तैयारी के साथ किया गया था। इसे अस्वीकार्य माना गया, लेकिन अनुच्छेद 370(1) के तहत संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने या विस्तारित करने को सही ठहराया गया।

मामला खत्म नहीं हुआ

फिर भी, मान लेते हैं कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विशेष दर्जा रद्द करने से जम्मू-कश्मीर के लोगों में नाराजगी है और केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के साथ ही मामला खत्म नहीं हुआ। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर (जो अपने विलय के बाद से एक राज्य था) को दो *केंद्रशासित प्रदेशों* में विभाजित कर दिया गया। क्या यह स्वीकार्य और वैध था? याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से इस सवाल पर भी विचार करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने इससे *इनकार* कर दिया, क्योंकि *केंद्र सरकार ने दलील दी कि वह जम्मू-कश्मीर (लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को छोड़कर) का राज्य का दर्जा बहाल करने और वहां चुनाव कराने का इरादा रखती है।* इस दलील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने इस सवाल के कानूनी पहलू को 'खुला' छोड़ दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय-सीमा तय की। जम्मू-कश्मीर में सितंबर, 2024 में चुनाव हुए, लेकिन आज तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है। यह निस्संदेह केंद्र सरकार की ओर से वादाखिलाफी है।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में टालमटोल के लिए भाजपा और राजग सरकार जिम्मेदार हैं। राजग में शामिल अन्य दल भी दोषी हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में सहभागी हैं।

नैशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने चुनाव जीतने के बाद 16 अक्तूबर, 2024 को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई। स्वाभाविक है कि एनसी सरकार चलाना चाहती थी और लोगों को उनकी प्रतिनिधि सरकार देना चाहती थी, जो जून 2017 से नकार दी गई थी। संभवतः, रणनीतिक कारणों से नैशनल कांफ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को लेकर मुखर नहीं हो पाई। यह मांग जोरदार तरीके से नहीं उठने पर केंद्र सरकार ने मान लिया कि राज्य का दर्जा बहाल होना जम्मू-कश्मीर के लोगों की प्राथमिकता नहीं है। जबकि, राज्य के दर्जे से वंचित होने की पीड़ा वहां के लोगों का प्रमुख मसला है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले दस माह में जो भी कार्य किए हों, पर वह लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई है। पीछे मुड़कर देखने पर नैशनल कान्फ्रेंस को यह एहसास हो सकता है कि राज्य के दर्जे पर मुखर न होकर उसने एक रणनीतिक गलती की थी।

पहलगाम और राज्य का दर्जा

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मेरा मानना है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के अलावा भारत में भी स्थानीय आतंकवादी मौजूद हैं। कौन कहां हमला करता है और समूह किसी हमले में सहयोग करते हैं या नहीं, यह घटना और अवसर पर निर्भर करता है। पहलगाम में एनआइए ने दो भारतीयों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर तीन पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह दी थी। आपरेशन सिंदूर के बाद और 28-29 जुलाई, 2025 को एक मुठभेड़ में तीन विदेशी आतंकवादियों को मार गिराने के उपरांत ऐसा लगता है कि सरकार ने पहलगाम की घटना पर से पर्दा हटा दिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को लेकर पूरी तरह से चुप्पी है। क्या वे अभी भी हिरासत में हैं या उन्हें रिहा कर दिया गया है और मामला बंद कर दिया गया है? यह एक रहस्य है।

मगर लोगों को याद है। उन्हें इस बात का स्मरण है कि राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा नहीं हुआ है। जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस वादे को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, तो न्यायालय ने कुछ मौखिक टिप्पणियां कीं कि पहलगाम में जो हुआ, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को और भी निराश कर दिया होगा। अगली सुनवाई लगभग आठ हफ्तों में निर्धारित की गई है।

मेरे विचार से, सर्वोच्च न्यायालय को इससे संबंधित कानूनी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के उतार-चढ़ाव से कानून के अनुसार न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए। कानूनी मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया, जबकि यह मुद्दा अदालत में किए गए वादे पर ही आधारित है। यह वादा बीस महीनों में पूरा नहीं हुआ है। अब विकल्प यह है कि वादे को तुरंत पूरा करने का आदेश दिया जाए या व्यापक कानूनी मुद्दे पर फैसला सुनाया जाए। मेरा मानना है कि संवैधानिक न्यायालय न्याय करेगा।

विरासत की राजनीति

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

अगर राजीव असली राजनेता होते तो प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वे उन जरूरी आर्थिक सुधारों को लाते जो 1991 में नरसिंह राव लाए थे। राजीव की समस्या यह थी कि अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक पंडितों के बदले उन्होंने अपने करीबियों में दोस्त रखे। काबिलियत से ज्यादा वफादारी को महत्त्व दिया। इसलिए ऐसे लोग जिनको देश की सेवा से ज्यादा पैसे बनाने का लालच था, वही दिखने लगे प्रधानमंत्री के करीबियों में।

राजीव गांधी जीवित होते तो पिछले सप्ताह वे अपना 80वां जन्मदिन मनाते। दिल्ली में तो यह दिन खूब तामझाम से मनता। कांग्रेसियों की भीड़ जमा होती और अखबारों में उनकी तारीफ में बड़े-बड़े इश्तिहार छपते। दिल्ली के सरकारी गलियारों में लोग इकट्ठा होते उनकी शान में कसीदे पढ़ने। कितना बदल गया है जमाना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनका जन्मदिन आम दिनों की तरह ही गुजरा दिल्ली में।

निजी तौर पर मेरे लिए कई पुरानी यादें ताजा हुईं। याद आया किस जोश से इस देश के लोगों ने 1984 वाले लोकसभा चुनाव में उनको अपना प्यार, अपनी संवेदना और अपने वोट दिए थे। मैं उस चुनाव में मध्य प्रदेश में थी और उस दिन ग्वालियर में थी, जब एक विशाल आमसभा को उन्होंने संबोधित किया था माधवराव सिंधिया के साथ। रात ठंडी थी, मैं आम लोगों के बीच ठिठुरती खड़ी थी मैदान में और मेरे आसपास जितने भी लोग थे, उनसे पता लगा कि उनमें भारत के लिए एक नए दौर की उम्मीद थी कि अब वास्तव में उनके जीवन में समृद्धि आने वाली है। इंदिरा गांधी की हत्या को भुला चुके थे लोग इसलिए कि उनके दौर में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की नालायकी से, लोग तंग आ चुके थे।

राजीव गांधी का शासनकाल बहुत बुरे दिनों से शुरू हुआ था। उनके प्रधानमंत्री बन जाने के कुछ घंटे बाद सिखों का जनसंहार सुनियोजित तरीके से करने लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सब खबरें जगजाहिर हैं कि मुर्दाघर भर गए थे और लाशों को जलाया गया था, उन्हीं सड़कों पर जहां सिखों को इंदिरा गांधी के चाहने वाले और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने मारा। इस संहार के हफ्तों बाद भोपाल में उस जहरीली यूनियन कार्बाइड फैक्टरी ने दो दिसंबर की आधी रात अपना जहर फैलाया सोती हुई बस्तियों पर, जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों में तीन हजार से पांच हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। फैक्टरी के अमेरिकी मालिक को राजीव सरकार की सहमति से चुपके से वापस अमेरिका भेज दिया गया।

मगर इस देश की आम जनता ने इन दोनों त्रासदियों के बावजूद राजीव को दिल से माफ ऐसा किया कि उनको लोकसभा में 414 सीटें देकर जिताया। विपक्षी दलों का इतना बुरा हाल हुआ इस चुनाव में कि महारथियों को पटक दिया मतदाताओं ने। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी को सिंधिया ने हराया और इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने। यानी राजीव गांधी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि देश की शक्ल बदल सकते थे। ऐसा न हुआ अगर, तो दोष उनका अपना है, लेकिन उनके लिए इतना प्यार था कि उनकी हत्या के बाद न सिर्फ उनकी पत्नी को देश का अघोषित प्रधानमंत्री बनने दिया 2004 से लेकर 2014 तक, बल्कि बाद में उनके दोनों बच्चों को भी संसद तक पहुंचाया।

इस परिवारवाद के अलावा राजीव की राजनीतिक विरासत के बारे में सोचने बैठो, तो एक गहरी उदासी महसूस हुई इसलिए कि अगर राजीव असली राजनेता होते तो प्रधानमंत्री बन जाने के फौरन बाद वे उन जरूरी आर्थिक सुधारों को लाते जो 1991 में नरसिंह राव लाए थे। राजीव की समस्या यह थी कि अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक पंडितों के बदले उन्होंने अपने करीबियों में दोस्त रखे। काबिलियत से ज्यादा वफादारी को महत्त्व दिया। इसलिए ऐसे लोग जिनको देश की सेवा से ज्यादा पैसे बनाने का लालच था, वही दिखने लगे प्रधानमंत्री के करीबियों में।

कुछ ऐसे कांग्रेसी हैं जो कहते फिरते हैं आज भी कि राजीव कंप्यूटर क्रांति लाए थे भारत में। सच यह है कि राजीव के दौर में कंप्यूटर विदेश से लाना इतना मुश्किल था कि इन्फोसिस जैसी कंपनियों को एक साल से अधिक लगता था एक कंप्यूटर लाने के लिए। भारतीय छात्र भी जब अमेरिकी विश्वविद्यालय से घर आते थे छुट्टियों के लिए, तो रोके जाते थे हवाईअड्डे पर कई घंटों तक अगर उनके पास कंप्यूटर होते।

राजनीतिक बदलाव की बात करें, तो कहना पड़ेगा कि यह न होने के बराबर हुआ राजीव के शासनकाल में। असम में अशांति को शांति में बदला था उन्होंने एक समझौते के जरिए, लेकिन कश्मीर और पंजाब में वही हिंसा और अशांति देखने को मिली, इसलिए कि राजीव के करीबियों में ऐसे लोग थे जिनको मालूम तक नहीं था कि इन राज्यों में अशांति के कारण क्या हैं। समाधान तो दूर की बात। इन सब असफलताओं के बावजूद यह कहना पड़ेगा मुझे कि राजीव अपने बच्चों से कहीं अधिक काबिल थे और उनमें वह संजीदगी और ठहराव था जो उनके बच्चों में नहीं दिखता है।

उल्टा जब भी राहुल गांधी किसी गंभीर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हैं या यात्रा पर निकलते हैं जैसे इन दिनों बिहार में निकले हुए हैं, तो उनके भाषण, उनकी बातें इतनी बचकानी होती हैं कि गंभीरता से लेना मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी से तकरीबन सारे काबिल नेता छोड़ कर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। उनके करीबियों में रह गए हैं सिर्फ ऐसे लोग, जिनकी खूबी है खुशामद करना। उनकी बहन उनसे अच्छे भाषण जरूर दे लेती हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आसपास इकट्ठा किए हैं ऐसे लोग जिनकी सबसे बड़ी खूबी है चमचागीरी।

नतीजा यह कि राजीव गांधी के बच्चे अभी तक अपना संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में अनुमान लगाया जाता है कि कांग्रेस पचास से ज्यादा चुनाव हारी है। इस बात को आज छिपाने की कोशिश हो रही है 'वोट चोर' का नारा देकर। इससे पहले खूब हल्ला मचा था ईवीएम को लेकर और हाल में संविधान बचाने का नारा देकर। अफसोस कि राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत अगर है कोई, तो यही कि परिवारवाद की जड़ों को उन्होंने मजबूत किया।

औपनिवेशिक छाया से मुक्ति

संदर्भ

राकेश सिन्हा

अंग्रेज जब भारत से गए, तब देश में पचास फीसद से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। महात्मा गांधी ने दो मार्च, 1930 को वायसराय लार्ड इरविन को पत्र लिखकर उनका विरोध किया था। तब भारतीयों की आय तो दो आना प्रतिदिन थी, मगर वायसराय के प्रत्येक दिन का वेतन सात सौ रुपया था। महात्मा गांधी उसे कम करने की गुहार लगाते रहे। मगर आजादी के बाद गांधी और गरीब दोनों किस तरह भुला दिए गए, इन घटनाओं से पता चलता है।

आजादी के सात दशक बाद हम अंग्रेजी हुकूमत की संस्कृति और संरचना से बाहर निकलने का संकल्प एवं प्रयास कर रहे हैं। इतना वक्त क्यों लगा? यह प्रश्न गैरवाजिब नहीं है। यह इसलिए कि भारत अपनी प्रकृति से विचारवान राष्ट्र है। यहां के लोग स्वभाव से परिवर्तनशील और वैचारिक रूप से साहसी होते हैं। भारत के इतिहास में अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ रचनाओं का सृजन हुआ। 'रामचरित मानस' और 'दास बोध' इसके उदाहरण हैं। भारत की आजादी के आंदोलन का चरित्र भी अन्य औपनिवेशिक देशों से भिन्न था। सबका लक्ष्य तो देश की स्वतंत्रता था, पर ऐसा करने में लोगों के मस्तिष्क में स्वतंत्रता संग्राम और सहमति-असहमतियों के बीच ताला नहीं लगा था। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का काल वैचारिक विविधता का संगम था। इन कारणों से यह अस्वाभाविक नहीं है कि देश के स्वतंत्र होते ही औपनिवेशिकता के संकेतों, छाया और संस्कृति से मुक्ति का अभियान पिछले कुछ वर्षों तक शुरू नहीं हो पाया!

सवाल है कि स्वतंत्र होते ही देश का नेतृत्व करने वालों को इस नैतिक जिम्मेदारी का अहसास क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर 'फ्रैंज फेनो' देते हैं। वे औपनिवेशिक प्रभाव और दासता से मुक्ति का विश्लेषण करने वाले गंभीर चिंतकों में एक हैं। उपनिवेशवाद अपने विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों में अपने जैसा बोलने वाला, अपने जैसा सोचने वाला और अपनी संस्कृति का अनुकरण करने वाला कुलीन तैयार करता है। वही देश की स्वतंत्रता के बाद औपनिवेशिक संस्कृति का संरक्षक बन जाता है। यही भारत में भी हुआ। इतिहास में कभी-कभी ऐसे मोड़ भी होते हैं, जब संघर्ष करने वाले आदर्श के हिमायती और सही सोच रखने वाले किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। वे परिस्थितियों से लड़ने का साहस खो देते हैं और मूकदर्शक की भूमिका में चले जाते हैं। भारत में वर्ष 1947 के बाद यही हुआ।

अंग्रेज जब भारत से गए, तब देश में पचास फीसद से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। महात्मा गांधी ने दो मार्च, 1930 को वायसराय लार्ड इरविन को पत्र लिखकर उनका विरोध किया था। तब भारतीयों की आय तो दो आना प्रतिदिन थी, मगर वायसराय के प्रत्येक दिन का वेतन सात सौ रुपया था। महात्मा गांधी उसे कम करने की गुहार लगाते रहे। मगर आजादी के बाद गांधी और गरीब दोनों किस तरह भुला दिए गए, इन घटनाओं से पता चलता है। 30 अगस्त, 1948 को संविधान सभा में बी दास ने पूछा था कि क्या गवर्नर जनरल का प्रतिमाह वेतन बीस हजार से दस हजार करने का आग्रह किया गया है, तब जवाहर लाल नेहरू का उत्तर था- 'ऐसे आग्रह करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।' मांटटबेटन को वेतन के अतिरिक्त अस्सी हजार रुपए का भत्ता मिलता था। यह भारत के लोगों की प्रति-व्यक्ति आय से दो हजार गुना अधिक था।

संविधान सभा के एक अन्य सदस्य एचवी कामथ ने नेहरू सरकार की 'उदारता' पर सवाल खड़ा किया था। जून, 1948 में मांटटबेटन ब्रिटेन वापस चले गए। वे नए वित्तीय वर्ष में मात्र तीन महीने पद पर रहे, लेकिन पूरे वर्ष के भत्ते की राशि डकार गए। कामथ दुखी थे तो जवाहर लाल नेहरू उसका औचित्य बताने में लगे थे कि मांटटबेटन ने तीन महीने तक भारत का गहन दौरा किया। भुखमरी से जूझ रही जनता इन सबसे अनभिज्ञ थी। वह नेतृत्व का जय-जयकार करने में आनंदित थी। मांटटबेटन के सहयोगियों की जेब भी भरी जा रहा थी।

बी दास ने लोकसभा में जो कहा था, वह इस प्रकार है- 'मैं किसी बहस करने वाले समूह में नहीं बैठा हूं। मैं सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य के नाते बोल रहा हूं, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है।' सरकार उनकी बातों से निःशब्द थी। सरकार ने कमांडर-इन-चीफ जनरल बुसर को सुरक्षा बलों का इतिहास लिखने के लिए छह महीने देश में रोक लिया। उन्हें लाखों रुपए दिए गए, पर किताब नहीं छपी। बुसर वही शख्स थे, जिन्होंने हैदराबाद में भारतीय सेना को भेजने में जानबूझकर विलंब किया था।

एक और नाम है- मैकेंजी। उन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय सेना की भूमिका पर पुस्तक लिखने के लिए लाखों रुपए दिए गए। यह पुस्तक भी कभी प्रकाशित नहीं हुई। यह मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाने जैसा था। रामधारी सिंह दिनकर ने सत्ता के इसी रसूख के कारण दिल्ली को 'रेशमी नगर' कहा था। इसी रेशमी नगर में मांटटबेटन वर्ष 1956 में भ्रमण करने आ रहे थे। भारत सरकार ने सांसदों को पत्र भेजकर आग्रह किया कि वे हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए जाएं। तब मांटटबेटन न तो राष्ट्राध्यक्ष थे, न ही किसी संसद के सभापति। प्रश्न तो उठाए गए, पर ऐसे वाजिब प्रश्न निष्प्रभावी हो जाते हैं, जब लोग स्वयं अपनी चेतना को मारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तब दास, कामथ और त्यागी का सत्यान्वेषण बौद्धिक विलास बनकर रह गया था। इसीलिए महावीर त्यागी सच बोलकर भी अपराध बोध में चले गए। त्यागी ने मांटटबेटन को गवर्नर जनरल बनाए जाने पर संविधान की भूमिका का सवाल उठाया था। सदन के सामने उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव कभी आया ही नहीं, कभी इस पर विचार हुआ ही नहीं। फिर अनुमोदन करने की बात कितनी उचित थी? महावीर त्यागी को भी कहना पड़ा कि उन्हें बना लीजिए, पर साथ ही कहा कि 'सदन की ओर से' शब्द हटा दीजिए। मगर वे शब्द नहीं हटे। इसे कहते हैं मांटटबेटननामा।

घमासान के बीच

बाखबर

सुधीश पचौरी

संसद न चलनी थी, न चलने दी गई। अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद सिर्फ तीस फीसद चली। यह 'नियोजित व्यवधान' के कारण हुआ। सत्र के लिए कुल 222 करोड़ खर्च हुए, लेकिन काम एक तिहाई हुआ। एक सांसद कहिन कि संसद न चलने देने के लिए सत्ता-विपक्ष बराबर के दोषी हैं।

पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संघ की जैसी प्रशंसा की, उसे लेकर चैनलों में देर तक बहस होती रही। एक कहिन कि लालकिले से संघ का नाम नहीं लेना था, तो दूसरा कहिन कि संघ के 'कार्यकर्ता' से यही उम्मीद थी, तीसरा कहिन कि आजादी की लड़ाई में संघ ने भाग नहीं लिया तो चौथा बोला कि उस पर कई बार पाबंदियां लगीं...। आरोपों के जवाब में संघ पक्ष गर्व से बोला कि बड़े-बड़े संगठन निपट गए, लेकिन संघ बना रहा और बढ़ता रहा। जब-जब राष्ट्र पर संकट आया, संघ ने उबारा। नेहरू ने परेड में बुलाया, इंदिरा ने सावरकर की तारीफ की... प्रणव मुखर्जी संघ के कार्यालय गए..।

उधर, संसद न चलनी थी, न चलने दी गई। अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद सिर्फ तीस फीसद चली...यह 'नियोजित व्यवधान' के कारण हुआ। सत्र के लिए कुल 222 करोड़ खर्च हुए, लेकिन काम एक तिहाई हुआ..। एक सांसद कहिन कि संसद न चलने देने के लिए सत्ता और विपक्ष बराबर के दोषी हैं। अगर संसद में बहस नहीं करनी, तो चुन कर क्यों आते हैं। बहसें सुन कर लगता है कि सत्ता की जिम्मेदारी है संसद चलाना जबकि विपक्ष का काम है 'ब्रेक' लगाना..। लेकिन विपक्ष पर ऐसे आरोप हमें कुछ जंचते नहीं, क्योंकि संसद 'भवन' में न सही, विपक्ष की संसद के बाहर तो चलती ही है। विपक्ष के सांसद 'भवन' छोड़ सड़क पर धूप-ताप सहते अपने ऐसे पोस्टरों-नारों से 'बहस' चलाते तो हैं कि 'एसआइआर' बंद करो... वोट चोरी बंद करो..। फिर कहां संसद भवन की एसी की हवा और कहां संसद के गेट के बाहर खुली हवा और सावन-भादो की फुहारें..। फिर सांसदों का अपनी युवावस्था में लौट कर सड़क की राजनीति करने का अभ्यास करना..।

ऐसे ही घमासान के बीच, विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए अपना पक्ष रखा और मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि आयोग किस तरह 'पारदर्शिता' से और नियमानुसार काम करता है कि आरोप 'स्वयं प्रमाण' हैं कि 'एसआइआर' क्यों जरूरी है... 'एसआइआर' से ही मालूम हुआ कि बिहार में इतने लाख वोट 'जाली' हैं... कि अगर किसी को शिकायत है, तो वह आयोग को लिख सकता है। महाराष्ट्र में 'वोट चोरी' का आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेता से उन्होंने कहा कि वे सात दिन में हलफनामा भर कर शिकायत करें, नहीं तो देश से माफी मांगें।

विपक्ष के एक नेता ने इसका यही जवाब दिया कि मैं जन प्रतिनिधि हूं। मेरा कहा ही मेरा 'हलफनामा' है..। यानी 'मेरा वचन गीता की कसम', कि 'तू डाल-डाल तो मैं पात-पात...' और, फिर वही 'धमकी' कि हम सत्ता में आए तो देख लेंगे...तलवारें तनी हैं..। 'चोरी हो गई...वोट की चोरी हो गई'...वाला 'नारा' अब समूहगान में बदल कर सीधा हो गया दिखता है!

विपक्ष के एक नेता तो अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' में अब सीधे नारे लगवाने लगे हैं। अब बच्चा भी कहने लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़... फिर एक नाम लेकर कहते दिखा कि फलां वोट चोर..।'

बहस में एक चर्चक क्षुब्ध होकर कहता दिखा कि चुनाव आयोग क्यों नहीं ऐसे आरोप लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराता? कई दूसरे भी कसमसाते दिखे कि सत्ता पक्ष ऐसे आरोपों पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता..। आती खबरों और बहसों में पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। एक-दूसरे को 'वोट चोर' कहते रहते हैं, तो दूसरे, 'वोट चोर कहने वालों' पर प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि आप पचास बरस तक जीते या कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में जीते तो क्या 'वोट चोरी' से जीते... अतीत में हम हारते रहे, लेकिन हमने कभी 'वोट चोरी' की शिकायत न की। बिहार में अपनी आसन्न हार को देख ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जबकि हमारा संगठन है, हम काम करते हैं। जनता वोट देती है, इसलिए खिसियाए हैं।

और अब तो हालात ये हैं कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद कहने लगे हैं कि अगर हमारी बात गलत है तो आपने भी वही मुद्दा क्यों उठाया। वोट चोरी के आरोपों की जांच होनी चाहिए। हम तैयार हैं, आप भी इस पर तैयार हो जाएं। ऐसी ही बहस में एक ने कहा कि भइए! ये तब तक शांत नहीं होने के, जब आप इनको सारे चुनाव जितवा कर गद्दी नहीं सौंप देते। चोर-चोर और चोरी-चोरी के ऐसे 'चोर सीजन' में ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब वोट चोर..!

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संन्यास से सिंहासन की डगर पर योगी का दम और उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम

सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए

संपादक की कलम से

डा. देवेंद्र सिंह
प्रधान संपादक

संन्यास से सिंहासन का दुर्गम सफर और मठ की आराधना से लेकर सत्ता की दहलीज को लांघना यह किसी अजूबे से कम नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और बीमारू राज्य की बागडोर थामने वाले तपस्वी योगी आदित्यनाथ ने अपने अब तक के आठ साल के कार्यकाल में ऐसा धमाल मचाया कि उनके तमाम फैसले देशभर के लिए नजीर बन गए। एक संत के लिए इतने बड़े राज्य की सत्ता किसी संग्राम से कम नहीं रही, लेकिन जिस सलीके से सीएम योगी अदित्यनाथ ने अपने धर्म और शास्त्र की मर्यादा के साथ सियासी संघर्ष छेड़ा उससे हर कोई हैरान रह गया। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बात कहनी पड़ी कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए हैं उपयोगी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज था जिसको महाराज ने मटियामेट कर डाला। ऐसे में योगी राज के संदर्भ में निष्पक्ष आंकलन किया जाए तो कानून व्यवस्था के लिहाज से तमाम दावे शत-प्रतिशत सत्य प्रतीत होते हैं।

योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले आठ वर्षों से यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। इस दिशा में उठाए गए सख्त कदमों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक नई दिशा दी है. इसके लिए सीएम योगी ने न केवल पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से सुसज्जित किया, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा किया. पिछले आठ वर्षों की सख्त नीति और अभियान का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाने लगा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आजादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश की गिनती व पहचान एक असुरक्षित और बीमारू राज्य के रूप में होती रही है। यह छवि आधारहीन नहीं थी, इसके अनेक कारण रहे हैं। एक समय था जबन उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था और बाहुबिलयो व गैंगवार ने राज्य की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। आलम ये था कि निरंकुश अपराध से आम आदमी में भय का महौल था, खासकर व्यापारियों व महिलाओं में और असुरक्षा व्याप्त थी। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में यहां से भारी संख्या में लोगों का पलायन हो गया, जबकि बहुत सारे लोग पलायन के बारे में सोच रहे थे। लेकिन योगी सरकार के सत्तासीन होने के साथ राज्य से पलायन पर काफी हद तक रोक लगी है। यहां तक कि पलायन कर गए काफी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश वापस भी आए हैं। कैराना क्षेत्र इसका सर्वाधिक उपयुक्त उदहारण है। इस छवि का अन्य अनेक हानियों के अलावा मुख्य नुकसान यह हुआ कि पूर्व में यूपी में कोई विशेष निवेश नहीं हुआ, उद्योग-धंधे वांछित रूप से पनप नहीं पाए और विकास की दौड़ में यह राज्य अपेक्षाकृत पिछड़ेपन का शिकार रहा। सौभाग्यवश शपथ लेने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति जीरो टोलरेंस नीति अपनाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान छेड़ दिया। अपराध

रोकने के लिए योगी सरकार ने असंख्य कदम उठाए व अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया है।

उत्तम प्रशासन, निवेश और रोजगार के वादे पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जादुई ढंग से सत्ता में अपनी पैठ बनाई थी और चुनाव जीत कर आई थी। कामकाज संभालने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में अथक प्रयास किए। इनमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश समेत अन्य अधिकांश प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था में सुधार, भू व खनन माफिया, अवैध बूचड़खानों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक, मंत्रियों व विधायकों को संपत्ति घोषित करने के निर्देश देने सहित अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कार्य शामिल हैं। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस की छवि में सुधार के तहत 40 से अधिक नए पुलिस थाने, एक दर्जन से ज्यादा नई पुलिस चौकियां और लगभग डेढ़ लाख नई पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की गई है। योगी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एक गंभीर समस्या थी। योगी सरकार ने महिला अपराध रोकने के लिए रात्रि सुरक्षा कवच योजना, महिला सहायता डेस्क, गुलाबी बूथ समेत गुलाबी बस सेवा आरंभ की। इन सभी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम राज्य में दिखाई भी देने लगा है।

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों का पुराना इतिहास रहा है। तब राज्य दंगों की आग में झुलसकर इसका खामियाजा भुगतता था। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दंगा मुक्त प्रदेश बनाने में प्रबल इच्छा शक्ति दर्शाई है और पिछले पांच वर्षों में यूपी में दंगे न होना निश्चित ही योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों दशार्ते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपराध तेजी से घटे हैं। दुष्कर्म के मामलों में उत्तर प्रदेश में 45 प्रतिशत की कमी आई है जो वर्ष 2016 में 3419 से घट कर वर्ष 2020 में 2317 हो गए। पुलिस के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होने से खाकी की हनक फिर पहले जैसी हो गई और अपराधी घुटनों के बल आ गए। आम आदमी के प्रति पुलिस का व्यवहार भी आज बदला नजर आता है, जिस कारण आम आदमी में सुरक्षा व पुलिस के प्रति विश्वास वापस आया है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निश्चित ही अभूतपूर्व दृरदष्टि, इच्छाशक्ति, दृढ़निश्चय और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

आंकड़े गवाह हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकारआने से पहले राज्य में कानून व्यवस्था का संकट था। उनके आने के बाद प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में 22 अपराधियों को मार गिराया गया, 20,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, और गैंगस्टर एक्ट के तहत 142 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। आज कानून व्यवस्था में राज्य ने लंबी छलांग लगाई है और प्रयागराज में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुआ महाकुंभ इसका बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर काम किया। मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, गरीबों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समेत कई योजनाओं से लाखों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। सरकार ने पंद्रह करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया।अन्य उपलब्धियों में सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने की योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की लगभग 60% आबादी को कवर किया गया, जिसमें 3.16 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को नई तकनीकों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़े। यूपी सरकार ने हवाई अड्डों का विकास भी किया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, वहीं अब 9 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय में 5 और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कार्य तेजी से चल रहा है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जारी है, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। हाल ही मानसून सत्र में सदन में डाक्यूमेंट विजन पर चौबीस घंटे चली ऐतिहासिक बहस उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम की एक और कहानी कह रही है।

अगर ऐसे में प्रख्यात कवि व गजलकार दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों का संदर्भ लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ की कर्मठ कार्यशैली इस अद्भुत रचना में साफ झलकती है।

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी
शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर छाए स्वास्थ्य संबंधी पोस्ट

नमी और तापमान में परिवर्तन त्वचा को पहुंचाते हैं नुकसान

सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी पोस्टों की भरमार है। उनमें से कई आम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। मौसम के बदलाव के कारण नमी और तापमान में परिवर्तन होते हैं, जो त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे बंद पोर्स, अधिक तेल स्राव और बार-बार फोड़े-फुंसियों का कारण बनते हैं। त्वचा देखभाल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, आहार का प्रभाव अक्सर नजरअंदाज रह जाता है। एक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. मधुमिता कृष्णन सुझाव देती हैं कि मानसून में वात और पित्त दोष को संतुलित करने के लिए ऐसे भोजन शामिल करें जिनकी प्रकृति मीठी और थोड़ा तैलीय हो। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और त्वचा की समस्याओं में सुधार होगा। वे पांच आयुर्वेद सुपरफूड्स की सलाह देती हैं, जिनमें पोषक तत्वों से भरपूर बादाम और त्रिदोष संतुलित करने वाला आंवला शामिल हैं, जो मुँहासों को कम करने और त्वचा को साफ-सुथरा रखने में मदद करते हैं।

बादाम, हल्दी, आंवला, नीम और लहसुन। बादाम मानसून के आहार के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं क्योंकि इनका स्वाद मुखरतः मीठा होता है। वे वात और पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करते हैं। थोड़े तैलीय होने के कारण ये त्वचा को अंदर से पोषण देने के लिए आदर्श हैं। इस प्रकार, वे बरसात के मौसम में संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रकाशित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी ग्रंथों के अनुसार, बादाम त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और त्वचा की चमक बढ़ा सकते हैं। रात भर भिगोकर खाने से वे पचने में आसान होते हैं और त्वचा को गहराई से पोषण प्रदान करते हैं। हल्दी-पीढ़ियों से यह स्वर्ण रंग की मसाला

अपनी एंटीबैक्टीरियल (जीवाणुरोधी) और एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन रोधी) गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह पाचन को बेहतर बनाए रखने में सहायक है और वात दोष को संतुलित करती है, जिससे त्वचा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हल्दी को नियमित भोजन में शामिल करने से मुँहासे और अन्य त्वचा संबंधी सूजन को कम किया जा सकता है।

यह संक्रमणों से लड़ती है, रक्त को शुद्ध करती है और त्वचा को स्वस्थ बनाती है। आंवला- आंवला, जो सभी त्रिदोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है और त्वचा को युवा, ताजगी से भरा तथा पोषित बनाए रखता है।

श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग : दारूकावन में भगवान शंकर का दिव्य अवतरण

रमाकांत पंत

भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से दसवां स्थान श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्राप्त है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ₹नागेश्वर₹ रूप का प्रतिक है, जो उन्होंने अपने परम भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए धारण किया था। शिवपुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण तथा अन्य अनेक धर्मग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से उल्लेख मिलता है।

राक्षस दारूक और दारूका की उत्पीड़न गाथा : प्राचीन समय में दारूक नामक एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था, जिसकी पत्नी दारूका देवी पार्वती की कृपापात्र थी। देवी के आशीर्वाद से वह अपनी इच्छानुसार वनभूमि को स्थानांतरित कर सकती थी। यह राक्षस दंपति अपने अनुयायियों के साथ पश्चिमी समुद्र तट के पास एक घने दारूकावन में निवास करते थे। वे संत-महात्माओं और यज्ञों का विध्वंस कर अधर्म को बढ़ावा देते थे। राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित जनता ने महर्षि और्व से शरण मांगी। धर्म की रक्षा के लिए महर्षि और्व ने उन्हें शाप दिया कि जो राक्षस धरती पर हिंसा करेगा या यज्ञों का विध्वंस करेगा, वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। इस शाप से भयभीत राक्षस समुद्र में जा बसे।

सुप्रिय की भक्ति और शिव का अवतरण : इसी काल में सुप्रिय

नामक एक धर्मात्मा वैश्य समुद्री यात्रा पर निकला। दारूक ने उसकी नाव पर आक्रमण कर सभी यात्रियों को बंदी बना लिया। कारागार में भी सुप्रिय ने शिव-भक्ति नहीं छोड़ी और अपने साथियों को भी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। जब दारूक को इसकी सूचना मिली, तो वह क्रोधित हो उठा और सुप्रिय की हत्या का आदेश दे दिया। परन्तु सुप्रिय निर्भय होकर शिव का जाप करता रहा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हुए। उनके साथ एक दिव्य मंदिर और उसमें प्रकाशित ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ।

राक्षसों का संहार और धर्म की स्थापना : भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र से दारूक, उसके सैनिकों और अस्त्र-शस्त्रों का नाश किया। इसके बाद उन्होंने वरदान दिया कि यह वन अब धर्मभूमि कहलाएगा, जहाँ चारों वर्णों के धर्मपालक जन निवास करेंगे, और राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इसी समय राक्षसी दारूका ने माता पार्वती की स्तुति कर अपने कुल की रक्षा की प्रार्थना की। पार्वती ने शिव से अनुरोध किया कि दारूका को उसकी शक्ति अनुसार राज्य संचालन का अधिकार मिले। शिव ने स्वीकार किया कि युग के अंत तक यह तामसिक व्यवस्था चलेगी, पर वे स्वयं भी इस वन में निवास करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे।

शिव का वरदान और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना : भगवान शिव ने घोषणा की कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनका दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कलियुग के अंत में वीरसेन नामक राजा शिव के दर्शन के बाद चक्रवर्ती बनेंगे। तभी से यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ और पार्वती जी ₹नागेश्वरी₹ कहलाईं। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है।

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रामाणिकता को लेकर मतभेद हैं। हालांकि, गुजरात राज्य में द्वारका के निकट स्थित दारूकावन क्षेत्र को सबसे प्रमाणिक स्थान माना गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के हिंगोली के पास अवढा गांव और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास जोगेश्वर तीर्थ में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने का दावा किया जाता है।

स्कंद पुराण में उत्तराखंड स्थित नागेश लिंग का वर्णन है, जबकि श्रीशिवमहापुराण दारूकावन को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की मूल भूमि मानता है।

चाहे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग किसी भी स्थान पर स्थित हो, उसकी महिमा अद्वितीय है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए जब भी प्रकट होते हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा यह सिखाती है कि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और धर्म की राह पर चलने वाले की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं।

नागेशं दारुकावने यह मंत्र आज भी शिवभक्तों की आस्था का केंद्र है।

बेजुबानों की दोस्त

शालिनी अग्रवाल अरोड़ा की करुणा भरी दुनिया

शिरोज खान

आज के समय में जब इंसान अपनी जिंदगी की दौड़ में इतना उलझ चुका है कि उसे दूसरों की तरफ देखने तक का वक्त नहीं मिलता, वहीं एक महिला हैं जो खुद तंगी की हालात में रहकर भी उन प्राणियों की जिंदगियाँ संवार रही हैं जिन्हें हम अक्सर ''मुसीबत'' कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह महिला शालिनी अग्रवाल अरोड़ा ग्राम आसपुर खुबचंद में रहतीं है, अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद घायल और असहाय जानवरों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी बनी हुई हैं।चाहे वह भूख से तड़पता कुत्ता हो, दुधंटना में घायल हुई गाय हो, या फिर बिजली की तार से घायल कोई बंदर जैसे ही ऐसी कोई खबर मिलती है, शालिनी जी पहले जाने वालों में से होती हैं।

वे न केवल जानवरों जिन्हें वह अपने बच्चे कहती हैं को खाना खिलाती हैं बल्कि उनका प्राथमिक इलाज भी करती हैं। अगर कहीं बड़ा मामला हो तो अपने संसाधनों से डॉक्टर बुला लाती हैं। उनका दिन अक्सर इसी सेवा से शुरू होता है। सुबह-सुबह वे बिल्लियों और कुत्तों को दूध और रोटी देती हैं।

दोपहर को गायों , भैंसों व अन्य बच्चो को चारा डालती हैं और शाम को कई बार घायल पक्षियों को पानी पिलाना और दवा देना उनका काम बन गया है। शालिनी अग्रवाल खुद आर्थिक रूप से बहुत सम्पन्न नहीं हैं, घर चलाने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके भीतर जानवरों के लिए जो प्रेम है वह किसी बाधा के आगे नहीं झुकता। कई बार ऐसा हुआ कि घर के खर्चों से कम करके उन्होंने दवा और भोजन जानवरों पर खर्च किया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी परे-रु39यानियों के बावजूद आप यह सब क्यों करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा ''अगर हम थोड़ी सी इंसानियत भी नहीं दिखा सकते, तो फिर जीने का मतलब ही क्या बचता है?''

आसपास के इलाकों के बच्चे उन्हें प्यार से 'जानवरों की डॉक्टर आंटी' कहते हैं और बुजुर्ग अक्सर उन्हें मोहल्ले की ''मदर टेरेसा'' का दर्जा देते हैं। जहाँ कहीं घायल जानवर दिख जाता है, लोग तुरंत फोन करके ~शालिनी जी को बुला लेते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि वे मदद के लिए जरूर आएँगी। वह कहती हैं ''जानवर बोल नहीं सकते, पर उनकी आँखें सब कह देती हैं।

ISSN 0969-9546 Copyright © Pioneer Publication Paid1

कैसे घटाएं परिधान क्षेत्र के कार्बन पदचिन्ह

सुमन दत्ता

परिधान क्षेत्र के इस विशाल पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए, कपड़ों और फैशन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू विकल्प प्रदान करते हैं; एक ओर, पर्यावरण-अनुकूल कपड़े चुनने का, और दूसरी ओर, लोगों को स्टाइलिश और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बने रहने का अवसर प्रदान करने का।

वैश्विक तापमान वृद्धि और विषाक्त अपशिष्ट से लेकर वायु प्रदूषण और जैव विविधता के ह्रास तक, कई पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही दुनिया के बीच, हममें से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि हमारे कपड़े और फैशन के विकल्प इन संकटों में कैसे योगदान करते हैं। अनुमानित 10 प्रतिशत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कपड़ा उद्योग से होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन और समुद्री नौवहन के संयुक्त उत्सर्जन से भी अधिक है। कपड़ा उद्योग जल क्षरण के मामले में भी तीसरे स्थान पर है। चिंताजनक रूप से, परिधान अपशिष्ट भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगरपालिका अपशिष्ट स्रोत है, जिसे विघटित होने में 100 वर्ष तक का समय लगता है। कपड़ों के उत्पादन, उपभोग और निपटान का पूरा चक्र एक बड़ा पारिस्थितिक पदचिह्न छोड़ता है।

परिधान क्षेत्र के इस विशाल पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए, कपड़ों और फैशन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम कितनी बार अपनी अलमारी में सजे कपड़ों का जायजा लेने के लिए रुकते हैं? अगर हम अपने कपड़ों का हिसाब-किताब करें, तो यह संख्या हैरान करने वाली हो सकती है; और हमारी जरूरतों और खरीदारी की आदतों के बीच एक जबरदस्त विरोधाभास भी उजागर कर सकती है। भारत में, सांस्कृतिक समारोहों से लेकर शादी-ब्याह और जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत समारोहों तक, हर अवसर अपनी अलग स्टाइलिश भव्यता की माँग करता है। उपभोक्तावाद और तेज फैशन के दौर में, कई मौकों पर एक ही तरह के कपड़े पहनना एक सामाजिक अपराध जैसा लग सकता है, जिससे हमें लगातार नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। कपड़ों के इस निरंतर संग्रह से न केवल हमारी अलमारी में बेकार कपड़े जमा हो जाते हैं, बल्कि पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है।

पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, कम करें : चक्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू, एक ओर, पर्यावरण के अनुकूल कपड़े चुनने के विकल्प प्रदान करते हैं, और दूसरी ओर, लोगों को स्टाइलिश और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बने रहने की अनुमति देते हैं, साथ ही ढेर सारे कपड़े रखने की जरूरत को कम करते हैं। छंटाई, ग्रेडिंग, पुनर्चक्रण और पुनर्रचना जैसे चक्रीय फैशन सिद्धांत अपशिष्ट को कम करके पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करते हैं। पुनर्चक्रण में, प्रयुक्त वस्त्रों से निकाले गए रेशों और प्लास्टिक की बोतलों से पॉलिएस्टर का उपयोग नए कपड़े बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत सहित प्रमुख वैश्विक ब्रांड, पर्यावरणीय चिंताओं और टिकाऊ उत्पादों की उपभोक्ता मांग, दोनों को ध्यान में रखते हुए, अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में पुनर्चक्रित रेशों को तेजी से शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मार्क्स एंड स्पेंसर अपने वस्त्र उत्पादन में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।

यह ब्रांड यह सुनिश्चित करता है कि उसके परिधानों में इस्तेमाल किया जाने वाला कपास या तो जैविक हो या पुनर्चक्रित सामग्री से प्राप्त हो। इसके अलावा, इसने 2025 तक केवल पुनर्चक्रित पॉलिएस्टर का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह, एच एंड एम समूह ने अपने उत्पादों में पुनर्चक्रित सामग्री को शामिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023 में, उपयोग की गई 25 प्रतिशत सामग्री का पुनर्चक्रण किया गया, और 2030 तक इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

स्थायित्व प्रयासों और पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सस्टेनेबल क्लोदिंग अलायंस द्वारा विकसित हिग इंडेक्स, फैशन उद्योग में जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन उपकरण प्रदान करता है।

पुनर्चक्रण के एक अन्य दृष्टिकोण में, परिधान उत्पादन से निकले बेकार कपड़ों और फैक्टरी कचरे को बचाया जाता है और नए परिधान बनाने के लिए उन्हें काटकर, पुनः जोड़कर या नवीनीकरण करके उनका पुनः उपयोग किया जाता है।

पैचवर्क डेनिम इस नवीनीकृत उत्पाद श्रेणी का एक प्रमुख उदाहरण है। हालाँकि, बेकार सामग्रियों से तैयार किए गए नवीनीकृत, पुनः निर्मित और पुनः डिजाइन किए गए परिधान वैश्विक उत्तरी बाजारों में उच्च-स्तरीय ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, फिर भी भारत में उनकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत सीमित है। भारत में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की ठोस क्षमता वाले चक्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम खोजा गया पहलू किराये का फैशन है।

जहाँ दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अनौपचारिक कपड़ों का आदान-प्रदान लंबे समय से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, वहीं औपचारिक कपड़ों की किराये की सेवाएँ एक अधिक संरचित और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ये सेवाएँ व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए कपड़े किराये पर लेने की अनुमति देती हैं और साथ ही दूसरों के उपयोग के लिए अपने खुद के कपड़े भी दान करती हैं। महिलाओं के लिए शादी की साड़ियाँ या लहंगे और पुरुषों के लिए शेरवानी या सूट जैसे उच्च-स्तरीय भारतीय पारंपरिक परिधान किराये पर लेना विशेष रूप से लोकप्रिय हो सकता है।

यह स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नवीन समाधानों की क्षमता को रेखांकित करता है, साथ ही व्यक्तियों को बार-बार उपयोग किए बिना विभिन्न प्रकार के परिधानों तक पहुँचने, अपने पैसे की अधिकता और वैश्विक बहुमूल्य संसाधनों के अति प्रयोग से बचने में सक्षम बनाता है।

वैश्विक रुझान : ग्लोबल डेटा के अनुसार, वैश्विक परिधान रेंटल बाजार 2023 में 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुँच गया, जिसमें उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, उसके बाद यूरोप और एशिया का स्थान है। यूके स्थित पीयर-टू-पीयर फैशन रेंटल मोबाइल ऐप, बाय रोटेशन, सदस्यों को अपनी जरूरत के कपड़े किराए पर लेने और कभी-कभार इस्तेमाल होने वाले कपड़े उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2019 में लॉन्च होने के बाद से, इस ऐप के 150,000 से ज्यादा उपयोगकर्ता हो चुके हैं। न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन ने 2021 में अमेरिका में 125 अमेरिकी डॉलर प्रति माह से शुरू होने वाली सदस्यता सेवा शुरू करके रेंटल बाजार में कदम रखा। इस बाजार के 2028 तक 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। इस बीच, भारतीय ऑनलाइन परिधान रेंटल बाजार का मूल्य 3-4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो आगे विकास और विस्तार की महत्वपूर्ण संभावना को दशार्ता है। हालाँकि कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि कपड़े किराए पर देने की प्रथा, खासकर शादी के लिए, गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है। रेंट द रनवे द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि किराए पर लिए गए कपड़ों से खुदरा खरीदे गए कपड़ों की तुलना में ऊर्जा की खपत में 24 प्रतिशत, पानी की खपत में 6 प्रतिशत और उ$2 उत्सर्जन में 3 प्रतिशत की कमी आई। हालाँकि, कपड़ों के किराये के लाभ पर्यावरण संरक्षण से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। कई उपयोगकताओं को फास्ट फैशन के कपड़ों तक पहुँच और उनका आनंद लेने की अनुमति देकर, किराये की सेवाएँ न्यायसंगत उपभोग को बढ़ावा देती हैं, जहाँ किराया आमतौर पर वस्तु की मूल लागत का 10-15 प्रतिशत होता है। इन संभावित लाभों के बावजूद, कपड़ों के किराये को व्यापक रूप से अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर स्वच्छता मानकों और ड्राई क्लीनिंग व डिलीवरी जैसी रसद संबंधी समस्याओं के संबंध में।

संपादकीय

अमृतवर्षा संपादकीय

भारत-रूस के प्रगाढ़ सम्बन्ध

पिछले पचास के दशक के शुरू में जब सोवियत संघ के नेता श्री खुश्चेव भारत की एक सप्ताह से अधिक की यात्रा पर आये थे तो उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में खड़े होकर यह घोषणा की थी कि कश्मीर जैसी कोई समस्या नहीं है और इसका सम्पूर्ण विलय भारतीय संघ में हो चुका है। इससे आज की पीढ़ी को अन्दाजा हो सकता है कि भारत व सोवियत संघ (रूस) के आपसी सम्बन्ध किस स्तर पर रहे हैं। रूस ने भारत का साथ हर मुसीबत के समय दिया है और सिद्ध किया है कि वह भारत का नैसर्गिक मित्र देश है। 1990 में सोवियत संघ का विघटन होने से पहले इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती थीं। अतः भारत व सोवियत संघ के सांस्कृतिक सम्बन्ध भी बहुत प्रगाढ़ थे। दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों के बीच आज तक कभी कोई ऐसा अवरोध नहीं आ सका है जिससे इनमें खटास का भाव जागता हो। यहां तक कि जब 2008 में भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया तो रूस ने इसका बुरा नहीं माना और हमारे साथ अपने सामरिक, रणनीतिक व राजनयिक सम्बन्धों के धागे को कस कर पकड़े रखा। भारत के विदेश मन्त्री श्री एस. जयशंकर आज ही रूस का तीन दिवसीय दौरा करके लौटे हैं। अपनी इस राजनयिक यात्रा के दौरान उन्होंने रूस की धरती पर खड़े होकर ही अमेरिका को यह पैगाम दिया कि अमेरिका ने ही उससे कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व गैस की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए वह रूस से कच्चा तेल भी खरीदें। यह कह कर जयशंकर ने साफ करने की कोशिश की है कि भारत से रूस के व्यापारिक सम्बन्ध वैश्विक हित को देखते हुए ही बने हुए हैं। जयशंकर को यह कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय आयातित माल पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क की वृद्धि इसी कारण की है। श्री ट्रम्प का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रूस के खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे युद्ध की विभीषिका को कम करने की गरज से ही लगाये गये हैं। उन्होंने एक तरह से भारत के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की और तर्क दिया कि इससे यूक्रेन के प्रति रूस की आक्रामकता में कमी आयेगी। अमेरिका एक तरफ भारत को अपना रणनीतिक सहयोगी मानता है और दूसरी तरफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करता है। अतः श्री जयशंकर का रूस में जाकर अमेरिका के मुतल्लिक बयान देना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर है कि श्री ट्रम्प के तेवर दादागिरी वाले हैं और वह अपने देश में आने वाले भारतीय माल पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा कर भारत को डराना चाहते हैं जबकि रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात चीन करता है और गैस आदि का सर्वाधिक आयात पश्चिम यूरोप के देश करते हैं। ऐसे हालात में भारत की नीति पूरी तरह तर्कसंगत है। दरअसल ट्रम्प चाहते हैं कि भारत को अपना विदेश व्यापार उनकी शर्तों पर करना चाहिए। शायद ट्रम्प भूल रहे हैं कि भारत एक स्वयंभू राष्ट्र है और उसकी विदेश नीति स्वतन्त्रता के बाद से ही पूरी तरह स्वतन्त्र रही है। भारत पर दबाव बनाने की गरज से ही श्री ट्रम्प पाकिस्तान के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं और बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि उन्होंने ही विगत 10 मई को भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध या संघर्ष विराम कराया। बेशक उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा भारत से कुछ घंटे पहले की मगर इससे यह कहां साबित होता है कि उन्होंने मध्यस्थता की जबकि भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि युद्ध विराम के सन्दर्भ में उनकी विश्व के किसी भी नेता से कोई बातचीत नहीं हुई। श्री ट्रम्प को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत अमेरिका की गीदड़ भभकियों के आगे कभी नहीं झुका है।1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में अमेरिका भारत के विरोध में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था इसके बावजूद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को पानी पिला दिया था और 1965 में तो भारतीय फौजें लाहौर तक पहुंच गई थीं। उस समय पाकिस्तान पर फौजी शासक जनरल अयूब का शासन था। भारत के हमलों से घबरा कर रातोंरात जनरल अयूब चीन से मदद मांगने के लिए बीजिंग पहुंचे थे। मगर तब सोवियत संघ हमारे साथ पर्वत की तरह खड़ा हुआ था। इसी प्रकार 1971 के बंगलादेश युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बीच से चीर कर दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। उस समय अमेरिका ने अपना सातवां जंगी जहाजी एटमी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था। मगर तब रूस ने चेतावनी दे दी थी कि यदि जहाजी बेड़े से जरा भी हरकत हुई तो रूसी जंगी जहाजी बेड़े उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मगर इस युद्ध को हुए अब पचास साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान वैश्विक परिस्थितियों में गुणात्मक सामरिक व रणनीतिक परिवर्तन आ चुका है। सामरिक दबावों की जगह आर्थिक दबावों ने ले ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया के देश उनकी आर्थिक ताकत के समक्ष नतमस्तक हो जायेंगे। उनकी यह सोच आत्मकेन्द्रित हो सकती है क्योंकि आज की भारत की नई पीढ़ी कम्प्यूटर व साफ्टवेयर उद्योग में विश्व की सिरमौर है और अपने ज्ञान के भरोसे पर वह शेष दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। भारत की इस ताकत को कोई देश नहीं छीन सकता है। मगर यह तस्वीर का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत के मेक इन इंडिया अभियान को वैश्विक बाजार की जरूरत है और अमेरिका को भारत का निर्यात सर्वाधिक रहता है।

संस्थापक संपादकः स्व. पारसनाथ तिवारी
स्वत्वाधिकारी एवं प्रकाशक रीता तिवारी,मुद्रक कुंज बिहारी के द्वारा आर डी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., प्लॉट नं- सी 16-17 पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013 से मुद्रित व B-14 जगत भवानी अपार्टमेंट, एसपी सिन्हा लेन, बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1 से प्रकाशित
संपादक-बन बिहारी
दूरभाष - 9905463571, 8757425017, धनबाद कार्यालयः मास्टर पाड़ा जे.सी. मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद दूरभाष - 2204991, दिल्ली कार्यालयः बी-49, जैन मंदिर गली, शकरपुर मेन मार्केट, दिल्ली-110092, फोन नं.- 011-22055208, आर.एन.आई नं. 44420/87
ईमेलः amritvar-shanews2015@gmail.com

भारत-अमेरिका सम्बन्धों में आए दरार के कूटनीति मायने

ऐसा इसलिए कि मित्र बनकर अमेरिका ने भारत से जो दगाबाजी पाकिस्तान प्रेरित पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है, उससे उसके बारे में यह अवधारणा मजबूत हुई है कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं।

कमलेश पांडे

भारत-अमेरिका संबंधों में गहराते दरार से दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। चूंकि भारत और अमेरिका के बीच संबंध 1947 में हासिल स्वतंत्रता के बाद से ही महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें जो उतार-चढ़ाव आए हैं, उसपर पूरी दुनिया की स्वार्थपरक निगाहें लगी हुई हैं। ऐसा इसलिए कि इससे अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीकरण की पूर्ववर्ती और मौजूदा दोनों कोशिशों को भी गहरा धक्का लग सकता है। चूंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, ऐतिहासिक पंचशील के सिद्धांतों को मानता आया है, इसलिए वह अमेरिका और रूस (यूएसएसआर) के खेमेबाजी से दूर रहने की कोशिश करता है। अमेरिका-चीन के वैश्विक रस्साकशी से खुद को दूर रखना चाहता है। लेकिन पिछले 7-8 दशक में भारत के पड़ोसी देशों- पाकिस्तान व चीन ने ऐसा सीमाई उधम मचाया कि भारत को कभी रूस से तो कभी अमेरिका से मदद लेनी पड़ी। जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है, तो रूस (सोवियत संघ) ने भारत के लिए मित्र से भी बढ़कर संरक्षक भूमिका निभाई है- तन-मन-धन से और यूएसए में वीटो करके भी। वहीं, जब कभी चीन से भारत का तनाव पैदा हुआ तो रूस ने पीछे से भारत की नैतिक मदद की, जबकि अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस समर्थक रूस को संतुलित करने के लिए पूर्व भाजपाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने दगाबाज अमेरिका से जो रणनीतिक मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये थे, वो दूसरे भाजपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि मित्र बनकर अमेरिका ने भारत से जो दगाबाजी पाकिस्तान प्रेरित पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है, उससे उसके बारे में यह अवधारणा मजबूत हुई है कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। जबकि रूस पर यह बात लागू नहीं होती। वह भारत-अमेरिका के प्रगाढ़ होते सम्बन्धों के बावजूद विचलित नहीं हुआ और भारत के रणनीतिक सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति करता रहा। यही वजह है कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब उसके ऊपर पश्चिमी देशों द्वारा विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए तो भारत ने उसे मानने से इनकार कर दिया और अपनी पुरानी भरोसेमंद वैश्विक मित्रता की लाज रखते हुए उससे तेल व हथियार खरीदकर उसकी पूरी मदद की। शायद यही बात अमेरिका को अखड़ गई, जबकि उसे धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि यूरोप का मुकाबला रूस से है, अमेरिका का नहीं! शीत युद्ध के बाद तो अमेरिका का मुकाबला चीन से, जिससे निबटने के लिए अमेरिका ने भारत से सांठगांठ शुरू की थी। चूंकि मौजूदा समय में रूस-चीन में गहरी यारी है और भारत, रूस-चीन के खिलाफ अमेरिका का मोहरा बनने को तैयार नहीं है, इसलिए सनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत को ही सबक सिखाने की ठान ली। यह अमेरिकी प्रशासन की अव्वल दर्जे की मूर्खता है और उसे अपनी भूल का एहसास तब होगा, जब तेजी से उभरता हुआ भारत अपने रुपये से डॉलर पर चोट करेगा। अभी अमेरिका इस गलतफहमी में है कि वह पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव आदि को उकसा कर भारत को कमजोर करेगा। लेकिन उसे यह याद रहना चाहिए कि जब भारत उसके साथ था, अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर झोंक चुका था, बावजूद इसके रूस-चीन-ईरान के दिमाग के समक्ष उसे पिटना पड़ा और अपने कीमती हथियार व उपकरण अफगानिस्तान में ही छोड़कर उसे भागना पड़ा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान जब अमेरिका इजरायल के पक्ष में खड़ा हुआ तो अरब देश कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने अपनी मिसाइल से हमला बोल दिया। वहीं, इजरायल को कितना नुकसान पहुंचाया, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तब पाकिस्तान भी उसके साथ था, लेकिन इजरायल से मित्रता के बावजूद भारतीय तटस्थता पर कभी रूस व ईरान ने एतराज नहीं जताया। वहीं, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध की कुछ बातों का भारत ने अनुपालन किया। इसलिए रूस से तेल खरीदने के सवाल पर जो अमेरिकी भृकुटी तनती जा रही है, उसके भविष्य गत मायने को समझने की जरूरत है। बताते चलें कि भारत को अमेरिका अनायास टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि वह समझ चुका है कि भारत में वो दम है जो ग्लोबल साउथ यानी अंतरराष्ट्रीय दलित-पिछड़े देशों को अपने पाले में करके अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। इसलिए फिलवक्त अमेरिकी रणनीति है कि रूस और चीन से मधुर सम्बन्धों को विकसित करते हुए भारत की आर्थिक व सैन्य कमर तोड़ दी जाए। इसलिए वह अंदरखाने में रूस-चीन को यही समझा रहा होगा कि भारत को हथियार मार्केट में उभरने ही नहीं दिया जाए। भारत के जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से बने रणनीतिक सम्बन्ध तभी हतोत्साहित होंगे, जब अमेरिका भारत से दूर होगा। चूंकि भारत ही रूस-चीन वैश्विक ऊर्जा का अर्थिग बना हुआ है, इसलिए भारत के घुटने पर आते ही रूस-चीन भी घुटने पर आ जाएंगे। ऐसे में भले ही अभी यह कहा जा रहा है कि विशेष रूप से, व्यापार और ऊर्जा विवादों ने संबंधों को प्रभावित किया है, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के दौरान। लेकिन इसके पीछे की सुनियोजित अमेरिकी प्रशासन की नीतियों को भी मैं ऊपर डिकोड कर चुका हूं, जिसे हमें समझना होगा, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र तो उसका मुखौटा मात्र होता है। अंततः दोनों मिलकर अपने देश की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। रही बात अमेरिका की तो वह कई साल आगे की रणनीति भी वर्तमान में ही शोध पूर्वक तैयार कर लेता है और फिर यूरोप के बलपर उसे पूरी दुनिया पर थोपता है। इसलिए समसामयिक वैश्विक परिवेश में जब अमेरिका को यूरोप में रूस (पूर्व सोवियत संघ का अगुवा राष्ट्र) से, एशिया में चीन से, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील से, और इन सबके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से चुनौती मिलनी जारी है तो उसने अपने डॉलर का दुरूपयोग करके वहां अशांति पैदा करवाने की कोशिशें तेज कर दी है। इसलिए उसने पुराने हरामखोर पार्टनर पाकिस्तान को भी पटा लिया है। इससे उसके हथियार व गोला-बारूद निमार्ता कम्पनियों को आशातीत मुनाफा होगा। इसलिए वह इस प्रकार की हरामखोरी जारी रखता है। वैश्विक कूटनीति में अमेरिकी मित्रता को आस्तीन में सांप पालने जैसा समझा जाता है। जहां तक अमेरिका-भारत के दरकते रणनीतिक सम्बन्धों के नकारात्मक प्रभाव की बात है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि आपसी संबंध बिगड़ते हैं, तो व्यापार समझौते और निवेश प्रभावित हो सकते हैं, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। चूंकि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग भी चल रहा है, खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, तो संबंधों में आई हालिया दरार से यह सहयोग भी कमजोर हो सकता है। वहीं, जहां तक आपसी रणनीतिक सहयोग की बात है तो दोनों देश कई वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी आदि। लेकिन पारस्परिक संबंधों में आई खटास से इन मुद्दों पर भी द्विपक्षीय सहयोग बाधित हो सकता है। खास बात यह है कि दोनों देशों के मधुर सम्बन्धों के बीच भारतीय-अमेरिकी समुदाय की भी अमेरिका में एक महत्वपूर्ण समुदाय है, और यदि द्विपक्षीय संबंधों में दरार आई तो इससे इस महत्वपूर्ण समुदाय के लिए भी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने के कई कारण हैं- पहला यह कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक विकास और सुरक्षा सहयोग में साझा हित रखते हैं। इसके अलावा, भारतीय-अमेरिकी समुदाय दोनों देशों के बीच एक सम्बन्ध सेतु का काम करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत-अमेरिका संबंधों में दरार से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बनाए रखने के कई कारण हैं, इसलिए यह देखना और इंतजार करना श्रेयस्कर होगा कि आने वाले वर्षों में आपसी संबंध कैसे विकसित होते हैं।

भारत का 'ट्रम्प कार्ड' रूस

आज की तारीख में अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी की चर्चा है तो वहीं एशियाई महाद्वीप में भारत का जिक्र भी उसकी बढ़ती ताकत के लिए किया जाता है जिसके सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। यहां चीन को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जो कि एशिया में भारत की ही तरह एक बड़ा वजूद रखता है। अगर पिछले तीन-चार वर्षों की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद स्थितियां बदली और राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय माहौल बनाने में ट्रंप ने एक बड़ा काम किया। लेकिन पिछले दो-तीन महीनों में जो कुछ हुआ है उससे दुनिया की नंबर दो सुपर पावर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का चेहरा भी उभरकर सामने आया है। जितने भी नये-नये एंगल बन रहे हैं उनमें एक खलनायक के रूप में ट्रंप ही उभर रहे हैं। इस बीच भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसके सीजफायर का श्रेय लेने के लिए ट्रंप ने कम से कम 25 बार फायर किये होंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से अपने यहां भारी तबाही को लेकर पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया तो भारत ने युद्ध रोका, इसके बाद से लेकर ट्रंप बिदक गये हैं। इसी की खुंदक में उन्होंने भारत के खिलाफ नया टैरिफ बम फोड़ दिया है और इसे 50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। यह बात अलग है कि रूस से भारत का आयल लेना भी उन्हें पसंद नहीं है। इन सब घटनाक्रमों के परिणाम जिस तरह दिखाई दे रहे हैं उससे भारत ही मजबूत होगा और रूस हमेशा की तरह भारत के एक टेस्टिड और ट्रस्टिड अर्थात देखे-परखे मित्र के रूप में उभरा है। पुतिन अगर मास्को से विशेष रूप से पीएम मोदी को अपनी ट्रंप से मुलाकात के बारे में भारत को जानकारी दे सकते हैं तो वहीं से रिश्तों की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में मोदी और सी-जिनपिंग के बीच प्रस्तावित वार्ता ने भी ऐसी नई संभावनाओं को जन्म दिया है जो अमरीका को परेशान कर सकती है। लिहाजा आने वाले दिनों में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यह सब ट्रंप के लिए चेतावनी का संकेत भी है। बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में रूस, इंडिया और चीन अर्थात आरआईसी के एक नए गठबंधन की चर्चा दुनिया के बड़े देश कर रहे हैं। रूस से दोस्ती की हमारी पुरानी मजबूती ट्रम्प को रास नहीं आ रही आज भी चुनौतियां तो हैं लेकिन मोदी है तो सब मुमकिन है, भारत सबकुछ ठीक कर लेगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक रूस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत रहे हैं और मजबूत ही रहेंगे। यह विश्वास भी दोनों राष्ट्रों को है। रूस विखंडन के बाद हमारे रिश्तों पर बर्फ जमी लेकिन संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, उधर अमेरिका सुपर पॉवर बन गया था।

पहले जापान फिर चीन...कूटनीति में यात्रा का क्रम कई संदेश देता है, एशियाई राजनीति में संतुलन साधेंगे मोदी

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा केवल दो देशों की यात्रा भर नहीं है, बल्कि एशिया तथा वैश्विक राजनीति की दिशा और संतुलन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव वॉशिंगटन तक भी पहुँचेंगे। सबसे पहले, 29-30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान जाएंगे, जहाँ वह प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारतद्वजापान वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। यह मोदी का जापान का आठवाँ दौरा और इशिबा के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। हम आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, जिसमें रक्षा-सुरक्षा, व्यापार, तकनीकी सहयोग और जन-से-जन संपर्क प्रमुख आधार हैं। इस यात्रा के माध्यम से मोदी यह संदेश देंगे कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक, पारदर्शी और नियम-आधारित व्यवस्था का प्रबल समर्थक है। जापान के लिए यह संकेत भी स्पष्ट होगा कि भारत उसके साथ गहरी साझेदारी चाहता है और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच वह अकेला नहीं है। इसके बाद, 31 अगस्त 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रउड भारत की एशिया नीति का अहम हिस्सा है। वहाँ सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होता है। इस मंच पर मोदी की मौजूदगी चीन के लिए यह संदेश है कि भारत टकराव नहीं बल्कि संवाद और बहुपक्षीय सहयोग का पक्षधर है।

साथ ही यह भी स्पष्ट संकेत है कि भारत जापान जैसे देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाकर बीजिंग पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाए रखने की क्षमता रखता है। कूटनीति में यात्रा का क्रम भी संदेश देता है। मोदी ने पहले जापान और फिर चीन का दौरा तय कर यह जताया है कि भारत एशिया में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चलता है। बीजिंग को संकेत दिया गया है कि भारत उसकी शर्तों पर नहीं झुकेगा और जापान को आश्वस्त किया गया है कि चीन के साथ संवाद उसकी कीमत पर नहीं होगा। इसके अलावा, जापान के साथ रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का संतुलन साधने में मदद कर सकता है, वहीं जापान निवेश और तकनीकी सहयोग का भी बड़ा स्रोत है। दूसरी ओर, चीन के साथ सीधे संवाद बनाए रखने से भारत को सीमा विवाद और एससीओ जैसे मंचों पर अपनी स्थिति मजबूती से रखने का अवसर मिलता है। इस क्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का हालिया बयान उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि परिस्थितियाँ मांगने पर चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगी पाबंदियों की समीक्षा की जा सकती है। यह संकेत ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में तनाव देखा जा रहा है और चीन के साथ तालमेल की संभावनाएँ खुल रही हैं। अमेरिकी दृष्टि से यह यात्रा बेहद अहम है। वॉशिंगटन इसे गहराई से देखेगा, क्योंकि यह उसकी इंडो-पैसिफिक रणनीति, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और जापान की भूमिका— तीनों से जुड़ी है। भारत यहाँ अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। जापान में जाकर भारत अपने स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करता है, जो अमेरिका की इंडो-पैसिफिक दृष्टि से मेल खाता है। वहीं चीन जाकर मोदी यह दिखाएंगे कि भारत अपने पड़ोस और बहुपक्षीय मंचों की अनदेखी नहीं करेगा। बहरहाल, मोदी की जापान और चीन यात्रा अमेरिका को यह याद दिलाती है कि भारत उसका नेचुरल पार्टनर तो है, लेकिन जूनियर पार्टनर नहीं। भारत सहयोग का पक्षधर है, पर अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करता। यह दौरा साफ तौर पर दिखाता है कि भारत किसी एक ध्रुव का हिस्सा बनने के बजाय संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देता है।

https://t.me/+MLNsLJ7GEFE3ZDid1

विभाजक ताकतों को उलाहना देती बाबुश्किन की हिंदी

बाबुश्किन का हिंदी बोलना भारतीय राजनीति और समाज के उस तबके के लिए सीख हो सकता है, जो हिंदी का सवाल आते ही भड़क उठते हैं। जिन्हें विदेशी अंग्रेजी तो ग्राह्य और स्वीकार्य है, लेकिन हिंदी उनकी अपनी अस्मिता पर सवाल उठाती लगती है।

उमेश चतुर्वेदी

आज के रूस और उसके पूर्ववर्ती सोवियत संघ में हिंदी की पढ़ाई-लिखाई 1957 से ही शुरू हो गई थी, इस लिहाज से रूस के किसी नागरिक का हिंदी बोलना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। लेकिन आज के दौर में भारत स्थित रूसी दूतावास के दूसरे नंबर के अधिकारी रोमन बाबुश्किन अगर हिंदी के चंद लफ्जों का इस्तेमाल करें तो वह अहम हो जाता है। रूस से तेल खरीद के चलते अंकल सैम की आंखें इन दिनों भारत पर लाल हैं। इसी संदर्भ में 20 अगस्त को रूसी दूतावास ने एक प्रेस कांफ्रेंस रखी। उस प्रेस कांफ्रेंस में अपने संबोधन की शुरूआत बाबुश्किन ने हिंदी के दो वाक्यों से करके भारतीय भाषा प्रेमी पत्रकारों का दिल जीत लिया। बाबुश्किन का पहला वाक्य रहा, ह्यसभी का हार्दिक स्वागत है। पत्रकारिता जगत की हस्तियों की श्रवणेंद्रिय इस हिंदी प्रयोग का झटका झेल रही थीं, कि बाबुश्किन ने ठेठ भारतीय सांस्कृतिक अंदाज में दूसरा वाक्य छोड़ दिया, "हम शुरूआत करेंगे...भगवान गणेश के साथ। गणेश चतुर्थी आ रही है। बाबुश्किन का हिंदी बोलना

भारतीय राजनीति और समाज के उस तबके के लिए सीख हो सकता है, जो हिंदी का सवाल आते ही भड़क उठते हैं। जिन्हें विदेशी अंग्रेजी तो ग्राह्य और स्वीकार्य है, लेकिन हिंदी उनकी अपनी अस्मिता पर सवाल उठाती लगती है। आजाद भारत की राजनीति जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किस कदर विभाजित हुई है, इसे समाज तो रोज ही झेलता-देखता है। इस विभाजक सोच का ही असर है कि हमारी अपनी भाषाओं के बीच भी झगड़े पैदा किए जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के विरोध में राजनीति खूब खड़ा कर रही है और इसके जरिए वह अपना सियासी उल्लू ही सीधा करती है। नैरतंर्य और सकारात्मकता के लिहाज से देखें तो इसके सामाजिक विघटन की नींव ही मजबूत हो रही है। अस्मिताबोध को जगाने की आड़ में भाषायी वैमनस्य की राजनीति का एक मात्र मकसद सामाजिक विघटन को बढ़ाना और उस बंटे समाज के बीच से अपने खांचे में फिट बैठने वाला बड़ा समर्थक आधार वर्ग तैयार करना है। इसीलिए जब नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के जरिए प्राथमिक शिक्षा की बात होती है तो हिंदी को किनारे लगाने के लिए तमिल राजनीतिक अस्मिता उठ खड़ी होती है। कन्नड़ और बांग्ला भाषा बोध भी हिंदी के खिलाफ उठ खड़ा होता है। दिलचस्प यह है कि स्थानीय भाषाबोध के इन खिलाड़ियों के लिए वह अंग्रेजी अपनी हो जाती है, जिसकी कथित तौर पर वैश्विक व्यापकता है। हालांकि हकीकत यह है कि अंग्रेजी की व्यापकता गहराई से देखें तो अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और हांगकांग में ही है। अंग्रेजी को तो बाबुश्किन ने भी अपना रखा है। भारतीय पत्रकारों के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बाद में वे अंग्रेजी में ही बोले। लेकिन हिंदी में बोलकर उन्होंने एक तरह से भारतीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी स्थानीय समुदायों के दिल तक अपनी पैठ बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं के कुछ शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरूआत करते रहे हैं। पता नहीं, बाबुश्किन ने हिंदी बोलकर वहां उपस्थित कितने भारतीय पत्रकारों का दिल जीता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया पर जब से उनकी मीठी प्रचारित हुई है,उन्होंने ठेठ भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया है। सोवियत संघ में हिंदी फिल्में काफी पसंद की जाती रही हैं। एक दौर में राजकपूर की फिल्में खासा लोकप्रिय रही हैं। राजकपूर अभिनीत फिल्म श्री 420 का गीत मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक दौर में सोवियत संघ के घर-घर का पसंदीदा गीत बन गया था। कम्युनिस्ट शासन के दौर में रूस की राजधानी मास्को में हिंदी में दो प्रकाशक भी सक्रिय रहे, प्रगति प्रकाशन और रादुगा प्रकाशन। इन प्रकाशनों के जरिए रूसी लेखकों के साथ ही लेनिन, स्टालिन आदि की रचनाएं हिंदी में अनूदित होकर सस्ते में उपलब्ध होती थीं। एक दौर में सोवियत संघ की दो पत्रिकाएं सोवियत देश और 'स्पूतनिक भारत में बहुत प्रचलित थे। हिंदी की वहां पढ़ाई भी खूब होती है। इसकी शुरूआत 1955 में हुई। उसके पहले तक रूस की भारत में दिलचस्पी संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन तक सीमित थी। साल 1955 में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने भारत का दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, "हम यह देखेंगे कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी विकसित हो जिसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण-सम्पन्न नई पीढ़ी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखें।"इसी के बाद सोवियत संघ में हिंदी प्रकाशन और पढ़ाई-लिखाई की शुरूआत हुई। आज रूस के मास्को राजकीय विश्वविद्यालय, रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्वविद्यालय, सांक्त पितेरबूर्ग विश्वविद्यालय, विद्यालय क्रमांक 19, मॉस्को, फार ईस्ट विश्वविद्यालय, ब्लादीवोस्तक आदि में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सॉंस्कृतिक केंद्र में हिन्दी की कक्षाएँ चल रही हैं। जिनमें हर आयु वर्ग लोग हिंदी सीख रहे हैं। साफ है कि विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं, भारत आए विदेशी हिंदी बोल रहे हैं। इस्कॉन के मंदिरों में जाकर देखा जा सकता है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी
संपादकीय
संस्थापक: छठीं पिताजी लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं करम के योद्धा श्रद्धेयी सुरेश जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

बिहार एसआईआर आधार भी मान्य

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव लोकतांत्रिक चेतना का उत्सव होते हैं। चुनावी व्यवस्था की सफलता और विश्वसनीयता के पीछे सबसे बड़ा स्तम्भ भारतीय निर्वाचन आयोग है। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की विश्वसीयता उसकी संस्थाओं में जनविश्वास से तय होती है। भारत का लोकतंत्र केवल ईवीएम मशीनों से नहीं चलता। वह संस्थाओं की ईमानदारी और नागरिकों के विश्वास से चलता है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद चुनाव आयोग को विपक्षी दलों ने कठघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर अंतरिम आदेश दे दिया है, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह आधार कार्ड को मान्यता दे। शीर्ष अदालत ने हटाए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति दी और कहा कि आधार कार्ड समेत फार्म-6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी एक जमा किया जा सकता है। पीठ ने चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वह मतदाता सूची से बाहर हुए व्यक्तियों के दावा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा कराने वाले राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजैंटों को पावती रसीद भी उपलब्ध कराएं।

> बीते कुछ वर्षों में राजनीति का स्वरूप कुछ इस तरह का हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना एक प्रचलन बन गया है। विपक्षी दलों को यह अधिकार है कि वह आलोचना करें, विरोध करें, सवाल उठाएं लेकिन साथ ही उन्हें संस्थाओं का सम्मान भी बनाए रखना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने उन मतदाताओं को भी पेश किया है जिन्हें मतदाता सूची में मृत दिखाया गया है। एसआईआर में कई तरह की विसंगतियां हैं। कुछ मामलों में लोगों के पास दो-तीन और यहां तक कि चार एपिक मौजूद हैं। कुछ लोग एक ही बूथ पर कई बार रजिस्टर्ड हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। विपक्ष ने दावा किया है कि सर्वोच्च अदालत के हस्तक्षेप से लोकतंत्र चुनाव आयोग के क्रूर हमले से बच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश यह भी दिया है कि उसने सभी 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाते हुए उन मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया है जिनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां 1.68 लाख से ज्यादा बूथ स्तरीय एजैंट तैनात हैं, चुनाव आयोग के पास अब तक केवल दो आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इतनी बड़ी संख्या में एजैंट होने के बावजूद इतना कम सहयोग गम्भीर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके मतदाता सूची में संशोधन को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं। इसकी सराहना की जानी चाहिए।

अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप तथ्यहीन शोर-शराबा है या संस्थागत दुर्भावना। बीते कुछ वर्षों में राजनीति का स्वरूप कुछ इस तरह का हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना एक प्रचलन बन गया है। विपक्षी दलों को यह अधिकार है कि वह आलोचना करें, विरोध करें, सवाल उठाएं लेकिन साथ ही उन्हें संस्थाओं का सम्मान भी बनाए रखना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने उन मतदाताओं को भी पेश किया है जिन्हें मतदाता सूची में मृत दिखाया गया है। एसआईआर में कई तरह की विसंगतियां हैं। कुछ मामलों में लोगों के पास दो-तीन और यहां तक कि चार एपिक मौजूद हैं। कुछ लोग एक ही बूथ पर कई बार रजिस्टर्ड हैं। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इन विसंगतियों को दूर करे।

देश ने अपने चुनावी इतिहास में पिछले हफ्ते एक असाधारण स्थिति देखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कई मुद्दों पर चुनौती दी, जैसे कि डुप्लिकेट ईपीआईसी प्रविष्टियां, निर्वाचन क्षेत्रवार वृद्धि जो सांख्यिकीय रूप से अजीब लगती है,मशीन-पठनीय रोल देने से इन्कार और सीसीटीवी/वेबकास्ट फुटेज को 45 दिनों में हटाना आदि, जिससे चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब माताधिकार की अखंडता के बारे में विशिष्ट, जांच योग्य आरोपों का सामना करना पड़ता है तो क्या आयोग फाइल खोलता है या अपनी खेमेबंदी करता है? संस्था की ओर से "हलफनामा दायर करने"की पहली प्रतिक्रिया एक संवैधानिक प्रहरी के आत्मविश्वास से कम और एक प्रक्रियात्मक चाल ज्यादा लग रही थी।

सवाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सशक्त भी बनाया है और सीमाओं में भी बांधा है। बिहार में एसआईआर ने आशंकाओं को जन्म इसलिए दिया है कि पहले की आधार रेखाओं की तुलना में मसौदा सूची से 65 लाख नाम गायब हैं। यद्यपि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह बिना सूचना सुनवाई और तर्कसंगत आदेश के किसी भी योग्य मतदाता को नहीं हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को मान्यता देने के बाद मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना या भौतिक रूप से फार्म भरना आसान हो गया है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बूथ एजैंट मिलकर मतदाता सूचियों की विसंगतियां दूर करें। लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूचियों के पवित्र होने पर ही निर्भर करती है।

इस फैसले ने किया न्यायोचित...

गीता पाढा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का दिल से आभार है, कुत्ता प्रेमियों की अपील पर किया आपने सराहनीय विचार है, कुत्तों की नियमित नसबंदी और टीकाकरण के लिए नगर पालिका रहे तैयार है, मानवीय सुरक्षा के साथ-साथ जानवरों के साथ भी- इस फैसले ने किया न्यायोचित व्यवहार है !!

दो नावों पर सवार हैं पवार

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

राकांपा नेता शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सूले ने हालिया दिनों में कांग्रेस के एक बड़े नेता से मिलकर उन्हें अपनी पार्टी हैडक्वार्टर के लिए आवंटित नई दिल्ली स्थित 81, लोदी एस्टेट निवास रहने के लिए ऑफर किया है, कहते हैं इस नेता ने सुप्रिया के इस 'गुडविल ऑफर' को आसानी से स्वीकार भी कर लिया है। सनद रहे कि यह नेता पहली बार के सांसद हैं, इस नाते उन्हें रहने को छोटा सरकारी आवास ही आवंटित हुआ है, पर उनके मुलाकातियों की संख्या को देखते हुए उन्हें एक बड़े घर की दरकार थी, सुप्रिया ने मौके की इसी नजाकत को भांपते हुए नेता जी को 81 लोदी एस्टेट का अपनी पार्टी का दफ्तर ही ऑफर कर दिया।

दरअसल, शरद पवार पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की अपनी जमीन को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, वे जब भी उद्धव ठाकरे से बात करते हैं तो प्रमुख उनकी रंग बदलती सियासत को देखते हुए बेसाख्ता कह देते हैं कि 'आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी मोदी जी से इतनी गहरी छनती है कि आप महीने में कम से कम दो बार उनसे बात जरूर करते हैं। उन्होंने आपसे यह भी वायदा किया हुआ है कि बिहार चुनाव के बाद वे आपकी पुत्री को अपनी सरकार में शामिल करेंगे।'

इसी कड़ी में बड़े पवार ने अपने घर अपने कुछ मूंहलगे पत्रकारों को डिनर पर आमंत्रित किया और उनसे 'ऑफ द रिकार्ड' बात करते हुए उन्होंने कहा-मैं चाहता हूं कि हम विपक्ष में रह कर अब अपनी भूमिका मजबूत करें, आजकल शरद पवार परिवार कंग्रेस के प्रति इतनी आस्था दिखा रहा है।

क्यों बेचैन हैं एनडीए के ओबीसी नेता?

सूत्रों की मानें तो करीब दो सप्ताह पहले केंद्रीय मंत्री व अपना दल (सोनेवाल) की नेता अनुप्रिया पटेल और यूपी की मल्लाह राजनीति के केंद्र रहे संजय निषाद के बीच एक लंबी और सारगर्भित मुलाकात हुई। कहते हैं कि अनुप्रिया ने अपने दर्द को स्वर देते हुए कहा कि 'भाजपा की नजरों में हमारी कोई वकत नहीं, हमें 6-7 सीटों पर ही निपटा देंगे, चूंकि आपका बेटा भी इस बार चुनाव हार गया है सो, आपका समय तो और भी मुश्किलों भरा है।' संजय निषाद भी चाहते हैं कि यूपी के ये छोटे-छोटे दल इकट्ठे होकर अपना एक 'संयुक्त मंच' बना लें जिससे कि भाजपा नेतृत्व से ठीक से तोलमोल के बोल हो सकें।

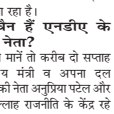

कहते हैं इसी कड़ी में इन नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से भी बात की। जयंत से कहा गया कि 'हम सभी नेताओं को एक मंच पर आकर एकजुटता में अपनी ताकत दिखानी होगी तभी हम भाजपा नेतृत्व पर कोई दबाव बना पाएंगे।' माना जाता है कि जयंत चौधरी भी इन दिनों भाजपा नेतृत्व से थोड़े खफा-खफा चल रहे हैं क्योंकि भले ही उन्हें फिस्कल डेपलपमेंट मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया हो, पर पिछले सालभर में उनके मंत्रालय को कोई फंड ही आवंटित नहीं हुआ है, ऐसे में वे स्वयं को मंत्री 'दिए आउट पोर्टफोलियो' जैसा ही महसूस कर रहे हैं। इसके बाद इस नए मंच के गठन के लिए यूपी में पिछड़ों के एक बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर से भी बात की गई है। फिलवक्त इन नेताओं ने मिल कर यही सामूहिक रणनीति बनाई है कि ये नेतागण घूम-घूम कर अपने-अपने क्षेत्रों में रैलियां व जनसंपर्क अभियान करेंगे और भाजपा को यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि 'वह सिर्फ अगड़ी जातियों के दम पर सरकार में नहीं हैं, उन्हें पिछड़ी जातियों की भी इतनी ही जरूरत है।'

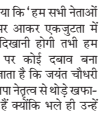

चिराग को फटकार

अभी दो-तीन दिन पहले ही भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को तलब कर उनकी अच्छी खासी क्लास लगा दी। दरअसल, चिराग को लेकर बिहार चुनाव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी खबर आती है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, कभी यह कि वे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ सीटों का तालमेल कर सकते हैं। इस पर भाजपा के एक कद्दावर नेता ने चिराग को तलब कर उनसे दो टूक पूछ लिया- आप अलग-अलग जगह पर अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा असमंजस बना हुआ है कि आप करेंगे क्या? इस पर चिराग ने कहा कि 'वे एनडीए में रह कर एनडीए के हाथ ही मजबूत करना चाहते हैं, पर भाजपा बताए कि उनके लिए वह कितनी सीटें छोड़ेंगी।'

कहते हैं इस पर उक्त बड़े भाजपा नेता ने कहा कि हम सीटों की बात बाद में करेंगे, पहले आप यह बयान जारी करें कि आप एनडीए के अंदर रह कर ही चुनाव लड़ेंगे।' दरअसल इस पूरे कथानक के पीछे भाजपा का अपना एक जनमत सर्वेक्षण है। सूत्र बताते हैं कि अभी पिछले दिनों भाजपा ने बिहार में अपना एक अंदरूनी सर्वेक्षण करवाया है, यह सर्वे 'एसआईआर' और वोट चोरी के हंगामे के बाद के तापमान को नापने के लिए आहूत हुआ था। इस सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि अगर इस दफे के चुनाव में भाजपा अपने दम पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाए तो वह 70-75 सीटों पर सिमट सकती है, अगर वह लोक जनशक्ति यानी चिराग के साथ लड़ी तो उसे 10 सीटों का इज़ाफा हो सकता है, पर अगर वह जदयू के साथ चुनाव में गई तो वह जरूरी बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंच सकती है। वैसे भी नीतीश ने भाजपा नेतृत्व से दो टूक कह दिया है कि 'चिराग पासवान के साथ रहने या ना रहने से गठबंधन को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, अगर चिराग के लिए भाजपा सीटें छोड़ना चाहती है तो वह अपने कोटे से छोड़ें।'

धनखड़ की धमक कहां गई?

महीने भर का वक्त हो गया, पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहीं नजर नहीं आ रहे, वे किसी से मिलने-जुलने से भी गुरेज कर रहे हैं। कहते हैं अभी पिछले सप्ताह पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं का एक जत्था उनसे मिलने उसके आवास पर पहुंचा, उन्हें सम्मान के साथ बिठाया गया, चाय-वाय पिलाई गई और बाद में उन्हें बता दिया कि अभी धनखड़ जी किसी से मिल नहीं रहे, जब मिलना-जुलना शुरू करेंगे तो आप लोगों को भी बुला लिया जाएगा। पर अभी भी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही कि अचानक से भाजपा हाईकमान ने उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? उनसे जुड़े एक विश्वस्त सूत्र का दावा है कि धनखड़ पिछले दिनों (जब से विपक्ष ने खास कर कांग्रेस ने उन पर महाभियोग चलाने की धमकी दी थी) विपक्षी नेताओं से खूब मेल-जोल बढ़ाने में जुट गए थे।

खास कर राहुल गांधी को लेकर उनका आग्रह भाजपा शीर्ष के गले नहीं उतर रहा था। वे टीएमसी नेताओं से मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे और उनसे कह रहे थे-मनी ड्रेन व ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अगर अभी स्थितियां ठीक नहीं करोगे तो आगे चल कर बेहद मुश्किल होगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि उन्होंने कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता को सलाह दी कि उन्हें चंद्रबाबू व एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं से बात करनी चाहिए।' कहते हैं धनखड़ के इन मनोभावों की जानकारी भाजपा की 'बी टीम' कहे जाने वाले दिल्ली के एक बड़े नेता ने भाजपा शीर्ष तक पहुंचा दी, इस नेता ने भाजपा शीर्ष से यह भी कह दिया कि 'धनखड़ विरोधी गुट के 300 सांसदों का एक धड़ा तैयार करने में मदद कर रहे हैं,' फिर क्या था गुस्से से लाल-पीला होते भाजपा शीर्ष ने धनखड़ की विदाई की पटकथा लिख दी।

...और अंत में

लगता है बिहार में मुद्दतों बाद कांग्रेस संगठित रूप से चुनावी मैदान में दमखम दिखाने को उतारू है। कहते हैं कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी तेजस्वी यादव को सौंप दी है। माना जाता है कि इस लिस्ट में 6-7 सीटें कोसी अंचल की भी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लिस्ट की बाकी सीटों पर तो तेजस्वी को कोई खास एतराज नहीं, पर वह कोसी अंचल की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को राजी नहीं। तेजस्वी की सोच है कि कांग्रेस ये सीटें अपरोक्ष तौर पर पप्पू यादव के लिए चाह रही है। राहुल गांधी की 17 अगस्त से बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' जारी है। इस यात्रा की सफलता-असफलता ही तय करेगी कि राहुल कोसी अंचल की सीटों को लेकर तेजस्वी से कितना मोल-भाव कर पाएंगे। फिलवक्त तो राहुल बिहार में मिल रहे रिस्पांस से बम-बम लग रहे हैं।

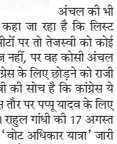

सलवा जुडूम पर फैसला मेरा नहीं, उच्चतम न्यायालय का है:सुदर्शन रेड्डी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सलवा जुडूम पर फैसले को लेकर नक्सलवाद का 'समर्थन' करने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वह इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। रेड्डी ने कहा कि यह फैसला उनका नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय का था।

शाह ने एक दिन पहले विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार रेड्डी पर तीखा हमला किया था। रेड्डी ने न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर के साथ उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुडूम को भंग करने का आदेश दिया था और कहा था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवाओं का विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है।

इस फैसले का हवाला देते हुए गृह मंत्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर नक्सलवाद का 'समर्थन' करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर यह नहीं हुआ होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। रेड्डी ने कहा कि अगर शाह ने पूरा फैसला पढ़ा होता, तो वे यह टिप्पणी नहीं करते।

रेड्डी ने कहा, ''मैं भारत के माननीय गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मामले में नहीं शामिल होना चाहता, जिनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद, प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है।'' उन्होंने कहा, ''दूसरी बात, मैंने यह फैसला लिखा है। यह फैसला मेरा नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय का है।''

रेड्डी ने कहा कि उनके साथ पीठ में एक और न्यायाधीश भी बैठे थे और फैसले को 'रद्द' करवाने की बार-बार की गई कोशिशें नाकाम रहीं।

रेड्डी ने कहा, ''मैं फैसले के गुण-दोषों पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे अपने साथियों ने सिखाया है कि किसी को अपने फैसले की महानता के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसका फैसला जनता को करना है। यह मेरा निजी दस्तावेज नहीं है।''

> शाह ने एक दिन पहले विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार रेड्डी पर तीखा हमला किया था : वह इस मामले पर और टिप्पणी करके बहस की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते

रेड्डी ने कहा, ''काश, माननीय गृह मंत्री ने खुद पूरा फैसला पढ़ लिया होता, बजाय इसके कि उन्हें किसी से जानकारी मिले, मुझे नहीं पता... उनके पास लगभग 40 पन्नों का फैसला पढ़ने के लिए इतना समय नहीं रहा होगा। अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता, तो शायद उन्होंने यह टिप्पणी नहीं की होती। मैं बस इतना ही कहूंगा और यहीं समाप्त करता हूं।'' विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने कहा कि वह इस मामले पर और टिप्पणी करके बहस की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, ''बहस में शालीनता होनी चाहिए।'' केरल में शुक्रवार को भाजपा नेता शाह ने कहा, ''सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता, तो नक्सली उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। वह वही व्यक्ति हैं जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे।'' उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के रूप में विदेशों में जमा काले धन पर दिए गए अपने फैसलों के लिए जाने जाने वाले बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि देश की संपत्ति वापस लानी होगी और यह काम जारी है। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने काले धन के मामलों की जांच में 'ढिलाई' बरतने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकारों की आलोचना करते हुए फैसले दे चुके हैं। उन्होंने विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया था।

रेड्डी ने कहा, ''यह काम अभी जारी है... यह महत्वपूर्ण है। देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न माध्यमों और तंत्रों के जरिए देश से बाहर चला गया है। इसे वापस लाना होगा। यह हमारा पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है और देश की संपत्ति है।''

''आवारा कुत्ते और सुप्रीम फैसला...''

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
वेलफेयर- वरिष्ठ कार्यकैक केसरी बाल मुख्य संरक्षिका- चैयरपर्सन
सदस्या- राष्ट्रीय समाचारपत्र मण्डल, एकल संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

आवारा कुत्तों के मामले में देश की राजधानी दिल्ली समेत कितने ही महानगर समस्याएं झेल रहे हैं। कुत्तों के हमलों व बच्चों तथा बड़ों के काटे जाने की बढ़ती घटनाओं से क्षुब्ध होकर लोग छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ दिन पहले सुप्रीम आर्डर जारी हुए कि दिल्ली सरकार व एमसीडी सड़कों पर आवारा कुत्तों को पकड़े, उन्हें शैल्टर घरों में रखे ताकि नागरिकों को राहत मिल सके लेकिन इस फैसले के खिलाफ डॉग लवर्स फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मामले में नए ऑर्डर दो दिन पहले जारी किए गए। जहां डॉग लवर्स संगठन खुश हैं वहीं आम जनता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी हद तक संतुष्ट है। यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देख लीजिए तो अच्छा है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शैल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है। कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि पशुपालन केंद्रों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने राज्यों के हाईकोर्ट में ऐसे ही लंबित मामलों को लेकर जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी मामले शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाएगा या पकड़ा गया है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। हालांकि कोर्ट का ये आदेश रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा लेकिन कोर्ट के पहले आदेश की तुलना में नया आदेश डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी राहत की तरह जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश देते समय इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

फैसले के अनुसार रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा नगर निगम को कुत्तों के लिए अलग फीडिंग प्वाइंट बनाने होंगे और सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना मना रहेगा। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। हालांकि, डॉग लवर्स का कहना है कि अब भी उनकी दो बड़ी चिंताएं बरकरार हैं। पहली, आक्रामक कुत्तों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। कौन सा कुत्ता आक्रामक है और कौन सा नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा, यह सवाल सभी के मन में है। दूसरी, फीडिंग प्वाइंट से जुड़ी समस्या है। अदालत ने कहा है कि एमसीडी एक जगह खाना खिलाने के लिए जगह फिक्स करें, लेकिन हमारा मानना है कि इससे कुत्तों में लड़ाई हो सकती है और आम लोगों को भी इसकी सफाई की चिंता है, जो जायज है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं के बावजूद चिंतनीय रहेगा। अगर एमसीडी ठीक से काम करे तो यह मामला इतना बढ़ता नहीं। कई पशु प्रेमियों ने अपने खर्च से कुत्तों का टीकाकरण और देखभाल की है, अब एमसीडी को भी इस दिशा में जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारा मानना है कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

आक्रामक कुत्तों की पहचान और फीडिंग प्वाइंट की व्यवस्था पर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर विवाद और टकराव का सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक अदालत के आदेशों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता। एक तरफ डॉग लवर्स उन्हें खुला छोड़ने के पक्ष में हैं, जबकि दूसरी तरफ आम लोग चाहते हैं कि आवारा कुत्तों को शैल्टर्स में रखा जाए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से अन्यत्र ले जाए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों से मामले में सुनवाई से पहले एक सप्ताह के भीतर क्रमश: 25,000 रुपये और दो लाख रुपये जमा करने को कहा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विशेष पीठ ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग संबंधित नगर निकायों के तत्वावधान में आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सुविधाओं में किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, '' इस अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और प्रत्येक एनजीओ को सात दिन के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री में क्रमश: 25,000 रुपये और दो लाख रुपये जमा कराने होंगे। ऐसा न करने पर उन्हें मामले में आगे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।' फिर भी हमारा मानना है कि कुत्तों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण हो जाएगा।

दिल्ली या किसी शहर में भी कुत्तों का आतंक नहीं होना चाहिए लेकिन डॉग पकड़ने वालों पर हमले भी नहीं होने चाहिए। अभी कुत्तों की फीडिंग तथा नसबंदी टीकाकरण की चुनौतियां भी बरकरार हैं। फिलहाल एक बड़ा खतरा तथा टकराव सुप्रीम कोर्ट की योग्य पीठ ने अपने विवेक से टाल दिया है। डॉग लवर्स संगठनों व आम नागरिकों तथा अन्य नेताओं को भी इसका सम्मान करना चाहिए। हमारा देश दया व अहिंसा का देश है तथा यह जियो और जीने दो की नीति पर चलता है। जानवर या किसी इंसान पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, यही सोच कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200,45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
बैंगलौर विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

जीवन पर किसका कितना हक

इसमें कोई दो राय नहीं कि आवारा कुत्तों का उत्पात अब राष्ट्रीय आपदा का रूप ले रहा है। इसकी तत्काल रोकथाम जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की उस ताकतवर लॉबी को रोक पाएगा, जो हरदम इनके पक्ष में उठ खड़ी होती है?... हमें भूलना नहीं चाहिए, यदि पशुओं को प्रकृति प्रदत्त जीवन जीने का हक है, तो इंसानों को भी उनके जीवनाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की धरपकड़ से जुड़े मामले पर जो नया फैसला सुनाया, वह पशु-प्रेमियों व आवारा कुत्तों से आतंकित जन-समूह, दोनों की चिंताओं को संबोधित करता है। अदालत ने न तो इनके पकड़ने पर रोक लगाई और न ही बिना वैक्सीनेशन व नसबंदी के इनको छोड़ने का आदेश दिया। अब कोई सरेआम आवारा कुत्तों को भोजन नहीं दे सकेगा और प्रशासन को बड़ी संख्या में उनके लिए आश्रय बनाने होंगे।

अदालत ने अपने इस फैसले का दायरा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बढ़ाकर राष्ट्रीय कर दिया है।

इस महीने की 26 तारीख को अंतरराष्ट्रीय श्वान दिवस है। इस दिन को कुत्तों और इंसानों के बीच भावनात्मक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए समर्पित किया गया है। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा है। ऐसे में, यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय का यह दिशा-निर्देश क्या कुत्तों के आतंक पर प्रभावी रोक लगा सकेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने से पहले जरा हालात पर गौर फरमा देखिए।

वह गुजरे बुधवार का उजला सवेरा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने शासकीय आवास में जन-सुनवाई कर रही थीं। अचानक एक शख्स कागज दिखाता है, चीखते हुए कुछ कहता है और उन पर झपट पड़ता है। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी और मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं। अनहोनी टल जाती है।

पुलिस आक्रामक को हिरासत में ले लेती है। उसकी शिनाख्त राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी के तौर पर होती है। उसकी मां भानुबेन के अनुसार, राजेश पशु-प्रेमी है और वह आला अदालत के फैसले के अनुपालन में आवारा कुत्तों के खिलाफ चल रही कार्रवाई से क्षुब्ध था। क्या इस वजह से कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर किसी मुख्यमंत्री पर हमला कर सकता है?

रेखा गुप्ता पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले नई दिल्ली के केएन काटजू मार्ग थाने में नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन लोगों ने नगर निगम की उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आवारा कुत्तों की धरपकड़ में लगाई गई थीं। क्या पशुओं के साथ होने वाली हिंसा का विरोध करने वाले मनुष्यों के प्रति हिंसक हो सकते हैं?

हमारे देश में पशु-प्रेमियों का एक ऐसा वर्ग है, जो पूरी ताकत से ऐसे फैसलों और निर्णयों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है। ऐसा कहते वक्त मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कुत्ते सहित किसी भी पशु या पक्षी से कोई वैर नहीं है। खुद

आजकल

हमारे परिवार में 13 वर्ष तक एक जीव रहा था, जिसे हम प्यार से नीलू कहते थे। हमारे घर में उसका दर्जा भाई से कम नहीं था। यहां तक कि जब मेरा विवाह हुआ, तब मेरे ससुराल वालों ने उसके लिए मखमली कपड़ा भेजा था! वह इठलाता हुआ बारात में भी शामिल हुआ था। उसके गुजरने के बाद गुजरे 35 सालों में हमारे परिवार में नए सदस्यों की आमद हुई, लेकिन आज तक कोई उसे कुत्ता नहीं कहता।

वह हमारे लिए नीलू था, नीलू है।

हमारे बचपन में हर गली-मोहल्ले और गांव में ऐसे तमाम कुत्ते होते थे, जो अघोषित तौर पर उस इलाके की रखवाली करते थे। उन्हें समाज पालता-पोसता था। उनको इतना भोजन मिल जाता था कि वे आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करते थे। अब हालात बदल गए हैं। शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं और मोहल्ले सोसाइटियों में तब्दील हो गए हैं। कामकाज के सिलसिले में लोग अपना मूल स्थान छोड़कर बड़ी संख्या में देश या अपने प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बस रहे हैं। इसने सामूहिकता और साहचर्य की भावना को नए अर्थ प्रदान कर दिए हैं। इंसान और इलाकाई जानवरों के रिश्ते भी इससे

प्रभावित हुए हैं। पुराने दिनों में हम यह कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि आवारा कुत्तों के झुंड किसी वयस्क व्यक्ति को इस तरह भंभोड़ लेंगे कि उसकी जान ही चली जाए। अब देश के मुख्तलिफ हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें मिलती हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल सैकड़ों दर्दनाक वीडियो इसके गवाह हैं।

देश की राजधानी दिल्ली हो या कोई छोटा कस्बा, कुत्ते, बंदर, सांड़ या गाय कहीं भी, कभी भी लोगों की जान लेने को स्वतंत्र हैं। गाजियाबाद में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक ऋचा की त्रासदी इस मुद्दे की भयावहता को रेखांकित करती है। वह पिछले सोमवार की रात ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रही थीं। उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक आवारा कुत्ता आ गया। ऋचा ने जोर से ब्रेक लगाए, जिससे स्कूटी फिसल गई और उन्हें सांघातिक चोटें आईं। उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। सड़कों पर फिर रहे जानवर जानलेवा बन गए हैं। राज्य सरकारों के पास उन्हें सम्हालने की कोई योजना नहीं है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कोरोना महामारी से ऐन पहले 2018 में 'कुत्ता-काटे' की घटनाएं करीब 76 लाख तक पहुंच गई थीं। कोविड कालीन लॉकडाउन के दौरान इस दर में भारी कमी आई और 2021 में यह 17 लाख तक सिमट आई थी, लेकिन उसके बाद तो जैसे बाढ़-सी आ गई। साल-दर-साल इसके आंकड़े बजनदार होते जा रहे हैं। पिछले साल कुत्तों के काटने के 37.17 लाख मामले दर्ज किए गए। यानी औसतन 10 हजार रोजाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार, भारत में हर वर्ष 18 से 20 हजार लोग रेबीज से दम तोड़ जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रव्यापी निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में सही डाटा तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आवारा कुत्तों का उत्पात अब राष्ट्रीय आपदा का रूप ले रहा है।

इसकी तत्काल रोकथाम जरूरी है।

अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की उस ताकतवर लॉबी को रोक पाएगा, जो हरदम इनके पक्ष में उठ खड़ी होती है? इस मामले में लोगों को सबसे बड़ा अचंभा तो तब हुआ, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के परिवार के लगभग सभी सदस्य इस मुद्दे पर एक सुर में बोलते नजर आए। आप जानते हैं कि 1980 में संजय गांधी के दुखद अवसान के बाद गांधी परिवार में अप्रिय हालात पैदा हो गए थे। इंदिरा गांधी के जीते-जी संजय की पत्नी मेनका गांधी ने संजय विचार मंच बनाकर उन्हें चुनौती दी थी। तब से अब तक उनके सुर कभी नहीं मिले थे। दशकों बाद किसी मुद्दे पर इंदिरा गांधी की तीसरी पीढ़ी को एक स्वर में बोलता देख चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है। मुझे 'नेहरू-गांधी' परिवार की दयालु प्रवृत्ति पर कोई संदेह नहीं, लेकिन उन लोगों का क्या करें, जो साल-दर-साल कुत्तों और आवारा पशुओं के कारण जीवन गंवा रहे हैं?

हमें भूलना नहीं चाहिए, यदि पशुओं को प्रकृति प्रदत्त जीवन जीने का हक है, तो इंसानों को भी उनके जीवनाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। @shekharkahin

@shashishekhar.journalist

जीने की राह — **स्वप्निल माने**, डॉक्टर

काश! हर कस्बे को ऐसे डॉक्टर मिल जाते

गोडसे काका को रोज-रोज मरते हुए पूरा गांव देख रहा था। एक दिन उनकी पीड़ा देखकर रहा न गया, तो स्वप्निल ने मां से पूछा, 'आई, क्या काका का इलाज नहीं हो सकता?' मां ने बस इतना ही कहा था, 'बेटा, डॉक्टर सिर्फ उन्हीं को ठीक करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं।'

दुनिया के तमाम धर्मों ने सेवा को सर्वोच्च कर्म कहीं कहा? क्योंकि इनके प्रणेताओं को यह एहसास था कि एक दौर आएगा, जब इंसान इतना खुदगर्ज हो जाएगा कि समाज का अस्तित्व ही शायद खतरे में पड़ जाए। समाज को जोड़े रखने और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने सेवा, करुणा और परमार्थ को सर्वोच्च धर्म बताया। आज जब अपने ही देश में हम अस्पताल का बिल न भर पाने के कारण शव को बंधक रखने या इलाज न करा सकने के कारण गरीबों के तड़प-तड़पकर मरने की खबरें पढ़ते-सुनते हैं, तो स्वप्निल माने जैसे लोग हमें देवदूत लगते हैं!

आज से 43 साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनगांव में स्वप्निल पैदा हुए। पिता कॉपरेटिव बैंक में सहायक (चपरासी) की नौकरी करते थे और मां गृहिणी थीं। जाहिर है, पिता की मामूली तनख्वाह में किसी तरह परिवार का गुजारा हो पाता था। मगर माता-पिता, दोनों स्वप्निल की शिक्षा को लेकर जागरूक थे। वे उन्हें बड़े सपने देखने को प्रेरित करते। जिला परिषद का सरकारी स्कूल घर से दो किलोमीटर दूरी थी। नन्हे स्वप्निल को आते-जाते चार किलोमीटर की वह दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती। मगर उन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया।

पढ़ाई के प्रति बेटे का लगाव देख माता-पिता बहुत खुश होते, मगर एक बात उन्हें लगातार परेशान करती कि स्वप्निल की भविष्य की पढ़ाई संबंधी जरूरतें वे कैसे पूरी कर सकेंगे? बहरहाल, प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वप्निल को 12वीं तक के लिए शाहू महाराज विद्यालय लातूर से छात्रवृत्ति मिल गई। वह और मन लगाकर पढ़ने लगे। मगर उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी, जिसने स्वप्निल का भविष्य तय दिया।

तब वह आठवीं कक्षा में थे। पढ़ने में काफी होशियार होने के कारण गांव के सारे लोग उन पर खूब स्नेह लुटाते। पड़ोस के गोडसे काका भी उनमें शामिल थे। गोडसे काका दिहाड़ी मजदूर थे। रोजाना 50-60 रुपये कमाते, जिससे उनका परिवार चलता था। एक दिन वह ऐसा बीमार पड़े कि बिल्कुल बिस्तर से लग गए। पता चला, उन्हें कैंसर है। स्वप्निल के पिता ने थोड़ी-बहुत माली मदद की, मगर वह भी कितना कर पाते! गोडसे को रोज दर्द से कराहते, तड़पते और मरते हुए पूरा गांव देख रहा था। एक दिन उनकी पीड़ा देखकर रहा न गया, तो स्वप्निल ने मां से पूछा, 'आई, क्या काका का इलाज नहीं हो सकता?' मां का जवाब बेचैन करने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा था, 'बेटा, डॉक्टर सिर्फ उन्हीं को ठीक करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं।'

गोडसे काका बिना इलाज तड़पते हुए मर गए। मगर उसी समय स्वप्निल ने अपनी मां से वायदा किया- 'आई, मैं पढ़-लिखकर डॉक्टर बनूंगा और जिनके पास पैसे नहीं होंगे, उनका भी इलाज करूंगा।' मां की आंखें अनायास बरस पड़ी थीं।

स्वप्निल को यह बात लंबे समय तक परेशान करती रही कि अगर गोडसे काका के पास 40-50 हजार रुपये होते, तो वह ऐसी मौत न मरते!

सन् 1999 स्वप्निल के लिए एक यादगार वर्ष बनकर आया। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें प्रवर मेडिकल ट्रस्ट के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिल गया। साल 2005 में एडेड के साथ एमबीबीएस की डिग्री हाथ में थी। स्वप्निल के लिए अवसरों के अनेक दरवाजे खुल चुके थे, मगर उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें तो गरीब कैंसर मरीजों की सेवा करनी थी। उस वक्त माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपने तईं कुछ शुरू कर पाते, लिहाजा उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी में बतौर फेलो काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें काफी कुछ अध्ययन व शोध करने को मिला।

एक दिन वह अस्पताल के गलियारे से गुजर रहे थे, तभी उनकी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ी, जो हताश-मायूस खड़ा था। वह एक कैंसर रोगी था, जो अस्पताल तक तो किसी तरह आ गया था, पर उसके पास न इलाज के बिल चुकाने के पैसे थे और न घर लौटने तक का किराया था। स्वप्निल उसकी कैफियत समझ रहे थे। उन्होंने उस मरीज को तत्काल अपनी जेब से कुछ रुपये दिए और उसके इलाज की फीस के लिए एक एनजीओ से मदद मांगी। मदद मिली भी। इलाज पूरा होने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तो बेहद खुश था। बार-बार स्वप्निल के कदमों में झुक जाता। स्वप्निल ने उसी क्षण फैसला किया कि वह मुंबई नहीं, किसी गांव में इलाज करेंगे।

वह अपने राहुरी तालुका पहुंचे। स्वप्निल यह जानकर हैरान थे कि वहां प्रति 100 में से एक महिला को 'सर्वाइकल कैंसर' है, मगर पचास किलोमीटर तक न जांच की कोई सुविधा है और न विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। उन्होंने मामूली फीस पर मरीजों को देखना शुरू कर दिया। रोगियों की भीड़ उनके यहां उमड़ने लगी। इससे स्थानीय डॉक्टर नाराज हो गए। डॉक्टरों के संघ ने उन्हें नोटिस जारी कर तत्काल चैरिटी बंद करने को कहा। मगर स्वप्निल की पत्नी सोनाली माने पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहीं और दोनों ने उसी फीस पर गरीबों का इलाज जारी रखा।

गरीबों की दुआएं रायगां नहीं जातीं। कई अन्य डॉक्टरों ने स्वप्निल के साथ जुड़कर अपने जीवन को भी सार्थक बनाने की इच्छा जताई। वे सभी मिले, जुड़े और 'डॉ माने मेडिकल फाउंडेशन ऐंड रिसर्च सेंटर' की शुरुआत हो गई। साल 2011 से इस फाउंडेशन के तहत साईंधाम हॉस्पिटल ने भी काम करना शुरू कर दिया। बीते 14 वर्षों में स्वप्निल और उनकी टीम ने कैंसर की पहचान के लिए गांवों में 1,119 शिविर लगाए हैं। उनके अस्पताल में अब तक 18,000 गरीब मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन हो चुका है और लाखों लोगों की जिंदगियों में सुखद बदलाव आया है। निस्संदेह, स्वप्निल जैसों के कारण ही लोग आज भी डॉक्टरों को दूसरा देवता मानते हैं।

वह एक कैंसर रोगी था, जो अस्पताल तक किसी तरह आ गया था, पर उसके पास न इलाज कराने के पैसे थे और न घर लौटने तक का किराया था। स्वप्निल ने उसे तत्काल अपनी जेब से कुछ रुपये दिए और उसके उपचार की फीस के लिए एक एनजीओ से मदद मांगी। मदद मिल भी गई।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा — **शिवराम राजगुरु**, शहीद क्रांतिकारी

जब तिलक ने दुलारा और पहनाई माला

मौका देख वह तिलक के कमरे में जा घुसा। चरण स्पर्श किए। उसकी दृढ़ता को तिलक पहचान गए। उन्होंने स्नेह से उस बालक को दुलारा, उसे एक माला पहनाई और बोले, 'शिवराम, तुम्हारे जैसे बालकों के साहस और निर्भीकता से स्वराज्य का लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।'

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

बहुत पतली या सूखी-सी नदियां भी बारिश में सीना चौड़ा किए बहती हैं। वह नदी भीमा भी यही करती थी। भीमा हर बारिश में उस घर का स्पर्श करती थी, जिसमें उस हठी बालक का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के खेड़ गांव के उस घर में श्रावण मास के एक सोमवार को उसका जन्म हुआ, तो नाम भी शिवजी के ही नाम पर पड़ गया। पंडित ने बता दिया कि बालक भाग्यशाली है, तो सरल हृदय मां अक्सर अपने इस पुत्र को बापू साहब कहने लगीं। जिंदगी आराम से चल रही थी, पर एक दिन उसमें हलचल मच गई।

पूरे इलाके में शोर था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आए हुए हैं। वह बालक उन्हें सुनने के लिए सबसे पहले पहुंच गया। पहली पंक्ति में बैठकर एक-एक शब्द ध्यान से सुना। जादुई असर हुआ। तीसरी कक्षा का यह बालक किसी अन्य दुनिया में पहुंच गया। एक भाषण से मन न भरा, तो वहां पहुंच गया, जहां तिलक ठहरे थे। मिलने का आग्रह किया, तो बाहर खड़े लोगों ने उपहास उड़ाया, पर उसने तय कर लिया कि बिना मिले लौटना नहीं है। मौका देख वह तिलक के कमरे में जा घुसा। चरण स्पर्श किए। उसकी हिम्मत और दृढ़ता को तिलक पहचान गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उस बालक को दुलारा, उसे एक माला पहनाई और बोले, 'शिवराम, तुम्हारे जैसे बालकों के साहस और निर्भीकता से स्वराज्य का लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।'

अब तो बालक शिवराम का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। पहली बार स्नेह के साथ इतना सम्मान मिला था। शिवराम ने ठान लिया कि जताए गए विश्वास पर खरा उतरना है, मातृभूमि के काम आना है। पर यह घटना उनके बड़े भाई को पसंद न आई। उन्होंने छोटे भाई के गले से माला उतार फेंकी और फरमान सुना दिया कि वह इन कथित बड़े नेताओं द्वारा दिखाए गए आजादी के फिजूल सपनों के पीछे भागने के बजाय पढ़ाई में ध्यान लगाए।

यह समझाइश काम न आई। मन में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। शिवराम जिधर देखते थे, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय नजर आते थे। कुछ समय बीता, ब्रिटिश शासन के प्रशंसक बड़े भाई सरकारी क्लर्क बने और उनकी शादी भी हो गई। परिवार पैतृक खेड़ गांव से पुणे आ गया, जहां छोटे भाई से बड़े भाई का वैचारिक विवाद किसी बढ़ते पेड़ की तरह फैलता गया। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि बड़े भाई ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने सोलह वर्षीय भाई से कह दिया, अगर वह अपने कथित आपराधिक व्यवहार से अलग होकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, तो घर छोड़कर चला जाए।

बड़े भाई का बस इतना कहना था, छोटे भाई साहब ने तत्काल बड़े का चरण स्पर्श किया और स्वतंत्रता के आकाश की ओर उड़ चले। कई-कई दिन भूखे रहे, पेट पर पत्थर बांधकर भूख दबाने की भी नौबत आई, मगर मनोबल न टूटा। जीवन का पग-पग निर्णायक हो गया। यहां-वहां भटकते बनारस पहुंचे। वही बनारस, जहां पढ़ाए बच्चों को पढ़ाने वाले भी खूब मिलते हैं और भोजन कराने वाले भी। वहां संस्कृत पढ़ने में मन लग गया, पर मूल लक्ष्य था- मातृभूमि की सेवा और असली प्रतीक्षा थी कि आजाद से कैसे मुलाकात होगी? इस बीच वह अपने शरीर को बलवान बनाते रहे, क्योंकि मातृभूमि के लिए युद्ध में उतरना था।

तब क्रांतिकारियों के निर्विवाद मसीहा थे चंद्रशेखर आजाद। जब वह चाहते थे, तभी उनसे कोई मिल पाता था। महीनों प्रयास और अनेक परीक्षाओं के बाद कानपुर में शिवराम राजगुरु की भेंट आजाद से कराई गई। आजाद ने पूछा, 'आप क्रांतिकारियों में शामिल होना चाहते हैं?' जवाब मिला, 'हां, मैं चाहता हूं और इस दिशा में लगातार प्रयासरत हूं।' आजाद ने चेताया, 'यह जानते हुए भी कि इसका परिणाम गोलियों से छलनी शरीर, फांसी या निर्वासन हो सकता है?' राजगुरु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, 'हां, मुझे पता है, पर मैं इन निरर्थक परिणामों से भयभीत नहीं हूं।' आजाद ने वक्त जाया न किया। राजगुरु को अपने दल में शामिल कर लिया और कोड नाम रख दिया- रघुनाथ।

संसार जानता है, क्रांतिकारियों के इस दल में भीमा नदी वाले राजगुरु जब सतलुज के करीबी सुखदेव और राबी-चेनाब के पास वाले भगत सिंह से मिले, तब राष्ट्रभक्ति और शहादत का अमर इतिहास बन गया। तीनों में राजगुरु छोटे थे। 24 अगस्त को जन्मे राजगुरु जब अंतिम दिनों में लाहौर जेल में बंद थे, तब बड़े भाई नहीं आए। अंतिम बार मां मिलने आईं, पर रोईं नहीं। उनके दिलो-दिमाग में बेटे 'बापू साहब' शिवराम राजगुरु (1908-1931) के ही शब्द गूंजने लगे, 'मां, तुम्हारे दो बेटे हैं, बस इतना समझ लेना कि एक तुम्हारा है और दूसरा भारतमाता का।'

भीमा नदी आज भी बह रही है। उसके तट पर राजगुरु का वह घर आज भी है और खेड़ गांव का नाम राजगुरुनगर हो गया है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

हिंदी में 'मूंजी' यारों की कमी नहीं

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

अच्छी खबरें जलाती हैं और बुरी ठंडक पहुंचाती हैं। किसी को कुछ मिला, तो जला; किसी की किताब आई, तो चिढ़ा; किसी का सम्मान हुआ, तो बुरा लगा; कोई सेमिनार में बका, तो मन ही मन गरिआया; किसी का चेक आया और उसकी खबर फेसबुक पर देखी, तो पेट में मरोड़ उठी। किसी की रचना फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी में अनुदित होकर छप रही है, किसी की पंजाबी, गुजराती और मलयाली में छपने वाली है, जिसकी खबर उसने इंस्टाग्राम पर लगाई है। सच कहूं, दिल धू-धू कर जलने लगता है। इसे कोई भी 'फायर ब्रिगेड' नहीं बुझा सकती।

मगर यदि किसी लेखक ने किसी को 'शट अप' कर दिया, किसी ने किसी की पोल खोल दी, किसी ने किसी की चोरी पकड़ ली, किसी ने सबके आगे किसी को दुत्कार दिया, किसी ने किसी को 'अनफ्रेंड' कर दिया, किसी ने किसी को 'ब्लॉक' कर दिया, किसी ने किसी का 'बायकॉट' कर दिया, किसी ने किसी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया, किसी ने किसी को दो टके का लेखक कह दिया, किसी ने कह दिया कि फलां लेखक 'ओवर रेटेड' है, तो ऐसी हर खबर, ऐसी हर 'गप' देख-सुन मजा आता है।

ऐसे दुष्ट परिदृश्य में मुझे गोस्वामी तुलसीदास की *श्रीरामचरितमानस* याद आती है, जिसके उत्तरकांड में उन्होंने कहा है कि असंत का संग कभी न करना चाहिए, अगर किया, तो आप गए। असंतों के लक्षण बताते हुए वह कहते हैं- *काहू की जौं सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई।।/ जब काहू कै देखहिं बिपती। सुखी भए मानहुं जग नृपती।।* अगर तुलसी की इस दृष्टि से देखें, तो लगता है कि इन दिनों साहित्य में भी असंतों का ही बोलबाला है। उन्हीं की महिमा है और साहित्य में उन्हीं की चलती है। इसे देख मैंने भी संतों की राह छोड़ असंतों की राह पकड़ ली है और असंतों का भी असंत बनता जा रहा हूं।

एक मित्र लेखक ने आत्मकथा लिखी। मैं पूरी पढ़ गया, लेकिन उस मुए ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे कारनामे भी उसने अपने नाम कर लिए। बताइए, ऐसे को मैं क्यों सराहता? सो बदले में मैंने भी उसकी अच्छी तरह पूजा कर दी, फिर जब अपनी आपबीती लिखी, तो उसको अच्छी तरह ठिकाने लगाया। इसी तरह, मैंने जाना कि साहित्य का असली 'रूल' है- जैसे को तैसा। लेकिन यह अक्ल मुझे तब आई, जब 'चिड़िया चुग गई खेत' और मुझे अपनी मूर्खता पर पछताने तक का मौका न मिला।

बहरहाल, आलोचना की शुरुआती यात्रा में एक दिन मैंने पाया कि आलोचना ही साहित्य का सबसे बेहतरीन धंधा है। बड़े से बड़ा लेखक आलोचक के चक्कर मारता है कि वह उसकी नई किताब का अच्छा सा 'रिव्यू' कर, उसे महान बना दे। आलोचक की महिमा को देख मैं भी आलोचना के धंधे में कूद गया। तब से अब तक, पता नहीं कितनों की किताबों की समीक्षा की, लेख लिखे। जाने कितने स्वर्गीयों से ज्यादा नारकीयों, यानी जिंदा लेखकों को महान बनाया।

आह! वे भी क्या दिन थे, जब एक से बड़ा एक लेखक किताब भेजता, फिर फोन करता- 'पचौरी जी कैसे हैं? क्या लिख रहे हैं? किताब भेजी थी, जरा देख लेना।' मैं पचौरी से पचौरी जी बना रहता। मैं भी एक से एक घूरे पर गुलाल छिड़कता और बदले में धन्यवाद पाता। मगर अंततः लगा कि इस पुण्यकर्म में अगर कोई घाटे में है, तो वह मैं ही हूं। मैं सबको 'लिफ्ट' करता हूं, पर मुझे कोई 'लिफ्ट' नहीं करता। ऐसे में, एक बार जब एक मित्र लेखक का 'रिव्यू' का तकाजा आया, तो मैंने कह दिया कि यार! अब तक तुम्हारी सभी किताबों की समीक्षा मैंने की है, अब तुम भी मेरी इस नई किताब का 'रिव्यू' कर दो।

हे पाठको! वह दिन है कि वह दिन, न किसी का तकाजा आया और न किसी का धन्यवाद ही। तब समझ में आया कि 'मूंजी यार किसके, दम लगाए और खिसके' और तभी समझ आया कि हिंदी में 'मूंजियों' (मतलबियों) की कमी नहीं। तब से मैं भी 'मूंजी' बन गया!

कटाक्ष — **राजेंद्र धोड़पकर**

मर्यादा-उल्लंघन का परिणाम सदा घातक होता है

अमेरिका को जवाब

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर एक तरह से अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया कि यदि आपको भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने में परेशानी है तो आप उसे हमसे न खरीदें। ज्ञात हो कि भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है, उसके रिफाइंड उत्पादों के खरीदारों में यूरोप के साथ अमेरिका की भी गिनती होती है। यह तथ्य सामने रखकर भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दोहरे रवैये को बेनकाब करने का ही काम किया। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सफल न होने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस से तेल खरीदने को तुल तेकर जुर्माने के रूप में 25 प्रतिशत और टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस घोषणा पर 27 अगस्त से अमल होना है। ट्रंप का तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीदकर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है। यह बेतुका और हास्यास्पद आरोप है, क्योंकि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है, जिसके प्रति वे कठोर कदम उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। यूरोप भी बड़ी मात्रा में रूस से गैस खरीदता है। खुद अमेरिका रूस से उर्वरक खरीद रहा है। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरों अर्थात भारत पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जो अमेरिका एक समय मुक्त व्यापार की वकालत करता था और दुनिया भर के देशों पर इसके लिए दबाव डालता था, वह आज घनघोर संरक्षणवादी रवैया अपनाए हुए है। इस रवैये का परिचय ट्रंप के साथ-साथ अमेरिका के अरबपति कारोबारी भी दे रहे हैं। इस सबके बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ अपनी मनमानी टैरिफ नीति को लेकर चाहे जितने बड़े बोल बोलें, सच्चाई यह है कि भारत अब उनके दबाव में आने वाला नहीं है। उसे आना भी नहीं चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने यही संदेश देने के लिए यह कहा कि भारत ने अमेरिका से व्यापार वार्ता के मामले में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वस्तुतः यह नए भारत का संदेश है। यदि ट्रंप ने अपने मनमाने रवैये का परित्याग नहीं किया तो अमेरिका को और मुश्किल होगी, क्योंकि अब वह इस स्थिति में नहीं कि भारत जैसे देशों को अपनी ऐसी सामग्री खरीदने के लिए बाध्य कर सके, जो उपयोगी नहीं। वैसे भी अमेरिका मुख्यतः हथियार बेचता है और इसके लिए अस्थिरता एवं टकराव को बढ़ावा देता है। यह भी ध्यान रहे कि ब्रिक्स जैसे संगठन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए कमर कस रहे हैं।

सड़क सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न

पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में सिगरियावां स्टेशन के समीप ट्रक की टक्कर से आटो पर सवार नौ लोगों की मौत सड़क सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। पांच सीटों की क्षमता वाले आटो पर 13 यात्री सवार थे। जहां दुर्घटना हुई, वहां सड़क की चौड़ाई भी कम है, जबकि वाहनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और यातायात का दबाव है। सड़क सुरक्षा के लिए अभियान तो चलाए जाते हैं, पर इसमें निरंतरता नहीं होती। जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो प्रशासन सक्रिय जरूर होता है, पर कुछ दिनों बाद ही फिर वही स्थिति। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को जानें जा रही हैं। दुर्घटना के कारणों की पड़ताल करते हुए उसका निदान कर दिया जाए तो इसे कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गांव-कस्बों की बात तो दूर, राजधानी और जिला मुख्यालय तक में आटो चालक क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर हर दिन चल रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि इस तरह की दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। इसपर कड़ाई की जरूरत है, ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। आम जन को भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। बसों की छत पर और एक आटो में 12-13 यात्री बैठे हों तो वे सुरक्षित नहीं हो सकते। सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए इसकी निरंतर निगरानी की जरूरत है, ताकि लोगों का जीवन यात्रा के समय खतरे में नहीं पड़े।

कारणों की पड़ताल कर उसका निदान कर दिया जाए तो दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाला है?

आज का सवाल

क्या सर्जियो गोर की राजदूत के रूप में नियुक्ति से भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार होने के आसार हैं?

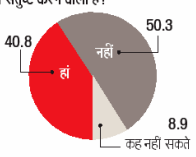

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

एक बुरे धंधे पर लगाम

संजय गुप्त

इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स को बढ़ावा देकर अपनी तिजोरी भरने वाली कंपनियों ने छद्म अनैतिक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली थी

मोदी सरकार की ओर से लोकसभा और फिर राज्यसभा में आनन-फानन पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशन आफ आनलाइन गेमिंग बिल, 2025 कानून में परिवर्तित हो गया और इसी के साथ उस पर अमल भी शुरू हो गया। इसके चलते कई आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने आनलाइन मनी गेम बंद करने शुरू कर दिए। जब से इंटरनेट का प्रसार एवं उसकी उपलब्धता बढ़ी है और मोबाइल फोन पर आनलाइन गेम्स का चलन बढ़ा है, तब से आनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसी कंपनियां भी आईं, जिन्होंने गेम की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का कारोबार शुरू कर दिया। पिछले कई वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित थीं कि पैसे के लेन-देन आधारित आनलाइन गेम्स कंपनियां गेम के नाम पर सट्टेबाजी का खेल खेल रही थीं। इस सट्टेबाजी के कारण तमाम लोग जुए की लत में अपना नुकसान कर रहे थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि सरकारों ने तो उन पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन संबंधित उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों के तर्कों को खारिज कर दिया और सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स को कौशल से जुड़ा खेल करार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसी कंपनियां अपना कारोबार खुलकर करने लगीं और इनमें से एक कंपनी तो भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक भी बन गई और उसका प्रचार नामी क्रिकेटर करने लगे।

यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार आनलाइन गेमिंग के नाम पर जारी सट्टेबाजी और जुए को लेकर चेती। उसकी ओर से आनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाना आवश्यक हो गया था। इस संदर्भ में जो कानून बनाया गया है, वह आनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर तो नियंत्रण की कोशिश है, लेकिन इसी के साथ वह कौशल वाले आनलाइन गेम्स को बढ़ावा भी देने वाला है। इन दोनों के बीच अंतर करना आवश्यक है, क्योंकि जहां आनलाइन सट्टेबाजी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रही थी, वहीं कौशल वाले आनलाइन गेम इंटरनेट आधारित एक नया उद्यम हैं। इन्हें पूरी दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है और लोग अपने कौशल एवं शौक के हिसाब से उन्हें खेलते हैं। इसकी प्रतियोगिताएं भी होने लगी हैं। चूंकि इनमें पैसे का कोई लेन-देन नहीं होता, इसलिए इन्हें बढ़ावा मिलने में हर्ज नहीं। आज करोड़ों लोग और विशेष रूप से युवा आनलाइन गेमिंग में रुचि रखते हैं। यह भी एक उद्योग का रूप ले चुका है और लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व उपलब्ध कराता है।

भारत का आनलाइन गेमिंग बाजार तेजी से बढ़ा है। 2023- 24 में यह

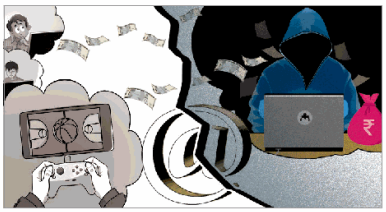

अवधेश राजपूत

23 प्रतिशत की दर से बढ़कर 3.8 अरब डालर तक पहुंच गया था। एक आंकड़े के अनुसार अपने देश में 2024 में आनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, लेकिन इस आकर्षक तस्वीर के पीछे उस बुरे धंधे की अनदेखी नहीं की जा सकती, जो खतरा बन गया था। यह खतरा सट्टेबाजी और जुए की लत बढ़ने के रूप में था। इस लत के चलते अनेक लोगों ने अपने लाखों रुपये गंवाए और हताश-निराश होकर आत्महत्या भी की। आत्महत्या के ऐसे कुछ मामलों का उल्लेख केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि आनलाइन मनी गेम्स की आड़ में हो रही सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन नाकामी मिली। सट्टेबाजी वाली आनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देकर अपनी तिजोरी भरने वाली गेमिंग कंपनियों ने एक अनैतिक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली थी। इसमें उपभोक्ताओं यानी आनलाइन गेमिंग के जरिये सट्टेबाजी करने वालों को न तो किसी तरह का संरक्षण प्राप्त था और न ही उनकी शिकायतों-समस्याओं की सुनवाई की कोई व्यवस्था थी। कुल मिलाकर मनमानी हो रही थी। अब इस मनमानी पर एक बड़ी हद तक रोक लगेगी, क्योंकि सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम का प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सट्टेबाजी कराने वाली आनलाइन कंपनियों को बैंक भुगतान प्रणाली से अलग किया जाएगा। अच्छा होगा कि सरकार नए कानून के हिसाब से नियामक प्राधिकरण जल्द बनाए, ताकि आनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर रोक लगने के साथ ई-स्पोर्ट्स और ई-खेल जैसे गेम्स का बेहतर नियमन हो, उनका बाजार बढ़े और रोजगार मिलने के साथ राजस्व भी मिले।

सट्टेबाजी और जुए की लत लोगों को बर्बाद ही करती है। जो कंपनियां लोगों को आनलाइन जुआ खिला रही थीं, उनके बारे में यह संदेह है कि वे मनी लांड्रिंग का भी काम करती थीं और उनका पैसा देश विरोधी गतिविधियों में भी खपाया जाता था। ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए 2021 में आइटी नियमों में संशोधन किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद भी कुछ लोगों का तर्क है कि अन्य देशों की तरह भारत में भी आनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के बजाय उनका नियमन किया जाना चाहिए। यह एक तर्क तो है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह एक कठिन काम है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इंटरनेट आधारित कंपनियां किस प्रकार हर तरह के नियमन का तोड़ निकालने में समर्थ होती हैं। अभी भी इसकी आशंका है कि ऐसी कंपनियां छल-छद्म से सक्रिय होने की कोशिश कर सकती हैं। सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा। सरकार की पहली प्राथमिकता एक बुरे धंधे से लोगों को बचाने की होनी चाहिए। इस धंधे की बुराई को इससे समझा जा सकता है कि एक अनुमान के मुताबिक अपने देश में लोगों को सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स के कारण सालाना 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा था। इन हालात में इस पर जोर देना ठीक नहीं कि आनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाने से सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही हजारों नौकरियां भी जाएंगी। फौरी तौर पर कुछ नौकरियां अवश्य जाएंगी, लेकिन क्या राजस्व के लोभ में सरकार एक अनैतिक और हानिकारक धंधे की अनदेखी कर दे? आखिर इस आवश्यक पहलू पर विचार क्यों नहीं किया जाता कि आनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों के जो हजारों करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे थे, वे अब उनके काम आएंगे और इसका लाभ किसी न किसी रूप में देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा।

response@jagran.com

सवाल के जवाब में सवाल

हास्य-व्यंग्य

मुकेश राठौर

जवाब देने से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सवाल के जवाब में ही सवाल दाग दिया जाए

एक पुरानी फिल्म आई थी-ससुराल। उसमें एक गाना था, 'एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो' में मंच से नायक-नायिका परस्पर अनेकानेक सवाल करते हैं। माने सवाल के जवाब में फिर एक और सवाल। यूं तो सवाल का सवाल नहीं, जवाब हुआ करता है, जिसकी अपेक्षा की जाती है। घड़ी भर को 'ककार' हटाकर सवाल को ही दोहरा दिया जाए, यहां तक भी ठीक है, लेकिन जब सवाल के जवाब में सवाल आगे विस्मयादिबोधक और पीछे प्रश्नवाचक चिह्न लगाकर आ खड़ा हो...तो अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती है। सवाल-जवाब का जन्मदाता है। एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, जैसे एक पिता की कई संतानें। इन दिनों सवाल पूछने वालों की तुलना में जवाब देने वालों की संख्या तेजी से घट रही है।

आज हर सवाली सवाल पूछकर अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाह रहा है। यही उत्सुकता सामने वाले की भी है। अफसोस कि जवाब देकर कोई भी उन्नीसा नहीं होना नहीं चाहता। गोया सवाल राजा, जवाब प्रजा हो गया। पिता निठल्ले बेटे से सवाल करते हैं 'फालतू यहां-वहां फिरते रहते हो कुछ काम-धंधा कर लो? बेटा जवाबी सवाल करता है 'यह भी कोई छोटा काम है क्या? मां बेटी से सवाल करती है 'इतनी रात गए कहां से आ रही हो?' बेटी प्रत्युत्तर में पूछती है 'आप अभी तक क्यों जाग रही हो?' छात्र शिक्षक से गुहार लगाता है कि सर कल जो सवाल हल करवाए थे, आज फिर से समझा देंगे क्या? जवाबी कार्रवाई करते हुए शिक्षक पूछते हैं 'पहले तो यह बताओ कि कल स्कूल क्यों नहीं आए?' मरीज सिर खुजलाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि डाक-साब पूरा कोर्स लेने के बावजूद खुजली नहीं जा रही? डाक्टर पूछते हैं, 'तुम खाने में क्या ले रहे हो?' अड़ोसी-पड़ोसी से सवाल करता है कि तुम बार-बार हमारे आंगन में कचरा क्यों फेंक देते हो? पड़ोसी उलटा सवाल दागता है कि 'तुमने हमारा पानी क्यों रोका? ऐसे में कोई मनोविज्ञानी यही सुझा सकता है कि जवाब देने से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि सवाल के जवाब में धड़ाधड़ सवाल दाग दो। इससे होगा यह कि सवाली जवाब दे न दे, मगर अब और सवाल करने को लेकर सोच-विचार में पड़ जाएगा। तब आदमी न कुछ पूछ पाता है और न कह पाता है।

लोगों के आपसी सवालों से इतर देश के सामने भी कुछ सवाल होते हैं। ऐसा ही एक सवाल इन दिनों बिहार में लाखों वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटने के रूप में उठ रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि नाम कटा आदमी महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के दौरान तमाम सवालों से दो-चार तो होगा ही। आखिर नाम कटना भी नाक कटने से किसी तरह कम थोड़े होता है। मंच पर स्वागत सूची से नाम कटे या पंगत हेतु निमंत्रण सूची से, नाम कटना हमेशा पीड़ादायी होता है। वोटर लिस्ट से नाम कटना इसलिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके जरिये कई सूचियों में नाम जुड़ता जो है। हाल तो ये है कि जिसका वोट कटा उससे कहीं ज्यादा चिंता उन्हें है 'जिनका वोट कटा।' आपके एक वोट की कीमत आपको भले पता न हो, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है, जो आपसे वोट मांगते हैं। दो रोटी मांगने पर संभव है कि एक ही घर से मिल जाए, लेकिन एक वोट के लिए कई बार मोहल्ले भर झोली फैलाकर और खंसे फुलाकर घुमना पड़ता है। आहत लोग सवाल कर रहे हैं कि जिनका नाम एक जगह भी नहीं रहने दिया, वे बेचारे कहां जाएंगे? 'वे' ज्ञान दे रहे कि आपका नाम दो जगह से कैसे जुड़ गया?

response@jagran.com

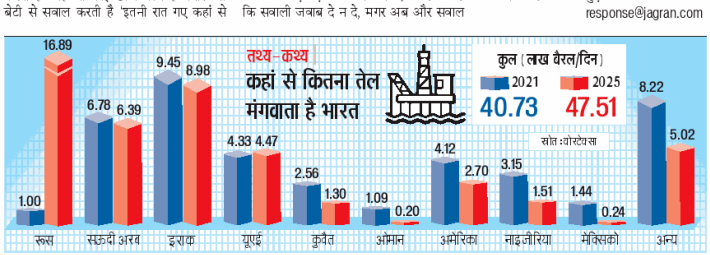

ऊर्जा

स्मृति-विस्मृति

प्रत्येक व्यक्ति का मन अनेक गतिविधियों और उनसे संबद्ध समस्याओं में आजीवन बंधा रहता है। वह कितना भी तीक्ष्णबुद्धि हो, विचारों तथा भावों के संग्रहण की उसकी क्षमता सीमित है। अतः मनुष्य को इस प्रकार निर्मित किया गया कि कालांतर में उसकी स्मृतियां तेजी से विलुप्त होती रहें। विस्मृति की गति विचार की गति से तीव्र है। अतीत की भारी हानि, भयावह परिस्थिति, खतरा अथवा अन्य कोई घटना मनुष्य को हतप्रभ कर देती है। विदारक घटनाएं मस्तिष्क से निष्क्रासित नहीं होंगी तो खानपान, निद्रा तथा दैनंदिन कार्य बाधित होते रहेंगे। वह असंतुलित रहने लगेगा, और स्वयं पर तथा दूसरों पर बोझ बन जाएगा। विस्मृति दोष नहीं, वरदान है। यह हमें अतीत के अवांछित, अप्रिय प्रसंगों से विमुक्त कर वर्तमान में जीना सिखाती है, ताकि पूर्णता से जीने के लिए उत्साह बना रहे। हालांकि स्मृति सशक्त होगी तभी अर्जित ज्ञान, कौशल, सूझबूझ और अनुभव को संरक्षित और संवर्धित किया जा सकेगा। प्रारंभ में पढ़ी-सीखी मूल जानकारी और अवधारणाएं स्मरण नहीं रहेंगी तो शिक्षार्थी का उच्चतर स्तर तक पहुंचना दुष्कर होगा।

जिन विषयों में अभिरुचि होगी, वे स्मृति में सहजता से अंकित हो कर टिके रहेंगे। किन विचारों, धारणाओं, मान्यताओं और व्यक्तियों को सहेजना, संरक्षित रखना है तथा किन्हें मन-चित्त में सायास स्थान नहीं देना, इसका विचार और अभ्यास अर्थपूर्ण जीवन की आधारशिला है। तनाव, अनिद्रा, दवाओं के सेवन या व्यसन की अवस्था में स्मृति का क्षरण होता है, ऐसा बारंबार हो तो उपचार लेना चाहिए। शारीरिक एवं बौद्धिक सक्रियता, उचित खानपान, सकारात्मक सोच और व्यसनों पर नियंत्रण से स्मरण शक्ति को चिरकाल तक जीवंत रख सकते हैं। कितना अद्भुत है, जो हम भूल गए, उसका स्मरण जीवन को वैविध्य और सुखद बनाता है।

हरीश बड़थ्वाल

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

श्रेय लेने की होड़

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का भले ही सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले किस दल ने की, इसका श्रेय लेने को लेकर उनमें होड़ मची है। हाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग के तीखे पलटवार के बाद एक मंच पर एकजुट हुए विपक्षी दलों के बीच इसका श्रेय लेने की यह लड़ाई साफ दिखी। स्थिति यह थी कि सपा नेता रामगोपाल के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मतदाता सूची की गड़बड़ियों को सबसे पहले उठाने का श्रेय अपने नेता अखिलेश यादव को दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की बारी आई तो उन्होंने अपनी नेता ममता बनर्जी को इसे सबसे पहले उठाने का श्रेय दिया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की बारी आई तो उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी को इसे पहले उठाने का श्रेय दिया। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष में शामिल और कौन-सा दल इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने का श्रेय लेते दिखता है।

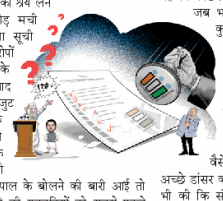

डांसिंग अर्थविद

वैसे तो वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अभी पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल कई बार अर्थनीति पर अपने

राजरंग

सोच एवं पुस्तकों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी नृत्य कला को लेकर है। हुआ यह कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ब्रेक के दौरान जब भारतीय परंपरागत डांस हो रहा था तब कुछ नर्तकों ने उन्हें घेर लिया। घेरा तो अन्य व्यक्तियों को भी गया था, लेकिन वे निकल गए, पर सान्याल ने नर्तकों के साथ ताल में ताल मिला दिया। वहां पर लोगों ने तालियां जमकर बजाईं। कुछ ही घंटे में देश के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार का डांस वायरल हो गया, बाद में उन्होंने सफाई भी दी। वैसे अपने मित्रजनों में उनकी पहचान एक अच्छे डांसर की पहले से ही है। कुछ लोगों ने टिप्पणी भी की कि संजीव सान्याल की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन डांस पर नहीं।

तारीफ या तंज

अपनी धरती पर गर्व सभी करते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि यह गर्व कब, कहां और किस परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया गया है। हाल में जब राज्यसभा में आइआइएम, गुवाहाटी से संबंधित विधेयक पर चर्चा चल रही थी, तब गुजरात के भाजपा सांसद रामभाई हरजीभाई मोकरिया ने भी विचार रखे। सरकार के कामकाज की तारीफ करने पर तालियां बजीं, लेकिन अचानक वह बोल पड़े-'जैसे गुजरात देश का मार्गदर्शन करता है, वैसे ही आइआइएम, अहमदाबाद भी आइआइएम, गुवाहाटी का मार्गदर्शन करेगा।' उस समय विपक्ष तो सदन से वाकआउट कर चुका था, लेकिन शायद सत्तापक्ष के ही अन्य राज्यों के सांसदों को मोकरिया की बातों में गर्व से अधिक अभिमान महसूस हुआ। रोकटोक या सीधी टिप्पणी 'अनुशासनहीनता' मानी जा सकती थी, इसलिए पीछे बैठे सदस्यों की प्रतिक्रिया थी- 'क्या बात है... क्या बात है...।' संभवतः सांसद मोकरिया को समझते देर न लगी कि इस तारीफ में कहीं न कहीं तंज है। तभी भाषण रोककर, पीछे मुड़कर प्रतिक्रिया दी- 'हां, यह सही बात है।'

समय की नजाकत

बिहार विधानसभा चुनाव में खेमा स्पष्ट बंटा हुआ है, पर लोजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लगातार ऐसे बयान आ रहे थे जिससे लग रहा था कि उनका खेमा स्पष्ट नहीं है। बिहार में अपनी ही सरकार पर अंगुली उठाकर वह यह संदेश देना चाहते थे कि निष्पक्ष हैं। अपना ग्राफ बढ़ाने का यह तरीका उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन बताते हैं कि उन्हें संदेश दे दिया गया है कि समय की नजाकत को पहचानें। दो नाव पर पांव रखना खतरनाक है। उसके बाद से ही वह थोड़े संयमित हो गए हैं।

पोस्ट

ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में राजदूत और दक्षिण, मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी बनाया है। इससे पहले ओबामा प्रशासन ने 2009 में दक्षिण एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था, जिनका भारत में गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया गया। मोनिका वर्मा@TrulyMonica

गोर की दक्षिण एवं मध्य एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्ति में भारत के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक पहलू यह भी देखा जा सकता है कि अमेरिका इन दो क्षेत्रों का कामकाज नई दिल्ली से संचालित करना चाहता है।

माइकल कुगेलमैन@MichaelKugelman

चूंकि गोर की गिनती ट्रंप के बेहद करीबी भरोसेमंद लोगों में होती है, इसलिए संभव है कि उनके आने के बाद भारत की व्हाइट हाउस से सीधी कड़ी जुड़ जाए।

शशांक मट्टू@MattooShashank

ट्रंप के टैरिफ वार के बाद भारत फ्रांस, रूस जैसे प्रमुख रणनीतिक सहयोगियों से अपने संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और संभवतः चीन के साथ भी। इस अस्थिर समय में दांव लगाना समझदारी भरा कदम हो सकता है। विक्रम चंद्रा@vikramchandra

जनपथ

भीषण होती हार है जब फूटे परिवार,
झेले तेजप्रताप का तेजस्वी जी वार।
तेजस्वी जी वार संभलता ना अपना घर,
ले राहुल को साथ टापते रहिए घर - घर !
जो रावण का हाल कराए जाय विभीषण,
वही दुर्दशा आप कराओ अपनी भीषण !!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द विपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 133

****

साहित्य

कहानी

साइकिल की सवारी

■ सुदर्शन

भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ, भगवान ने ये दोनों विद्याएँ भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलियुग की ये दोनों विद्याएँ नहीं लिखी गईं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यों हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हमीं जमाने भर के फिसड्डी रह गए हैं! सारी दुनिया चलाती है। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, परवाह नहीं।

दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमतीजी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। ?

श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा 'इन कपड़ों में अब जान ही कहा है कि मरम्मत करूँ! इन्हें तो फेंक दिया था। आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए।'?

हमने मुस्कुराकर कहा, 'तुम हर समय बहस न किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूँढ़ ढाँढ़ कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो।'?

मगर श्रीमती जी बोलीं, 'पहले बताओ, इनका क्या बनेगा?'

झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज ताँगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे।

श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोलीं, 'मुझे तो आशा नहीं कि यह बेल आपसे मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न करके देख लीजिए। मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा?'

हमने जरा रोब से कहा- 'आखिर बाइसिकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं, वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। जो बुद्धिमान हैं, वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं।

हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मँगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी।

हमने इधर बाजार जाकर जंबक के दो डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया, ताकि दूसरे दिन से साइकिल-सवारी का अभ्यास किया जा सके।

अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएँ। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मीनारायण आ गए और बोले, 'क्यों भाई हो जाए एक बाजी शतरंज की?'

हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, 'नहीं साहब! आज तो जी नहीं चाहता।'

तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, 'अरे भाई मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया?'

हमने कहा, 'तिवारी भैया, क्या कहें? सोचा था, लाओ, साइकिल की सवारी सीख लें। मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में?'

तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आँखों से ऐसे देखा, मानों हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, 'मेरी मानो तो यह रोग न पालो। इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे? और यह भी कोई सवारियों में कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ूँ बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर आओ एक बाजी खेलें।' मगर हमने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फुँका जाता है। हमने कहा, 'भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे। कोई आदमी बताओ।'

'आदमी तो है ऐसा एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा। फीस लेगा। दे सकोगे?'

'कितने दिन में सिखा देगा?'

'यही दस-बारह दिनों में!'

'और फीस क्या लेगा हमसे?'

'औरों से पचास लेता है। तुमसे बीस ले लेगा हमारी खातिर।'

हमने सोचा दस दिन सिखाएगा और बीस रुपये लेगा। दो रुपये रोजाना अर्थात् साठ रुपये महीना और वो भी केवल एक दो घंटे के लिए। ऐसी तीन चार ट्यूशनें मिल जाएँ तो ढाई-तीन सौ रुपये मासिक हो जाएँगे। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाओ जाकर मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और तीन-चार सौ रुपये मासिक कमाने लगे।

इधर तिवारी जी मामला तय करने गए इधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे तीन-चार सौ रुपये मासिक आमदनी होगी।

श्रीमती जी बोली, 'तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन न गया। पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोलना। मैं तो समझती हूँ कि तुम ही न सीख सकोगे दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है।'

हमने बिगड़कर कहा, 'यह बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो। पहले तो शायद सीखते या न सीखते, पर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी।'

श्रीमती जी बोली, 'मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ। यह बाइसिकिल क्या चीज है? मगर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे, तो देख लेना वहीं साइकिल फेंक-फाँककर चले आओगे।'

इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से प्रणाम किया।

तिवारी जी बोले, 'यह तो बीस पर मान ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे। कहते हैं, पीछे कोई नहीं देता।'

अरे भाई हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह बस चलाना सीखा दें, फिर देखें, हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं।'

मगर उस्ताद साहब नहीं माने। बोले, 'फीस पहले लेंगे।'

'और यदि आपने नहीं सिखाया तो?'

'नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे।'

'और यदि नहीं लौटाया तो?'

इस पर तिवारी जी ने कहा, 'अरे साहब! क्या यह तिवारी मर गया है? फीस लेकर भाग जाना कोई हँसी-खेल है?'

जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, 'उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना। हम तैयार रहेंगे। हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है, उससे साइकिल भी माँग ली है।'

तिवारी जी और उस्ताद जी चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पाँव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। हमने हाँफते-हाँफते कहा, 'उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लारेंसबाग में जो मैदान है, वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है। दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है।'

अब रात को आराम की नींद कहाँ? बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आँखें फाड़-फाड़ के देख रहे थे।

अब आँखें खुली तो दिन निकल आया था। नौकर को भेज कर मिस्त्री से साइकिल मँगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम लारेंसबाग की ओर चले। बाजार पहुँच कर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हँस रहा है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उलटे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हँस रहे हैं।

हमने उस्ताद से माफी माँगी और घर लौट आए अर्थात् हमारा पहला दिन मुफ्त में गुजरा।

दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, 'मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ। आप जरा साइकिल को थामिए।'

उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर-नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़ कर चलने लगे। मगर दो ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है।

इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न यह था कि क्या करना चाहिए? युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएँ? सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है। इसके सामने हम क्या चीज हैं। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पाँव पर गिर गई और हमारी रामदुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूँजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपनी घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री के दुकान पर भेज दी।

मगर हम अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए। आठ-नौ दिनों में साइकिल चलाना सीख गए थे। लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचा मार लिया मैदान हमने। दो चार दिन में पूरे मास्टर बन जाएँगे, इसके बाद प्रोफेसर प्रिंसिपल, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज फिर तीन-चार सौ रुपये मासिक। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए।

अब हम साइकिल चलाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी सौ गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़-फाड़कर चिल्लाना शुरू कर देते - साहब! बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखे। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दिया कि तिवारी जी, बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे।

तिवारी जी ने मुस्कुराकर कहा- 'जरा एक बात तो सुनते जाओ।'

हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, 'इस समय बात सुन सकते हैं? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं।'

तिवारी जी बोले, 'तो क्या जो साइकिल चलाते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर आओ।

हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को सँभालते हुए जवाब दिया, 'उतर आएँगे तो चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है चढ़ना नहीं सीखा।'

तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए, हम आगे निकल गए।

इतने में सामने से एक ताँगा आता दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से ही डाँट दिया, 'बाईं तरफ भाई। अभी नए चलाने वाले हैं।'

ताँगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक ताँगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पाँव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही ताँगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए।

जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बँधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमतीजी ने कहा, 'क्यों? अब क्या हाल है? मैं कहती न थी, साइकिल चलाना न सीखो! उस समय तो किसी की सुनते ही न थे।'

हमने सोचा, लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें। बोले, 'यह सब तिवारी जी की शरारत है।'

श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 'यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस ताँगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर आएँगी और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएँगी।

हमने निरुत्तर होकर आँखें बंद कर लीं।

उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ न लगाया।

■ उदय प्रकाश

दास्तान-ए-ला-पता

बहुतेरे ऐसे लोग-बाग़ हैं, जो अब उन पतों पर नहीं रहते
जहाँ वे वर्षों से, कभी-कभी तो कई पीढ़ियों से हमेशा पाए जाते थे ।

बहुत-से ऐसे गाँव-मोहल्ले, दूकान,
क़िले, घर और बग़ीचे अब उजाड़ हैं
बीयाबान
निर्जनता और ख़ामोशियाँ भय और
रहस्य के भारी-भरकम जूते पहने
दिन-रात वहाँ गलियों में टहलती है

वहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और ले
जाया गया है
या वे ख़ुद ही किसी रात या दिन की
परछाइयों में चुपचाप अपने पीछे
छोड़ गए हैं अपने पुराने पते

ये जगहें और उनके पुराने पते अब
सिर्फ़ उनकी स्मृतियों के अतीत में होंगे
जल उठते होंगे वे कभी-कभी किसी
बीमार पुराने बल्ब की तरह
उनके अपने धुन्धले जीवन में, अगर वे
अभी भी किसी दूसरे पते पर मौजूद हैं

यहाँ तो अब सन्नाटा बजता है
सायरन या नारे या एम्बुलेंस का अलार्म
की आवाज़ में

वे लोग जहाँ कहीं भी हैं
उनका हर रोज़ एक कोशिश है
ग़मज़दा, कठिन और दारुण
अपने छूटे पतों पर लौटने की, जिन्हें
अब भी वे न भूलने के लिए अक्सर
चुप हो जाते हैं

पिछले कई वर्षों-दशकों से, मुग़लों-
अँग्रेज़ों से लगाकर आज तक
किसी को लौटते हुए नहीं देखा गया
जो जाता है, लोग-बाग़ डरे हुए या
मुस्कुराते हुए कहते हैं — 'वह चला
गया !'
सरकारी और पँजीकृत चिट्ठियों के
लिफ़ाफ़ों पर लिखता है पड़ोसी —
'इस नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर
नहीं रहता ।'

महाकाव्यों और पॉप्युलर फ़िल्मों में
ज़रूर ऐसा पाया जाता है
उसके नायक या पात्र कई-कई साल
किन्हीं जँगलों-कन्दराओं के
अज्ञातवास में गुज़ारकर
किसी कालजयी विजेता की तरह
लौटते हैं दूँदुभियाँ-नगाड़े बजाते,
ध्वजाएँ फहराते

यथार्थ में जो लौटता है वह एक हारा
हुआ आदमी होता है बीमार बूढ़ा
भगोड़ा या फ़रार अपनी पहचान और
चेहरा छुपाता हुआ

कभी-कभी किसी गए हुए ला-पता का
शव ही लौटते देखा गया है
लोग उसे किसी विरक्त निस्पृहता के
साथ
आसपास की नदी या तालाब के किनारे
फूँक कर अपने घरों को लौट आते हैं

मरने के बाद न चाँद रहता है न सूरज
न हवा न पानी
सिर्फ़ मरे हुए की स्मृतियाँ रहती हैं
अन्तरिक्ष में
मरने के बाद पुराने पते पर लौटना
असम्भव है

जो जीवित होता है वही लौटता है

अगर कभी कोई तुमसे कहे
उसने किसी मृतक को देखा है नए
कपड़ों में बाज़ार में कुछ ख़रीददारी
करते हुए
खाते-खिलखिलाते हुए अपने जीवित
बचे परिवार के साथ
या उसे देखा है किसी बहुत पुराने छूटे
हुए वीरान ईंटहे घर की खिड़की से
बाहर की ओर
चुपचाप टकटकी बाँधे कुछ
निहारते हुए

तो मान लेना कि यह सच है

वैसा ही सच जैसे कोई कहे कि उसने
16 मई 2019 को देखा है
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को क़ाज़ी
नज़रुल इस्लाम के साथ
कोलकाता के भरे बाज़ार में दिन-
दहाड़े घूमते और गाते हुए

या कोई अपनी भाषा से निर्वासित
सनकी कवि अगर कहे
हर साल और यह कोई अजूबा नहीं कि
30 जनवरी की कड़कड़ाती ठण्ड में
एक बूढ़ा शाल ओढ़े लाठी टेकता
दिल्ली में टहलता दिखता है
तीस जनवरी लेन के किसी सेठ के पते
की ओर अकेले पैदल जाते हुए

(अपने बेहद प्रिय कथाकार मंज़ूर
एहतेशाम से शीर्षक के लिए क्षमा
माँगते हुए।)

अपने समय और समाज का भाष्य करती कविताएं

पुस्तक समीक्षा

सुरेश गुप्ता अपने पहले कविता संग्रह के प्राक्कथन में लिखते हैं कि 'कविता की बात कही जाए तो उसके उस संग्रह - असमय का अंधेरा' की कविताएं पढ़कर लगा कि सुरेश ने जो कुछ भी और जिस परिप्रेक्ष्य में और जिस शैली में भी लिखा है वो कविता ही है और अच्छी कविताएं हैं । क्षमा करें सुरेश, आपका यह सोच सही नहीं है कि कविता आपके बूते की बात नहीं हैं, आपने अच्छी कविताएं लिखी है और इस लेखन कर्म को निरन्तर रखियेगा।मुझे लगता है कि सुरेश ने इस बात का उल्लेख भले ही न किया हो मगर सरकारी कामकाज की एकरसता से ऊबकर मन में अपने परिवेश और घटित-अघटित को लेकर जो एक भाव मन में उठता है उसकी अभिव्यक्ति के कई माध्यम हो सकते हैं उनमें संस्मरण और कविताएं अहम् हैं और सुरेश ने दूसरा विकल्प चुनकर उस भावभूमि पर अच्छी कविताएं लिखीं हैं और सभी कविताएं अपने समय और समाज का भाष्य करती है।

सुरेश के संग्रह की शीर्षक कविता - 'असमय का अंधेरा' में जो दिन में होने वाले अंधेरे के कचोटने वाली बात लिखी है, वो बात संग्रह की कई और कविताओं में भी इसी परिप्रेक्ष्य के साथ सामने आई हैं । जब वे कहते हैं-'कुछ पा लिया / कुछ छूट गया /जो छूटा / उसमें / वो रास्ता भी रहा / जो तुम तक / जाता था।' उस एक तुम तक रास्ते के न जा पाने की बात भी असमय अंधेरे के मानिंद ही तो है। उन्हें संस्कारों का अधःपतन भी कचोटता है तभी तो वे लिखते हैं - 'और तब बच्चे / बड़ों के पदचिह्नों पर / चलने के जगह / उन्हें मिटाकर आगे बढ़ना सीख लेंगे।' उन्हें संस्कारों का यह अधःपतन भीतर तक कचोटता है।

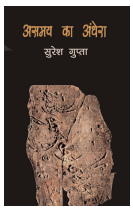

उनकी कविताओं का मूल स्वर आशावादी हैं

वे लिखते हैं 'किसी को हो न हो / मुझे पूरी आस है / किसी दिन - किसी एक पल में /कविता की एक पंक्ति के कलरव से / टूटेगी सन्नाटे की नीरवता।' सुरेश की तलाश सन्नाटे को तोड़ने वाली उसी कविता की एक पंक्ति तक सीमित नहीं है, वे कविता के जरिए बदलाव का संदेश भी देते हैं । उनकी कविता में प्रचलित मुहावरे भी है और एक कविता में जब वो बोलचाल में प्रचलित 'उखाड़ लेना' वाला मुहावरा लिखते हैं तो वह सर्वथा सहज लगता है जबकि यह एक निषिद्ध मुहावरा माना जाता है। कविता के माध्यम से यादों में उतरना और डूबना तथा अपने पैतृक कस्बे खिलचीपुर के बारे में लिखकर यादों के गलियारे में सब कुछ याद करना, अपनी जड़ों की ओर लौटना तथा बदलाव के प्रति अप्रसन्नता को शब्द देने में भी सुरेश ने अच्छे दृष्टांत गढ़े हैं ।

इस संग्रह में सुरेश द्वारा अपने दो दिवंगत मित्रों मनोज पाठक और महेन्द्र गगन के लिये लिखी गई कविताएं भी शामिल हैं। मनोज की स्मृति में लिखी गई कविता - 'उसकी बात ही कुछ ओर थी' में वे एकदम दिल खोलकर लिखते हैं -

'साथ था तो हरदम / अपने होने की याद दिलाता था / और अब जब नहीं है वो तो /अपने नहीं होने की भी हरदम याद दिलाता है।' इन पंक्तियों में मनोज के प्रति उनकी संलग्नता और बेजोड़ लगाव परिलक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार महेन्द्र गगन की स्मृति को समर्पित कविता में भी उन्होंने लिखा कि - ''महेन्द्र का होना / महफ़िल का होना था' और इस कविता का चरम देखिए - 'मेरे लिये महेन्द्र का होना / नेक इन्सान होने का उत्सव होना था।'

सुरेश की कविता छन्दबद्ध नहीं है मगर विधा का अनुशासन उनमें है। सूक्ष्म, सरल और सुबोध भाषा , विधागत अनुशासन और? विषय की विविधता से सुरेश की कविताएं श्रेष्ठता की मुनादी करती लगती है ।

■ राजा दुबे

एक ठगे गए मृतक का बयान

■ उदय प्रकाश

जो बेतरह ठगा गया है, ठग उसे देख कर हंसे जा रहे हैं
जो ठग नहीं भी हैं, वे भी हंस रहे हैं
लेकिन जो ठगा गया है, वह प्रयत्न करता है हंसने का
और आख़िरकार हंसता है वह भी एक अजब तरीके से

उसकी हंसी में कोई ज़मानाा है जहाँ वह लाचार है

जिसे मार दिया गया है वह मरने के बाद बेचैनी से अपना
चश्मा ढूँढ़ रहा है
उसे वे चेहरे ठीक से नहीं दिखे थे मरने के पहले
जो उसकी हत्या में शामिल थे
कुछ किताबें वह मरने के बाद भी पढ़ना चाहता है
जो मरने के ठीक पहले मुश्किल से ख़रीदी गई थीं तमाम
कटौतियों के बाद

वह मरने के पहले कोई सट्टा लगा आया था
अब वह जीत गया है
लेकिन वह जीत उधर है जिधर जीवन है जिसे वह खो
चुका है

एक सटोरिया हंस रहा है
बहुत से सटोरिये हंस रहे हैं
उन्हीं की हुकूमत है वहाँ, जहाँ वह मरने से पहले रहता
था

अरे भई, मैं मर चुका हूँ
तुम लोग बेकार मेहनत कर रहे हो
कोई दूसरा काम खोज लो
हत्या के पेशे में नहीं है इन दिनों कोई बेरोज़गारी

एक बात जो वह मरने से पहले पूछना चाहता था कवियों
से
वह बात बहुत मामूली जैसी थी
जैसे यही कि तुम लोग भई जो कविताएँ आपस में
लिखते हो
तो वे कविताएँ ही किया करते हो

या कुछ और उपक्रम करते हो

इस कदर हिंसा तो कवि में पाई नहीं जाती अक्सर ऐसा
पुराने इतिहास में लिखा गया है
अपने मरने के पहले वह उस इतिहास को भी पढ़ आया
था
जिस इतिहास को भी पिछले कुछ सालों में बड़े सलीके
से
नई तकनीक से मारा गया

जहाँ वह दफ़्न है या जहाँ बिखरी है उसकी राख़
वहाँ हवा चलती है तो सुनाई देती है उस हुतात्मा की
बारीक़ धूल जैसी महीन आवाज़

वह लगातार पूछता रहता है
क्यों भई ! कोई शै अब ज़िन्दा भी बची है ज़माने में ?

मैं राख़ हूँ फ़कत राख़
मत फ़ूँको
आँख तुम्हारी ही जलेगी

1 ■ अजीत सिंह हसरत

ग़ज़लें

घोंसले राख हो गए जल के
मिट गए सब निशान जंगल के

आग बरसा के उड़ गया बादल
पर निकल आए मूए बादल के

चीथड़े ओढ़ कर जो सोता हूँ
ख़वाब आते हैं मुझ को मख़मल के

साँप उन से लिपट गए अक्सर
हम ने बोए थे पेड़ संदल के

जिस में इंसानियत नहीं रहती
हम दरिंदे हैं ऐसे जंगल के

जो हवा पर सवार हो साहब
कब वो चलता है साथ पैदल के

आओ बच्चों का एहतिराम करें
ये तो वारिस हैं साहिबो कल के

अपना हक़ बढ़ के छीन लो यारो
यूँ दिखाओ न हाथ मल मल के

कुछ बताता नहीं तिरा 'हसरत'
जाने अब दिल में क्या है पागल के

— — —

2

गुज़रे जिधर से नूर बिखेरे चले गए
वो हम-सफ़र हुए तो अँधेरे चले गए

अब मैं हूँ और शिद्दत-ए-ग़म की है तेज़ धूप
उन गेसुओं के साए घनेरे चले गए

मेरे तफ़क्कुरात को डसती रही थी जो
नागिन चली गई वो सपेरे चले गए

उम्मीद के शजर पे वो हलचल नहीं रही
चिड़ियाँ गईं तो रैन बसेरे चले गए

अंधे सफ़र को घर से मैं निकला था दोस्तो
आई जब उन की याद अँधेरे चले गए

आतिश ने मेरे घर को जलाया तो क्या हुआ
कुछ देर के लिए तो अँधेरे चले गए

'हसरत' मैं बे-क़रार हूँ लुटने के वास्ते
जाने कहाँ हसीन लुटेरे चले गए

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की कूटनीतिक मुलाकात को अमेरिका सहित दुनिया के अनेक मुल्कों द्वारा बड़ी हैरतअंगेज दृष्टि से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि चीन के विदेशमंत्री वांग यी द्वारा पहले भारत का कूटनीतिक दौरा किया गया। उसके तत्पश्चात ही वह पाकिस्तान के दौरे पर गए। पाकिस्तान के ऊपर भारत को प्राथमिकता प्रदान करने वाला यह चीन का कूटनीतिक दृष्टिकोण एकदम अनोखा और नया है। यक्ष प्रश्न है कि अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक तनाव के नाजुक दौर में भारत द्वारा क्या चीन पर तहेदिल से यकीन किया जा सकता है? आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा बहुत जोर शोर से बुलंद किया गया, किंतु वर्ष 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण अंजाम देने के तत्पश्चात सरहद पर तल्ख विवाद के कारणवश दोनों देशों के मध्य कूटनीति रिश्ते कभी सामान्य और दोस्ताना नहीं हो पाए। अब ट्रंप के एकतरफ टैरिफ के बाद भारत और चन अपनी ट्रेडकूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देश मिलकर जहां ग्लोबल साउथ को मजबूत कर सकते हैं, वहीं एशिया का नेतृत्व भी कर सकते हैं। भारत, चीन व जापान में नई वैश्विक व्यवस्था गढ़ने का दम है। आजकल के ताजा अंक में पेश है भारत व चीन संबंध पर एक विश्लेषण...

सहयोग का इतिहास रचेंगे हिंदी-चीनी?

ट्रेडकूटनीति

प्रभात कुमार रॉय

विदेश मामलों के जानकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थोपी गई आक्रामक टैरिफ के कारण क्या भारत और चीन रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर निकट आ रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप की खुशफहमी है कि भारत इतना अधिक शक्तिशाली नहीं है कि निर्णायक और प्रभावी तौर पर अमेरिका पर चीन की तर्ज ओ तरीके से पलटवार कर सकेगा। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब चीन के विदेशमंत्री से मुलाकात अंजाम दी तो फिर दुनिया भर के जाने-माने डिप्लोमेट्स का नजरिया भारत के प्रति परिवर्तित होने लगा है। समस्त ऐतिहासिक शत्रुताओं के बावजूद भारत-चीन मित्रता विश्वपटल पर नया भविष्य रच सकती है, बशर्ते चीन द्वारा अपनी विस्तारवादी फितरत का परित्याग कर दिया जाए।

जटिल प्रश्न है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थोपी गई आक्रामक टैरिफ के कारण क्या भारत और चीन रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर निकट आ रहे हैं? अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फरमाया कि 27 अगस्त से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ बाकायदा आयद कर दिया जाएगा। अमेरिका के नीति नियंता भारत को निरंतर धमकियां दे रहे हैं कि रूस से तेल का आयात जारी रखा गया तो फिर भारतीय निर्यात पर टैरिफ दरों को सौ प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। यूरोप के कुछ कूटनीतिक विशेषज्ञों का मंतव्य है कि भारत की बहुरेखीय डिप्लोमेटिक रणनीति जबरदस्त तौर पर नाकाम सिद्ध हुई है। बाद में उनकी राय बदली है।

इस कूटनीतिक रणनीति के तहत भारत के लिए सभी देशों का दोस्त बन जाना और सभी के लिए अपरिहार्य बन जाने का उसका मकसद रहा है। लेकिन प्रायः सभी के लिए भारत कहीं अब गैरजरूरी तो नहीं बनता जा रहा है? यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के काल में अमेरिका और रूस दोनों ने पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू में तोल दिया। चीन से दुश्मनी अंजाम दिए बिना राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ भारत पर ही टैरिफ आक्रमण अंजाम देकर धमकाते और धकियाते रहते हैं, क्योंकि संभावतया राष्ट्रपति ट्रंप इस गलतफहमी के शिकार रहे हैं कि अमेरिका विरुद्ध भारत की खामोशी और ट्रेड समझौता करने की चाहत उसकी कमजोरी है। राष्ट्रपति ट्रंप की खुशफहमी है कि भारत इतना अधिक शक्तिशाली नहीं है कि निर्णायक और प्रभावी तौर पर अमेरिका पर चीन की तर्ज ओ तरीके से पलटवार कर सकेगा। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब चीन के विदेशमंत्री से मुलाकात अंजाम दी तो फिर दुनिया भर के जाने-माने डिप्लोमेट्स का नजरिया भारत के प्रति परिवर्तित होने लगा है।

भारत की वैश्विक कूटनीति

कुछ जाने-माने विशेषज्ञ तो यहां तक कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर ऐसी विरल रणनीतिक और कूटनीतिक हिम्मत विद्यमान है, जोकि यूरोपीय यूनियन के लीडरों के पास कदाचित मौजूद नहीं रही। तसव्वुर कीजिए, यदि ऐसा ही रणनीतिक अंदाज यूरोपीय यूनियन ने लीडरान द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध के निदान के लिए रूस के साथ कूटनीतिक मुलाकातें करने की खातिर अख्तियार किया होता तो फिर यूरोपीय यूनियन को रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की आवश्यकता कदापि नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की कूटनीतिक मुलाकात को अमेरिका सहित दुनिया के अनेक मुल्कों द्वारा बड़ी हैरतअंगेज दृष्टि से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि चीन के विदेशमंत्री वांग यी द्वारा पहले भारत का कूटनीतिक दौरा किया गया। उसके तत्पश्चात ही वह

पाकिस्तान के दौरे पर गए। पाकिस्तान के ऊपर भारत को प्राथमिकता प्रदान करने वाला यह चीन का कूटनीतिक दृष्टिकोण एकदम अनोखा और नया है। यक्ष प्रश्न है कि अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक तनाव के नाजुक दौर में भारत द्वारा क्या चीन पर तहेदिल से यकीन किया जा सकता है? आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा बहुत जोर शोर से बुलंद किया गया, किंतु सन् 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण अंजाम देने के तत्पश्चात सरहद पर तल्ख विवाद के कारणवश दोनों देशों के मध्य कूटनीति रिश्ते कभी सामान्य और दोस्ताना नहीं हो पाए।

चीन की बुनियादी फितरत में विस्तारवाद

सन् 1949 में कम्युनिस्ट इंकलाब के बाद से ही चीन की बुनियादी फितरत बाकायदा विस्तारवादी अंदाज में निरंतर कायम बनी रही। सबसे पहले चीन ने 1959 में अनाधिकृत तौर पर तिब्बत पर आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद चीन ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों और अरुणाचलम (नेफा) पर अपने स्वामित्व का दावा पेश किया। 35000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के अक्साई चिन इलाके पर चीन का अनाधिकृत आधिपत्य कायम बना रहा। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में रक्तरंजित सैन्य झड़प तत्पश्चात भारत-चीन संबंधों में फिर से एक खराब दौर आया, किंतु तभी से दोनों मुल्कों द्वारा परस्पर संबंधों सामान्य स्थिति में लाने की खातिर निरंतर सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं जारी रखी गई हैं। भारत-चीन संबंधों में तल्खी और तनाव का एक कारण क्वाड गठबंधन भी रहा है जिसे चीन अपने विरुद्ध एक अमेरिकन गठजोड़ के तौर पर देखता है। चीन द्वारा अमेरिकन टैरिफ के बरखिलाफ सबसे सशक्त आवाज बुलंद की गई और राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी भाषा में सख्त प्रतिउत्तर पेश कर दिया। विदेशमंत्री वांग यी की भारत यात्रा को चीन के मीडिया द्वारा अत्यंत प्रमुखता के साथ पेश किया गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ चीनी विदेश मंत्री द्वारा सीमा विवाद पर महत्वपूर्ण चर्चा अंजाम दी गई।

रणनीतियों में आएगा बुनियादी बदलाव

चीन के कूटनीतिक हल्कों में जोरदार चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों के मद्देनजर भारत और चीन वस्तुतः अपनी रणनीतियों में अब बुनियादी बदलाव करना चाहते हैं और वांग यी की भारत यात्रा इसी व्यापक कूटनीतिक पहल का एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन के जाने-माने डिप्लोमेट्स गुआंग का भी विचार है कि भारत और चीन के मध्य ताकतवर कूटनीतिक ताल्लुकात यकीनन ग्लोबल साउथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल साउथ टर्म का इस्तेमाल एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के समूह के लिए किया जाता है। आखिर वांग यी की भारत यात्रा से ठोस उपलब्धि क्या हासिल हुई? इसके उत्तर में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ मिंग ने फरमाया कि चीन और भारत अनेक जटिल विवादित प्रश्नों को लेकर ठोस सहमति पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के समक्ष सबसे जटिल प्रश्न है कि वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना कैसे किया जाए और किसी भी मुल्क के धौंस और दबाव की रणनीति का कारगर एवं समुचित विरोध करने के लिए किस तरह एकजुट हुआ जाए। विश्वसनीय कूटनीतिक सूत्र यह भी बयान करते हैं कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी दोनों देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। भारतीय कूटनीति सूत्रों ने दावा पेश किया कि चीन द्वारा भारत के ऊपर आयद किए गए अर्थ निर्यात नियंत्रण समाप्त कर दिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर इस तथ्य की हालांकि बाकायदा पुष्टि नहीं हो पाई है।

उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा भारत को कुल फर्टिलाइजर्स का लगभग 30 प्रतिशत सप्लाई कराया जाता रहा है। ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट्स के लिए अर्थ एलिमेंट्स और सड़क और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जरूरी टनल बोरिंग मशीन भी चीन द्वारा भारत को निर्यात किए जाते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ मिंग ने दावा पेश किया कि भारत ने ताइवान को चीन का अभिन्न अंग निरूपित किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को पहले की तरह जारी रखा जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, के निचले इलाके पर चीन द्वारा निर्मित किए जा रहे मेगा डैम के निर्माण को लेकर भारत की गहन चिंताओं को चीन के विदेशमंत्री वांग यी के समक्ष पेश किया। वस्तुतः चीन के विदेशमंत्री वांग यी की भारत यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई कॉआपरेशन आर्गेनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भागीदारी की तैयारी के संदर्भ में देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तकरीबन 100 देशों के विरुद्ध टैरिफ जंग शुरू की है। ट्रंप द्वारा टैरिफ आक्रमण में भारत को बख्शा नहीं गया है। इसके बावजूद कि विगत 25 वर्षों के दौर में भारत बेहद करीबी संबंध अमेरिका के साथ स्थापित कर चुका है। भारत यकीनन अत्यंत विवश होकर अमेरिकन प्रशासन के विरुद्ध सीधे टकराव की स्थिति में आ गया है, क्योंकि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदारी खत्म करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया है। इस वक्त भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के महत्व को बाकायदा समझ रहा है। भारत चीन के साथ संबंध सुधारने की अत्यंत संजीदा कोशिश अंजाम दे रहा है, ताकि विश्व पटल पर भारत को रणनीतिक गुंजाइश और नीतिगत लचीलापन हासिल हो सके। भारत अब अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए जबरदस्त झटके के बाद ग्लोबल साउथ के बाजारों की तरफ नजर डाल रहा है, ताकि भारत को निर्यात के लिए अमेरिका के बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

ट्रंप से यूरोपीय यूनियन के लीडर भी आहत

इन दिनों तक अमेरिका के आक्रामक व्यवहार से यूरोपीय यूनियन के लीडर भी बहुत आहत हुए, जिनके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनफीरियर देशों की तरह से व्यवहार किया है और जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है। उल्लेखनीय है कि विगत अनेक दशक से यूरोप वस्तुतः अमेरिका का पिछलग्गू बना रहा है। यूरोपीय यूनियन के अनेक बड़े लीडर तत्व्ह एहसास से गुजर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप तो रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना रहे हैं किंतु यूरोप ने रूस के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ कर अपना बहुत अधिक आर्थिक नुकसान किया है। यूरोपीय यूनियन के लोग गहनता से महसूस करते हैं कि चीन के प्रति भारतीयों के मन में जिस तरह का शत्रु भाव व्याप्त रहा है, इस तरह का शत्रुतापूर्ण भाव यूरोप में रूस के विरुद्ध लेकर कदाचित विद्यमान नहीं रहा है, अर्थात भारत के लिए एक दोस्त के तौर पर चीन के साथ पेश आना, वस्तुतः यूरोप की तुलना में राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कहीं ज्यादा मुश्किल रहा है, किंतु भारत ने यह कूटनीतिक करनामा कर दिखाया है, किंतु यूरोप अभी भी एक तरह से रूस के साथ अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को लेकर कन्फ्यूज भाव में डगमगा रहा है।

अब तो अमेरिका प्रशासन ने विश्व पटल पर ऐसे विकट हालात उत्पन्न कर दिए हैं कि भारत और चीन यदि निकट सहयोग नहीं करेंगे तो फिर गहन आर्थिक संकट के दलदल में धंस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विगत कार्यकाल में चीन के विरुद्ध ट्रेड वॉर का बिगुल बजाया गया था किंतु राष्ट्रपति ट्रंप के वर्तमान कार्यकाल में तो भारत को भी ट्रेड वॉर का निशाना बना दिया गया। समस्त ऐतिहासिक शत्रुताओं के बावजूद भारत-चीन मित्रता विश्वपटल पर नया भविष्य रच सकती है, बशर्ते चीन द्वारा अपनी विस्तारवादी फितरत का परित्याग कर दिया जाए। नए वर्ल्ड ऑर्डर की उम्मीद लगा सकते हैं।

https://t.me/pdfnotesforall1

एससीओ में दिखना चाहिए भारत का प्रभाव

विश्लेषण

सुनील अमर

वरिष्ठ स्तंभकार

चीन के त्यानजिन में 31 अगस्त को होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक, अमेरिकी दखलअंदाजी से बदले हुए अन्तरराष्ट्रीय माहौल के कारण अहम बन गयी है। इसी कारण दुनिया भर के राजनीतिक पर्यवेक्षकों व कूटनीतिज्ञों की निगाहों का केन्द्र बिन्दु बनी हुई है। भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भी इस बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी के इस बैठक में भाग लेने को चीन काफी गम्भीरता से ले रहा है और माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए कई स्तर के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली आये चीनी विदेश मन्त्री ने अपने भारतीय समकक्ष से मुलाकात कर न सिर्फ आशाजनक बयान दिये हैं बल्कि सार्थक क्रियान्वयन करने का एक खाका भी खींच गए हैं। अरसे से स्थगित वीजा और हवाई सेवायें शुरू की जा रही हैं। दोनों तरफ से बने हुए इस खुशनुमा माहौल का क्या नतीजा निकलेगा, यह तो एक सितम्बर के बाद ही पता चलेगा।

चीन द्वारा लगातार पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण चीनी प्रभुत्व वाले एससीओ से भारत को कभी भी ज्यादा उम्मीदें नहीं रही हैं। वैसे तो एससीओ का गठन वर्ष 2001 में ही हो गया था लेकिन भारत और पाकिस्तान इसमें वर्ष 2017 में शामिल हुए। असल में सोवियत संघ के विखण्डन के बाद बने देशों में सीमा और अन्य तरह के विवाद हो रहे थे तो उनको एक मंच पर लाकर बात करने के लिए वर्ष 1996 में शंघाई फाइव नाम से एक संगठन बनाया गया जिसमें रूस और चीन के अलावा तत्कालीन सोवियत संघ से आजाद हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान व ताजिकिस्तान देश शामिल थे। बाद में इसी को विस्तार देते हुए एससीओ बनाया गया जिसमें आज नौ देश शामिल हैं।

एससीओ से सार्थक उम्मीद नहीं

इस संगठन में चीन का ही प्रभुत्व है। ध्यान देना होगा कि बीते जून माह में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें भाग लेने गये भारतीय रक्षा मन्त्री ने वहां जारी साझा बयान को मानने और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भारत को आपत्ति थी कि एससीओ दोहरा मापदण्ड अपना रहा है। बयान में पाकिस्तान में हुए जाफर एक्सप्रेस आतंकवाद काण्ड की तो निन्दा की गयी थी लेकिन भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र भी नहीं किया गया था। भारत को इस संगठन से कभी भी कोई सार्थक उम्मीद नहीं रही है क्योंकि यह मुख्य रूप से चीन और रूस के हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि इस संगठन की आधिकारिक भाषा भी रुसी और चाइनीज ही है। भारत ने सुझाव दिया था कि इसमें अंग्रेजी को भी शामिल किया जाय लेकिन चीन नहीं माना।

ट्रंप के व्यापार युद्ध का असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते ही मानों व्यापार युद्ध सा छेड़ दिया है। उन्हें शायद लगता है कि वे अमेरिका की हर समस्या को अन्य देशों पर व्यापार कर यानी टैरिफ थोप कर हल कर लेंगे। उनके इस व्यापार युद्ध का ही असर है कि चीन इस बार एससीओ की बैठक के लिए भारत के प्रति दुर्लभ किस्म की विनम्रता

दिखा रहा है। भारत में चीन के राजदूत सू फ्येांग ने जहां कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ बैठक में भाग लेना 'अत्यन्त महत्वपूर्ण' होगा और इसे सफल बनाने के लिए भारत और चीन के अधिकारियों का एक समूह लगातार काम कर रहा है। वहीं, अपने हालिया भारत दौरे पर आये चीनी विदेश मन्त्री वांग यी ने तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व विदेश मन्त्री एस जयशंकर से हुई वार्ता के बाद यहां तक कह दिया है कि दोनों देशों के बीच सीमा आदि के विवाद को सुलझाने के लिए दस सूत्रों पर सहमति बनी है और जिस पर काम करने के लिए दोनों तरफ से दो-दो ग्रुप बनाये जाएंगे, जो विवाद निपटाने व सीमा प्रबन्धन का कार्य देखेंगे।

ध्यान रहे कि चीन के साथ भारत की सबसे बड़ी समस्या दशकों पुराना युद्ध स्तरीय सीमा विवाद ही है। एससीओ में भाग लेने जा रहे प्रधानमन्त्री मोदी के एजेन्डे के लिए यद्यपि राजनीतिक, कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं फिर भी कुछ खास और जाने-सुने मुद्दे हैं जिन पर वहां उनके बात करने की संभावना बन सकती है। सात वर्षों बाद भारतीय प्रधानमन्त्री की चीन यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होगा कि दोनों देशों के बीच खत्म हो चुके आपसी भरोसे को फिर से बहाल किया जाए। इस दौरान लगभग ढाई दर्जन बार हो चुकी बेनतीजा सीमा सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ताओं को अब किसी सिरे तक पहुंचाने की कोशिशें हों। इसके अलावा रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिज, उर्वरक, फार्मा व इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, सुरंग बनाने की मशीनें, कृषि क्षेत्र व वैकल्पिक ऊर्जा आदि बातचीत के विषय हो सकते हैं।

आतंकवाद व अलगाववाद जैसी समस्या से निपटना एससीओ की स्थापना का घोषित लक्ष्य है। देखना होगा कि इस बार चीन इस पर क्या रवैया अपनाता है। भारत यद्यपि ब्रिक्स व क्वाड जैसे अन्य कई बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, फिर भी चीनी प्रभुत्व के बावजूद एससीओ का उसके लिए महत्वपूर्ण है कि इससे मध्य एशिया की एनर्जी मार्केट में सीधा दखल तथा सुरक्षा सहयोग के अलावा क्षेत्रीय प्रभाव भी बनता है। इसके अलावा एससीओ देशों को मिलाकर लगभग 60 प्रतिशत यूरेशिया बनता है जिसमें तीन अरब से अधिक की विश्व आबादी रहती है। इसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे परमाणु सम्पन्न देश भी हैं। एससीओ में बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय व्यापारिक मार्गों की सुगमता का हो सकता है।

बेहतर कनेक्टिविटी की चर्चा

इस सम्बन्ध में भारत अन्तरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर जिसे संक्षेप में आईएनएसटीसी कहा जाता है पर बेहतर कनेक्टिविटी यानी मार्ग संयोजन की चर्चा कर सकता है। यह लगभग 7200 किमी का समुद्र, सड़क और रेल मार्गों से बनने वाला रास्ता है और जिससे हिन्द महासागर, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर और यहां से फिर रेल व सड़क मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग होकर उत्तरी यूरोप जुड़ता है। इस मार्ग से समय व धन की बचत होती है। एससीओ में भारत इस बात को भी प्रमुखता से रख सकता है कि इसे रूस-चीन का सुरक्षा कवच वाला संगठन बनाये रखने के बजाय सदस्य देशों के बृहत्तर उद्देश्यों के लिए विस्तारित किया जाए।

संभावना तो इस बात की ज्यादा है कि चीन घुमा-फिराकर अपने व्यापारिक लाभ की बातों को ही आगे रखेगा फिर भी कुल मिलाकर उम्मीद यही रखनी चाहिए कि भारत ने जो तेवर एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बयान पर दस्तखत करने से इनकार करके तथा भारतीय विदेश मन्त्री ने 'जो देश आतंकवाद फैलाने में सहायता करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी' जैसा बयान देकर भारत की मजबूती को दिखाया है, वही दिशा-दशा और संप्रभुता आगामी एससीओ सम्मेलन में भारत की बनी रहेगी।

ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करे भारत-चीन

विमर्श

शंभू भद्रा

वरिष्ठ पत्रकार

मौजूदा वक्त में दुनिया में अनेक स्तर पर हलचल है। इसके केंद्र में अमेरिका है, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने सबसे अदावत की ठान रखी है। भारत व चीन समेत 90 से अधिक मुल्कों पर ट्रंप के एकतरफा टैरिफ के ऐलान से वैश्विक रिश्ते रिशेप ले रहे हैं। देश अमेरिका के विकल्प तैयार कर रहे हैं। भारत और चीन तेजी से करीब आ रहे हैं।

यूं तो चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने का प्रयास भारत ने ट्रंप 2.0 आने से पहले वर्ष 2024 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन ट्रंप के अनुचित टैरिफ के बाद चीन ने भी भारत से ट्रेडकूटनीति को मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा, इस दौरान दुर्लभ खनिजों की बंद आपूर्ति को शुरू करने के साथ उर्वरक व टनल खुदाई मशीन देने पर सहमति और 31 अगस्त व 1 सितंबर को दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी के भाग लेने व उनकी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ प्रस्तावित बैठक इन्हीं कोशिशों की कड़ी हैं। भारत एक साथ ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चीन, रूस व ब्राजील से अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीकी संघ, लैटिक अमेरिकी देश और आसियान देशों के साथ भी भारत के रिश्ते बेहतर हैं। इसमें सबसे अहम भारत व चीन के उतार-चढ़ाव वाले रिश्ते हैं।

दूरदृष्टि का दे रहे परिचय

बेशक वांग यी की यात्रा के बाद चीन व भारत के संबंध को लेकर बीजिंग व नई दिल्ली में अलग-अलग विश्लेषण व नजरिया है, लेकिन दोनों मुल्क दूरदृष्टि का परिचय दे रहे हैं। भारत व चीन के संबंध भविष्य में क्या आकार लेंगे, कहना कठिन है, कारण चीन की विस्तारवादी नीतियां, पाकिस्तान के साथ दोस्ती व भारत के साथ सीमा विवाद राह के रोड़े हैं। भारत के साथ सामान्य संबंध चीन के रुख पर निर्भर करेगा, पर अभी ट्रंप टैरिफ की वजह से अगर दोनों देश नजदीक आ रहे हैं तो भी यह बहुध्रुवीय विश्व में नई उम्मीद को मजबूत कर रहे हैं। भारत के लिए अमेरिका का रिप्लेसमेंट चीन नहीं है, लेकिन भारत अपने हितों से कभी समझौता भी नहीं करेगा। भारत को लेकर अमेरिकी प्रशासन की भाषा अपमानजनक सरीखी है, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हाल में भारत ने रूस व चीन के साथ बेहतर तालमेल बढ़ा कर अमेरिका को संदेश दे दिया है कि ट्रंप के तरीके नामंजूर हैं।

पश्चिम पर निर्भरता कम होगी

भारत को अगर अपने ग्लोबल साउथ के आइडिया को अमलीजामा पहनाा है, तो उसमें चीन, जापान व ब्राजील का साथ जरूरी है। भारत, चीन, ब्राजील व जापान मिलकर ग्लोबल साउथ को नई दिशा दे सकते हैं। ये सभी मुल्क तकनीक, संसाधन और बाजार के साथ सामरिक ताकत से लैस हैं। इससे पश्चिम पर निर्भरता कम होगी। भारत को एशिया की मजबूती और शांति की दिशा में भी काम करना चाहिए। एशिया में देशों के बीच संघर्ष, अविश्वास व दुश्मनी पश्चिमी

हथियार बाजार को खाद-पानी देते हैं। एशियाई देशों में अगर यह समझ विकसित हो जाए कि आपसी टकराव के बजाय सहअस्तित्व व सहयोग से इस साधन संपन्न सबसे बड़े महादेश को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाया जा सकता है, तो हथियार की होड़ रुक सकती है, जिससे पश्चिम का दबदबा खत्म हो सकता है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के मुताबिक, 2014 से 2024 के बीच भारत के आयात परिदृश्य पर चीन का प्रभुत्व और अधिक बढ़ गया है। इंश्रोमाइसिन, सिलिकॉन वेफर्स, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, सौर सेल, लिथियम आयन बैटरियां, दुर्लभ खनिज खासकर मैग्नेट के लिए भारत चीन पर निर्भर है। इस कारण चीन संकट के समय भारत के खिलाफ माल आपूर्ति को रोक कर ढाल बनाता है। भारत को इस स्थिति से उबरना है। भारत को चीन पर दबाव भी बनाना होगा कि वह भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खोले, व्यापार संतुलन की खाई को पाटे। द्विपक्षीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दो दशक पहले के 42.3 प्रतिशत से घटकर आज केवल 11.2 प्रतिशत रह गई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा को व्यापक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की निर्धारित तथानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन यात्रा की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। चीन अगर भारत का भरोसा जीतना चाहता है तो, उसे अधिक पहल करनी होगी। भारत व चीन के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं। आयुर्वेद, योग और भारतीय शास्त्रीय कलाओं में चीन की रुचि बढ़ रही है।

पर्यटन, तीर्थयात्रा में वृद्धि हो रही है। भारतीय स्टार्टअप्स प्रमुख चीनी फंडिंग को आकर्षित कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे और हाई-स्पीड रेल के क्षेत्र में चीन की उन्नत जानकारी भारत के औद्योगिक विकास के लिए लाभकारी है। भारत और चीन ब्रिक्स, एससीओ, जी-20, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में सहयोग कर वैश्विक दक्षिण एकजुटता, बहुध्रुवीयता और जलवायु कूटनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन भारत के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का समर्थन करता है। दोनों देश पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कार्बन टैरिफ और वैश्विक जलवायु शासन में अंतर्निहित असमानताओं के बारे में गहरी चिंताएं साझा करते हैं। भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सीमाई स्थिरता, व्यापार और सामरिक संवाद के माध्यम से रचनात्मक सहभागिता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद, अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जा, अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'दक्षिण तिब्बत' बताकर चीनी दावा, देपसांग और चार्डिंग-निंगलुंग नाला जैसे टकराव वाले अनसुलझे बिंदु, डोकलाम गतिरोध (2017) और गलवान घाटी संघर्ष (2020), पीओके से होकर चीन का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपेक), चीन का ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियों पर नियंत्रण, चीनी विस्तारवाद, पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग आदि भारत व चीन के रिश्ते की राह में बाधाएं हैं।

प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत बनाएं

चीन वैश्विक मंचों पर भारत की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सीट की आकांक्षाओं में बाधा डालता है। फिर भी विश्वास-निर्माण उपायों, सामरिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय सहयोग तथा वैश्विक बहुध्रुवीय सहभागिता के संयोजन से एक स्थिर, सहयोगपूर्ण व भविष्यन्मुखी द्विपक्षीय संबंध की राह प्रशस्त की जा सकती है। भारत को स्मार्ट सीमा अवसंरचना, आईएसआर (खुफिया, निगरानी एवं टोही) तकनीकों तथा पर्वतीय युद्ध की तैयारी में निवेश कर अपनी विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना चाहिए।

दैनिक जागरण

मर्यादा-उल्लंघन का परिणाम सदा घातक होता है

अमेरिका को जवाब

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर एक तरह से अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया कि यदि आपको भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने में परेशानी है तो आप उसे हमसे न खरीदें। ज्ञात हो कि भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है, उसके रिफाइंड उत्पादों के खरीदारों में यूरोप के साथ अमेरिका की भी गिनती होती है। यह तथ्य सामने रखकर भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दोहरे रवैये को बेनकाब करने का ही काम किया। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सफल न होने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का दोहरे रवैये को बेनकाब करने का ही काम किया। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सफल न होने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस घोषणा पर 27 अगस्त से अमल होना है। ट्रंप का तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीदकर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है। यह बेतुका और हास्यास्पद आरोप है, क्योंकि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है, जिसके प्रति वे कठोर कदम उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। यूरोप भी बड़ी मात्रा में रूस से गैस खरीदता है। खुद अमेरिका रूस से उर्वरक खरीद रहा है।

यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरों अर्थात भारत पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जो अमेरिका एक समय मुक्त व्यापार की वकालत करता था और दुनिया भर के देशों पर इसके लिए दबाव डालता था, वह आज घनघोर संरक्षणवादी रवैया अपनाए हुए है। इस रवैये का परिचय ट्रंप के साथ-साथ अमेरिका के अरबपति कारोबारी भी दे रहे हैं। इस सबके बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के खिलाफ अपनी मनमानी टैरिफ नीति को लेकर चाहे जितने बड़े बोल बोलें, सच्चाई यह है कि भारत अब उनके दबाव में आने वाला नहीं है। उसे आना भी नहीं चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने यही संदेश देने के लिए यह कहा कि भारत ने अमेरिका से व्यापार वार्ता के मामले में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वस्तुतः यह नए भारत का संदेश है। यदि ट्रंप ने अपने मनमाने रवैये का परित्याग नहीं किया तो अमेरिका को और मुश्किल होगी, क्योंकि अब वह इस स्थिति में नहीं कि भारत जैसे देशों को अपनी ऐसी सामग्री खरीदने के लिए बाध्य कर सके, जो उपयोगी नहीं। वैसे भी अमेरिका मुख्यतः हथियार बेचता है और इसके लिए अस्थिरता एवं टकराव को बढ़ावा देता है। यह भी ध्यान रहे कि ब्रिक्स जैसे संगठन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए कमर कस रहे हैं।

पोषण से दूर बच्चे

उत्तराखंड में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन से पोषण के तत्वों के गायब होने पर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। खास बात तो यह है कि स्वयं शिक्षा विभाग की जांच में यह बात सामने आई है। विभाग की ओर से जो रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई है, उसमें माना गया है 50 से अधिक ऐसे स्कूल हैं, जहां भोजन में तय मानक के अनुरूप प्रोटीन और ऊर्जा नहीं पाई गई। इससे यह संदेश सामने आ रहा है कि जिन्हें व्यवस्था बनाने और उसका अनुपालन करने की जिम्मेदारी दी गई है, वे दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी योजना के क्रियान्वयन में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। नौनिहालों का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, लेकिन बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि हमारा निगरानी तंत्र अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं है। अव्वल तो यह कि स्कूली बच्चों के भोजन में पोषण की यह हकीकत एक शिकायत के बाद सामने आई है। न जाने कब से और कहां-कहां आंखों में धूल झोंककर बच्चों की थाली से पोषण के तत्व गायब हो रहे हैं। नौनिहालों की सेहत से खिलवाड़ को किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना होगा। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बच्चों के उपयुक्त पोषण के लिए भोजन के जो मानक तय किए गए हैं, उन्हें पूरा करना आवश्यक है।

> स्कूली बच्चों के उपयुक्त पोषण के लिए भोजन के जो मानक तय किए गए हैं, उसे पूरा करने के साथ व्यवस्था की निगरानी जरूरी हो गई है

एक बुरे धंधे पर लगाम

संजय गुप्त

इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स को बढ़ावा देकर अपनी तिजोरी भरने वाली कंपनियों ने एक अनैतिक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली थी

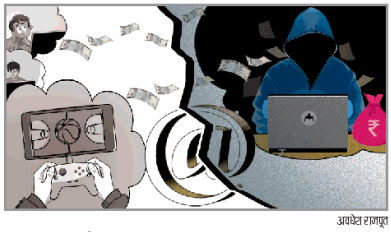

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार की ओर से लोकसभा और फिर राज्यसभा में आनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन आफ आनलाइन गेमिंग बिल, 2025 कानून में परिवर्तित हो गया और इसी के साथ उस पर अमल भी शुरू हो गया। इसके चलते कई आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने आनलाइन मनी गेम बंद करने शुरू कर दिए। जब से इंटरनेट का प्रसार एवं उसकी उपलब्धता बढ़ी है और मोबाइल फोन पर आनलाइन गेम्स का चलन बढ़ा है, तब से आनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसी कंपनियां भी आईं, जिन्होंने गेम की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का कारोबार शुरू कर दिया। पिछले कई वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित थीं कि पैसे के लेन-देन आधारित आनलाइन गेम्स कंपनियां गेम के नाम पर सट्टेबाजी का खेल खेल रही थीं। इस सट्टेबाजी के कारण तमाम लोग जुए की लत में अपना नुकसान कर रहे थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि सरकारों ने तो उन पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन संबंधित उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों के तर्कों को खारिज कर दिया और सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स को कौशल से जुड़ा खेल करार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसी कंपनियां अपना कारोबार खुलकर करने लगीं और इनमें से एक कंपनी तो भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक भी बन गई और उसका प्रचार नामी क्रिकेटर करने लगे।

यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार आनलाइन गेमिंग के नाम पर जारी सट्टेबाजी और जुए को लेकर चेती। उसकी ओर से आनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाना आवश्यक हो गया था। इस संदर्भ में जो कानून बनाया गया है, वह आनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर तो निर्यात्रण की कोशिश है, लेकिन इसी के साथ वह कौशल वाले आनलाइन गेम्स को बढ़ावा भी देने वाला है। इन दोनों के बीच अंतर करना आवश्यक है, क्योंकि जहां आनलाइन सट्टेबाजी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रही थी, वहीं कौशल वाले आनलाइन गेम इंटरनेट आधारित एक नया उद्यम हैं। इन्हें पूरी दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है और लोग अपने कौशल एवं शौक के हिसाब से उन्हें खेलते हैं। इसकी प्रतियोगिताएं भी होने लगी हैं। चूंकि इनमें पैसे का कोई लेन-देन नहीं होता, इसलिए इन्हें बढ़ावा मिलने में हर्ज नहीं। आज करोड़ों लोग और विशेष रूप से युवा आनलाइन गेमिंग में रुचि रखते हैं। यह भी एक उद्योग का रूप ले चुका है और लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व उपलब्ध कराता है।

भारत का आनलाइन गेमिंग बाजार तेजी से बढ़ा है। 2023-24 में यह 23 प्रतिशत की दर से बढ़कर 3.8 अरब डालर तक पहुंच गया था। एक आंकड़े के अनुसार अपने देश में 2024 में आनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, लेकिन इस आकर्षक तस्वीर के पीछे उस बुरे धंधे की अनदेखी नहीं की जा सकती, जो खतरा बन गया था। यह खतरा सट्टेबाजी और जुए की लत बढ़ने के रूप में था। इस लत के चलते अनेक लोगों ने अपने लाखों रुपये गंवाए और हताश-निराश होकर आत्महत्या भी की। आत्महत्या के ऐसे कुछ मामलों का उल्लेख केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि आनलाइन मनी गेम्स की आड़ में हो रही सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन नाकामी मिली। सट्टेबाजी वाली आनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देकर अपनी तिजोरी भरने वाली गेमिंग कंपनियों ने एक अनैतिक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली थी। इसमें उपभोक्ताओं यानी आनलाइन गेमिंग के जरिये सट्टेबाजी करने वालों को न तो किसी तरह का संरक्षण प्राप्त था और न ही उनकी शिकायतों-समस्याओं की सुनवाई की कोई व्यवस्था थी। कुल मिलाकर मनमानी हो रही थी। अब इस मनमानी पर एक बड़ी हद तक रोक लगेगी, क्योंकि सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम का प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सट्टेबाजी कराने वाली आनलाइन कंपनियों को बैंक भुगतान प्रणाली से अलग किया जाएगा। अच्छा होगा कि सरकार नए कानून के हिसाब से नियामक प्राधिकरण जल्द बनाए, ताकि आनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर रोक लगाने के साथ ई-स्पोर्ट्स और ई-सोशल जैसे गेम्स का बेहतर नियमन हो, उनका बाजार बढ़े और रोजगार मिलने के साथ राजस्व भी मिले।

सट्टेबाजी और जुए की लत लोगों को बर्बाद ही करती है। जो कंपनियां लोगों को आनलाइन जुआ खिला रही थीं, उनके बारे में यह संदेह है कि वे मनी लांड्रिंग का भी काम करती थीं और उनका पैसा देश विरोधी गतिविधियों में भी खपाया जाता था। ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए 2021 में आइटी नियमों में संशोधन किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद भी कुछ लोगों का तर्क है कि अन्य देशों की तरह भारत में भी आनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के बजाय उनका नियमन किया जाना चाहिए। यह एक तर्क तो है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह एक कठिन काम है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इंटरनेट आधारित कंपनियां किस प्रकार हर तरह के नियमन का तोड़ निकालने में समर्थ होती हैं। अभी भी इसकी आशंका है कि ऐसी कंपनियां छल-छद्म से सक्रिय होने की कोशिश कर सकती हैं। सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा। सरकार की पहली प्राथमिकता एक बुरे धंधे से लोगों को बचाने की होनी चाहिए। इस धंधे की बुराई को इससे समझा जा सकता है कि एक अनुमान के मुताबिक अपने देश में लोगों की सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स के कारण सालाना 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा था। इन हालात में इस पर जोर देना ठीक नहीं कि आनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाने से सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही हजारों नौकरियां भी जाएंगी। फौरी तौर पर कुछ नौकरियां अवश्य जाएंगी, लेकिन क्या राजस्व के लोभ में सरकार एक अनैतिक और हानिकारक धंधे की अनदेखी कर दे? आखिर इस आवश्यक पहलू पर विचार क्यों नहीं किया जाता कि आनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों के जो हजारों करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे थे, वे अब उनके काम आएंगे और इसका लाभ किसी न किसी रूप में देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा।

response@jagran.com

सवाल के जवाब में सवाल

हास्य-व्यंग्य

मुकेश राठौर

जवाब देने से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सवाल के जवाब में ही सवाल दाग दिया जाए

एक पुरानी फिल्म आई थी-ससुराल। उसमें एक गाना था, 'एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो' में मंच से नायक-नायिका परस्पर अनेकानेक सवाल करते हैं। माने सवाल के जवाब में फिर एक और सवाल। यूं तो सवाल का सवाल नहीं, जवाब हुआ करता है, जिसकी अपेक्षा की जाती है। घड़ी घर को 'कबार' हटाकर सवाल की ही दोहरा दिया जाए, यहां तक भी ठीक है, लेकिन जब सवाल के जवाब में सवाल आगे विस्मयादिबोधक और पीछे प्रश्नवाचक चिह्न लगाकर आ खड़ा हो...तो अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती है। एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, जैसे एक पिता की कई संतानें। इन दिनों सवाल पूछने वालों की तुलना में जवाब देने वालों की संख्या तेजी से घट रही है।

आज हर सवाली सवाल पूछकर अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाह रहा है। यही उत्सुकता सामने वाले की भी है। अफसोस कि जवाब देकर कोई भी उन्नीस नहीं होना नहीं चाहता। गोया सवाल राजा, जवाब प्रजा हो गया। पिता निठल्ले बेटे से सवाल करते हैं 'चलतू यहां-वहां फिरते रहते हो कुछ काम-धंधा कर लो? बेटा जवाबी सवाल करता है 'यह भी कोई छोटा काम है क्या? मां बेटी से सवाल करती है 'इतनी रात गए कहां से आ रही हो?' बेटी प्रत्युत्तर में पूछती है 'आप अभी तक क्यों जाग रही हो?' छात्र शिक्षक से गुहार लगाता है कि सर कल जो सवाल हल करवाए थे, आज फिर से समझा देंगे क्या? जवाबी कार्रवाई करते हुए शिक्षक पूछते हैं 'पहले तो यह बताओ कि कल स्कूल क्यों नहीं आए?' मरीज सिर खुजलाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि डाक्टर साब पूरा कोर्स लेने के बावजूद खुजली नहीं जा रही? डाक्टर पूछते हैं,'तुम खाने में क्या ले रहे हो?' अड़ोसी-पड़ोसी से सवाल करता है कि तुम बार-बार हमारे आंगन में कचरा क्यों फेंक देते हो? पड़ोसी उलटा सवाल दागता है कि 'तुमने हमारा पानी क्यों रोका? ऐसे में कोई मनोविज्ञानी यही सुझा सकता है कि जवाब देने से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि सवाल के जवाब में धड़ाधड़ सवाल दाग दो। इससे होगा यह कि सवाली जवाब दे न दे, मगर अब और सवाल करने को लेकर सोच-विचार में पड़ जाएगा। तब आदमी न कुछ पूछ पाता है, न कह पाता है।

लोगों के आपसी सवालों से इतर देश के सामने भी कुछ सवाल होते हैं। ऐसा ही एक सवाल इन दिनों बिहार में लाखों वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटने के रूप में उठ रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि नाम कटा आदमी महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के दौरान तमाम सवालों से दो-चार तो होगा ही। आखिर नाम [illegible] नाक कटने से किसी तरह कम थोड़े होता है। मंच पर स्वागत सूची से नाम कटे या पंगत हेतु निमंत्रण सूची से, नाम कटना हमेशा पीड़ादायी होता है। वोटर लिस्ट से नाम कटना इसलिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके जरिये कई सूचियों में नाम जुड़ता जो है। हाल तो ये है कि जिसका वोट कटा उससे कहीं ज्यादा चिंता उन्हें है 'जिनका वोट कटा।' आपके एक वोट की कीमत आपको भले पता न हो, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है, जो आपसे वोट मांगते हैं। दो रोटी मांगने पर संभव है कि एक ही घर से मिल जाए, लेकिन एक वोट के लिए कई बार मोहल्ले भर झोली फैलाकर और खोंसे फुलाकर घूमना पड़ता है। आहत लोग सवाल कर रहे हैं कि जिनका नाम एक जगह भी नहीं रहने दिया, वे बेचारे कहां जाएंगे? 'वे' ज्ञान दे रहे कि आपका नाम दो जगह से कैसे जुड़ गया?

response@jagran.com

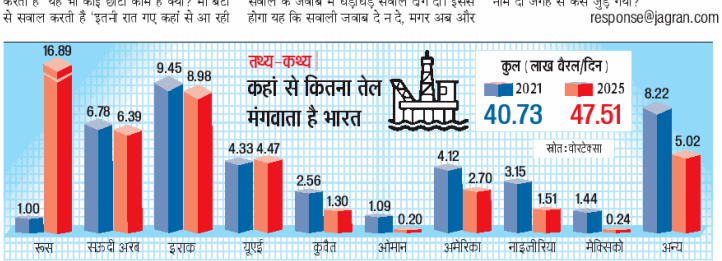

ऊर्जा

स्मृति-विस्मृति

प्रत्येक व्यक्ति का मन अनेक गतिविधियों और उनसे संबद्ध समस्याओं में आजीवन बंधा रहता है। वह कितना भी तीक्ष्णबुद्धि हो, विचारों तथा भावों के संघात का सामना करने में सक्षम हो, इतना [illegible] को इस प्रकार निर्मित किया गया कि कालांतर में उसकी स्मृतियां तेजी से विलुप्त होती रहें। विस्मृति की गति विचार की गति से तीव्र है। अतीत की भारी हानि, भयावह परिस्थिति, स्वयं या स्वजन का अंगभंग, मृत्यु या हृदय-विदारक घटनाएं मस्तिष्क से निष्कासित नहीं होंगी तो खानपान, निद्रा तथा दैनंदिन कार्य बाधित होते रहेंगे। वह असंतुलित रहने लगेगा, और स्वयं पर तथा दूसरों पर बोझ बन जाएगा। विस्मृति दोष नहीं, वरदान है। यह हमें अतीत के अवांछित, अप्रिय प्रसंगों से विमुक्त कर वर्तमान में जीना सिखाती है, ताकि पूर्णता से जीने के लिए उत्साह बना रहे। हालांकि स्मृति सशक्त होगी तभी अर्जित ज्ञान, कौशल, सूझबूझ और अनुभव को संरक्षित और संवर्धित किया जा सकेगा। प्रारंभ में पढ़ी-सीखी मूल जानकारी और अवधारणाएं स्मरण नहीं रहेंगी तो शिक्षार्थी का उच्चतर स्तर तक पहुंचना दुष्कर होगा।

जिन विषयों में अभिरुचि होगी, वे स्मृति में सहजता से अंकित हो कर टिके रहेंगे। किन विचारों, धारणाओं, मान्यताओं और व्यक्तियों को सहेजना, संरक्षित रखना है तथा किन्हें मन-चित्त में सायास स्थान नहीं देना, इसका विचार और अभ्यास अर्थपूर्ण जीवन की आधारशिला है। तनाव, अनिद्रा, दवाओं के सेवन या व्यसन की अवस्था में स्मृति का क्षरण होता है, ऐसा बारंबार हो तो उपचार लेना चाहिए। शारीरिक एवं बौद्धिक सक्रियता, उचित खानपान, सकारात्मक सोच और व्यसनों पर नियंत्रण से स्मरण शक्ति को चिरकाल तक जीवंत रख सकते हैं। कितना अद्भुद है, जो हम भूल गए, उसका स्मरण जीवन को सुखद बनाता है।

हरीश बड़थ्वाल

https://t.me/Civil_Services_Examination_Preparation_Material_Free_Paid1

सौर तूफानों से उपग्रहों को बढ़ता खतरा

मुकुल व्यास

> सौर घटनाएं समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही हैं, जो आज टेक्नोलाजी पर अत्यधिक निर्भर है

भविष्य में आने वाले सौर तूफान उपग्रहों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। विज्ञानियों ने यह पता लगाया है कि जैसे-जैसे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड का स्तर बढ़ता जाएगा, सौर तूफानों के पृथ्वी से संपर्क करने का तरीका भी बदल जाएगा। एक नए अध्ययन के अनुसार, भविष्य में भू-चुंबकीय तूफान ठंडे और कम सघन वायुमंडल में आएंगे। यह परिवर्तन उपग्रहों पर वायुमंडल के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे जीपीएस और संचार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं। हाल के दशकों में, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारी निर्भरता उन्नत नेविगेशन प्रणालियों, आनलाइन डाटा ट्रांसमिशन, राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों और उपग्रह संचालन पर बढ़ती जा रही है।

अमेरिका के राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए इस नए शोध में यह पाया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड का बढ़ता स्तर भू-चुंबकीय तूफानों के प्रभाव को बदल देगा। यह खोज पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले हजारों उपग्रहों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भू-चुंबकीय तूफान तब आते हैं जब सूर्य से आवेशित कणों का विस्फोट पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। ये सौर घटनाएं आधुनिक समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही हैं, जो आज टेक्नोलाजी पर अत्यधिक निर्भर है। भू-चुंबकीय तूफान अस्थायी रूप से ऊपरी वायुमंडल को सघन बन देते हैं, जिससे उपग्रहों पर वायुमंडल के खिंचाव में वृद्धि होती है। इसका प्रभाव उनकी गति, कक्षीय ऊंचाई और जीवनकाल पर पड़ता है। भविष्य के तूफानों के दौरान ऊपरी वायुमंडल उतना सघन नहीं होगा जितना आज समान तीव्रता वाले तूफानों के दौरान होता है। इससे भविष्य में उपग्रहों को विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा निचला वायुमंडल कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन से गर्म होता है, जबकि ऊपरी वायुमंडल ठंडा हो जाता है। इसका संबंध कार्बन डाईआक्साइड के विभिन्न प्रभावों से है। पृथ्वी की सतह के पास घनी हवा में अणुओं में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करने के बजाय कार्बन डाईआक्साइड अंतरिक्ष में उच्च ऊंचाई पर ऊष्मा पुनः उत्सर्जित करती है, जहां हवा बहुत पतली होती है।

शोधकर्ताओं ने पिछले साल 10-11 मई को आए भू-चुंबकीय तूफान पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को झकझोर दिया था। इस सदी के अंत में ऊपरी वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्र पिछले साल आए तूफान की तुलना में कम घने होंगे। अंतरिक्ष के मौसम में होने वाले परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भू-चुंबकीय तूफानों का अध्ययन शामिल है।

(लेखक विज्ञान का जानकार हैं)

श्रेय लेने की होड़

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का भले ही सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले किस दल ने की, इसका श्रेय लेने को लेकर उनमें होड़ मची है। हाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग के तीखे पलटवार के बाद एक मंच पर एकजुट हुए विपक्षी दलों के बीच इसका श्रेय लेने की यह लड़ाई साफ दिखी। स्थिति यह थी कि सपा नेता रामगोपाल के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मतदाता सूची की गड़बड़ियों को सबसे पहले उठाने का श्रेय अपने नेता अखिलेश यादव को दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की बारी आई तो उन्होंने अपनी नेता ममता बनर्जी को इसे सबसे पहले उठाने का श्रेय दिया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की बारी आई तो उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी को इसे पहले उठाने का श्रेय दिया। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष में शामिल और कौन-सा दल इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने का श्रेय लेने दिखता है।

डांसिंग अर्थविद

वैसे तो वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अभी पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल कई बार अर्थनीति पर अपने सोच एवं पुस्तकों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी नृत्य कला को लेकर है। हुआ यह कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ब्रेक के दौरान जब भारतीय परंपरागत डांस हो रहा था तब कुछ नर्तकों ने उन्हें घेर लिया। घेरा तो अन्य वक्ताओं को भी गया था, लेकिन वे निकल गए, पर सान्याल ने नर्तकों के साथ ताल में ताल मिला दिया। वहां पर लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ ही घंटे में देश के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार का डांस वायरल हो गया, बाद में उन्होंने सफाई भी दी। वैसे अपने मित्रजनों में उनकी पहचान एक अच्छे डांसर की पहले से ही है। कुछ लोगों ने टिप्पणी भी की कि संजीव सान्याल की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन डांस पर नहीं।

तारीफ या तंज

अपनी धरती पर गर्व सभी करते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि वह गर्व कब, कहां और किस परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया गया है। हाल में जब राज्यसभा में आइआइएम, गुवाहाटी से संबंधित विधेयक पर चर्चा चल रही थी, तब गुजरात के भाजपा सांसद रामभाई हरजीभाई मोकरिया ने भी विचार रखे। सरकार के कामकाज की तारीफ करने पर तालियां बजीं, लेकिन अचानक वह बोल पड़े- 'जैसे गुजरात देश का मार्गदर्शन करता है, वैसे ही आइआइएम, अहमदाबाद भी आइआइएम, गुवाहाटी का मार्गदर्शन करेगा।' उस समय विपक्ष तो सदन से वाकआउट कर चुका था, लेकिन शायद सत्तापक्ष के ही अन्य राज्यों के सांसदों को मोकरिया की बातों में गर्व से अधिक अभिमान महसूस हुआ। रोकटोक या सीधी टिप्पणी 'अनुशासनहीनता' मानी जा सकती थी, इसलिए पीछे बैठे सदस्यों की प्रतिक्रिया थी- 'क्या बात है... क्या बात है...!' संभवतः सांसद मोकरिया को समझते देर न लगी कि इस तारीफ में कहीं न कहीं तंज है। तभी भाषण रोककर, पीछे मुड़कर प्रतिक्रिया दी- 'हां, यह सही बात है।'

समय की नजाकत

बिहार विधानसभा चुनाव में खेमा स्पष्ट बंटा हुआ है, पर लोजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लगातार ऐसे बयान आ रहे थे जिससे लग रहा था कि उनका खेमा स्पष्ट नहीं है। बिहार में अपनी ही सरकार पर अंगुली उठा वह यह संदेश देना चाहते थे कि निष्पक्ष हैं। अपना ग्राफ बढ़ाने का यह तरीका उन्हें अच्छा लग रहा था, पर बताते हैं कि उन्हें संदेश दे दिया गया है कि समय की नजाकत को पहचानें। दो नाव पर पांव रखना खतरनाक है। उसके बाद से ही वह थोड़े संयमित हो गए हैं।

राजरंग

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****